हरियाणा विधान सभा की

कार्यवाही

23 जनवरी, 1976

खण्ड 1 अंक 10

अधिकृत विवरण

विषय–सुची

शुक्रवार, 23 जनवरी, 1970

पृष्ठ

संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

(10) 1

तारांकित प्रश्नों कें लिखित उत्तर

(10) 28

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर (10)

39

कार्य–मन्त्रणा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

(10) 49

हरियाणा विनियोग विधेयक, 1976

(10) 51

वर्ष 1975–76 के अनुपूरक अनुमानों (दूसरी किश्त)

पर चर्चा तथा मतदान (10)

80

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 23 जनवरी, 1976

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1 चण्डीगढ में प्रातः 9.30 बजे हुई ।

अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Question Hour.

तरांकित प्रश्न संख्या 1444

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी दल सिंह, सदन में उपस्थित नही थे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1415

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी राम लाल वधवा, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

MANDIS

***1535. Shri Om Parkash Garg :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) the total number of `Mandis' set up by the Haryana State Agricultural Marketing Board since its constitution todate together with the locations thereof; and

(b) the total number of Mandis together with the names of places where such Mandis are proposed to be set up in the State ?

Agriculture Minister (Col. Maha Singh) :

(a) (i) 14.

(ii) Ladwa, Sohna, Sadhaura. Naneola, Radaur, Behal, Shahzadpur, Farrukhn agar, Bilaspur, Jundla, Dhand, Jui, Balsmand and Kharkhauda.

(b) (i) 17.

(ii) Kalka, Medlauda, Gharaunda, Rohtak, Khizrabad, Khojkipur, Nissing, Jhansa, Pipli, Sewan, Arnauli, Hassanpur, Fetehpur, Biloch, Kalanaur, NangalChaudhari, Aher and Bass.

श्री गौरी शंकर : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि दाताराम सिंह में मंडी बनाने की क्या पोजीशन है?

कर्नल महा सिंह : अध्यक्ष महोदय, नई मंडियां बनाने के लिए उनकी वायाबिलिटी एग्जामिन करके फिर नई मंडियां बनाई जाएंगी ।

चौधरी शिव राम वर्मा : एक मंत्री अमीन गांव ने बनाने की तजवीज थी । क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या

वहां जमीन ऐक्वायर कर ली गई है और वह मंडी कब तक बन जाएगी '

कर्नल महा सिंहः अध्यक्ष महोदय, अमीन गांव में एक मंडी सैटअप होगी और उसका काम कालोनाइजेलन डिपार्टमेंट ने टेक–अप कर रखा है ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह पीपली में जो मंडी बनाने जा पे हैं यह कौन सी पीपली है? एक तो हमारे रास्ते में पड़ती है और एक दूसरी पीपली है ।

कर्नल महा सिंह : यह वही पीपली है जो आपके रास्ते में आती है ।

Shri Gulab Singh Jain : Whether the Government would consider the desirability of entrusting the setting up of Mandis in the State, in future, to the Agricultural Board rather than to the Colonization Department?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सरकार के विचारा– धनि है कि आइन्दा मंडियां बनाने का काम मार्किटिंग बोर्ड के सुपुर्द किया जाए क्योंकि मंडियां बनाने के पश्चात् मेनटेनेन्स का काम बोर्ड को ही करना पड़ता है । अतरू यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

राव बन्सी सिंह : क्या मत्री महोदय बताने की कृपा करें गे कि नांगल चौधरी में जो मंडी सैट–अप होने जा रही है उसकी क्या पोजीशन है? क्या वहां पर जमीन ऐक्वायर कर ली गई है?

कर्नल महा सिह : अध्यक्ष महोदय, नांगल चौधरी में जमीन एक्वायर की जा रही है और वहां पर मडी बन जाएगी । '

चौधरी पीर चन्द : अध्यक्ष महोदय, हिसार की मंडी बनकर तैयार ही गई है लेकिन वहां पर बोली नहीं हुई है । एक बार बोली लगी थी लेकिन फिर पुरानी मंडी में ही बोली लगने लगी । क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है?

कर्नल महा सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए अलग से नोटिस की जरूरत है । हिसार की मंडी बन गई है और उसको कालोनाईजेशन डिपार्टमैंट ने ले लिया है ।

श्री राम जी नाम डागर : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे 'कि, हथीन में नोटीफाइड एरिया कमेटी बनाने का विचार है?

कर्नल महा सिंह : अध्यक्ष महोदय,नोटीफाइड एरिया कमेटी के बारे में लोकल सैल्फ सवर्नमेंट के मत्री बता सकेंगे ।

चौधरी मंशा रामः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मदलोड दें मत्री कब तक तैयार हो जायेगी?

कर्नल महा सिंह : मदलोड की मंडी का केस टेक–अप किया हुआ है और कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी बनाई जाए ।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने नई मंडियों के नाम गिनवाए हैं । क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इनमें बराडा का नाम क्यों नहीं आया?

कर्नल महा सिंह : अध्यक्ष महोदय सवाल यह था कि मार्किटिंग बोर्ड ने कौन. सी मंडियां बनानी हैं । बराडा का नाम जरूर है और वह कालोनाईजेशन डिपार्टमैट की लिस्ट में है ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन्होंने जो मंडियों के नाम लिए हैं इनमें कौन सी अन्डर कंस्ट्रक्शन हैं, कौन सी बन गई हैं और कौन सी शुरू होने वाली हैं?

कर्नल महा सिह : अध्यक्ष महोदय, जो इनका सवाल था वह यह था कि जब से मार्किटिंग बोर्ड बना है तब से इसने कितनी मंडियां बनाई हैं और मैंने इस बारे में इनसे पूछ भी लिया था । 14 मंडियां जो हैं उनका काम मार्किटिंग बोर्ड का आलरेडी करीब–करीब कम्पलीट होने वाला है और इसी तरह से मैंने इनका नाम बताया है । मंडियों में सब–यार्ड भी आते हैं ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मंत्री महोदय बताने की कृ पा करेंगे अमीन मंडी के लिए दफा 4 का नोटिफिकेशन भी हो

गया है लेकिन उससे अगली कार्यवाही का पता नहीं है कि क्या स्थिति है और कब तक काम शुरू होने वाला है?

श्री अध्यक्ष : मंडियां दो डिपार्टमैंट्स के अन्डर हैं एक कालोनाइजेशन डिपार्टमैंट और दूसरा मार्किटिंग बोर्ड । आपको यह रैफर करना पड़ेगा कि किसके बारे में पूछ रहे हैं ।

चौधरी राम प्रशाद : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुंड में मंडी बनाने का विचार है और अगर है तो उसकी क्या स्थिति है?

कर्नल महा सिंह : अध्यक्ष महोदय, कालोनाइजेशन डिपार्टमैंट वहां पर लैड ऐक्वायर कर रहा है ।

श्री के ० एन ० गुलाटी : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि फरीदाबाद ब्लाक के लिए फरीदाबाद के अन्दर कहां और कब मंडी बनाने का विचार है?

कर्नल महा सिंह : अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद के अन्दर आलरेडी मंडी है और उसका सब–यार्ड भी है और फरीदाबाद न्यू टाउनशिप और ओल्ड टाउनशिप में भी मंडी हैं ।

चौधरी प्रभु राम : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि छोटे काश्तकारों की जो जमीन मंडी के लिए ऐक्वायर करते हैं उनको उस जमीन की कीमत किस हिसाब से देखे हैं?

कर्नल महा सिंहः अध्यक्ष महोदय, जमीन की कीमत चाहे छोटा काश्तकार हो या बड़ा काश्तकार हो जैसी वहां पर जमीन की कीमत हो उसके मुताबिक कीमत देते हैं ।

Pannuwala Water Supply

***1562. ShriJagjit Singh Tikka :**Will the Minister for Local government be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that one tube-well is not sufficient to supply drinking water to all the villages included in Pannuwala Water Supply Scheme in tehsil Naraingarh; and

(b) if so,the steps proposed to be taken by the Government to supply enough quantity of drinking water to all the villages included in the aforesaid scheme ?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी):

(क) हां ।

(ख) अतिरिक्त नलकूप का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि यह काम काफी देर से शुरू हुआ है तो यह काम कब तक पूरा हो जाएगा?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, काम बहुत दिनों से तो शुरू नहीं हुआ है कुछ पैसे की कमी पड़ गई थी जो इसी साल में मन्जूर हुआ है यह काम मार्च, 1976 में पूरा हो जाने की उम्मीद है ।

Statue of Nawab of Jhajjar

***1582. ChaudhriPhul Singh Kataria :** Will the Chief Minister b pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to instal a statue of Nawab of Jhajjar; if so, the date on which the statue is likely to be installed?

मलिक सतराम दास बतरा : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि रिवाडी के नवाब का कोई स्टेचू बनाया जाएगा?

श्री बनारसी दास गुप्त : रिवाडी में तो कोई नवाब नहीं हुआ है ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : स्पीकर साहब मन्त्री जी ने अपने जवाब में कहा है ' न ओं लेकिन नवाब झझर की कुर्बानियों को देखते हुए । उनकी बातों को देखते हुए, उनके नाम से कोई सड़क या कोई और मैमोरियल बनाने का सरकार का विचार है?

श्री बनारसी दास गुप्त:अध्यक्ष महोदय, स्वाधीनता की जब 25 वीं वर्षगांठ मनाई गई तब हरियाणा सरकार ने यह निश्चय किया था कि जितने शहीद हरियाणा प्रदेश में हुए हैं, चाहे वे

1857 के स्वाधीनता संघर्ष में या उसके बाद में हुए हैं, उन सब का एक बहुत शानदार स्मारक रोहतक के पास बौहर गांव में बनाया जाए । इसके लिये जमीन भी ऐक्वायर की जा चु की हए और हमारा चीफ आरकीटैक्ट इसके लिये डिजाइन तैयार कर रहा है, वहां सब शहीदों का स्मारक होगा, उन का नाम होगा और उसी में नवाब झज्जर का भी स्मारक बनाया जायेगा।

Milk Plants in the State

***1571. ShriDhaja Ram** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the number of milk plants in the State together with their locations and the dates from which these started functioning;

(b) the year-wise income accrued to each such plant, separately, from the date each of them started functioning to date;

(c) the total manufacturing capacity of each milk plant in the State; and

(d) whether each such milk plant is getting the full milk supply according to its capacity and, if not, how the same is proposed to be covered up ?

Finance Minister (Shri Ram Saran Chand Mittal)

(a)

(b)

(c) A statement is laid on the table of the House,

(d)

STATEMENT

(a) Three Milk Plants have been set up and commissioned so far. The one at Jind was commissioned on December 5, 1970, that at Bhiwani on October 28, 1972, and that at Ambala on August 29, 1973. The fourth one at Rohtakis nearing completion and expected to be commissioned any time during the current financial year .

(b) The year-wise turn-over of each Milk Plant is as follows;

Name of Plant	Upto 31-1-71	1-2-71 to 31-3-72	1-4-72 to 31-3-73	1-4-73 to 31-3-74
		(Rupees in Lacs)		
Jind	13.08	120.17	195.70	205 . 31
Bhiwani	—	—	1.05	45.12
Ambala	—	—		16 . 77
Total	13.08	120.17	196.75	267.20

The annual turn-over for the years 197475 and 1975-76 will be known after the accounts for these years are finalised.

(c) The Plant at Jind can process 50,000 litres of milk a day, the one al Bhiwani15,000 litres a day and the one at Ambala20,000 litres a day The PlantatRohtak will have a capacity of one lac litres a day.

(d) Each Plant is getting the quantity of milk it can sell after processing anc conversion into products.

Prices of Agricultural Inputs

***1577. ChaudhriMeharChand :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the prices of the following agricultural input the year 1973 and in December, 1975 :—

Agriculture Input

1 .	Kisan Khad per bag of 50 Kg.	In the year 1973	In December, 1975
2 .	Uria per bag of 50 Kg.	—do--	—do-
3 .	D.A.P.	—do--	—do—

Minister for Agriculture (Col. Maha Singh) : Sir, a statement is laid on the table of the House. -

Statement

The prices of fertilisers in the year 1973 and in December, 1975, were as under :—

Sr.	Name of fertiliser	No.--	In December,

		In the year 1973		1975
		17-3-72 to 9-10-73	10-10-73 to 31-12-73	
		Rs.	Rs.	Rs.
1.	Kisan Khad per bag of 50 Kg	28.25	30.90	50.90
2.	Urea per bag of 50 Kg.			
	(i) Pool	47.95	52.50	92.50
	(ii) Indigenous	47.95	52.50	96.00
3.	D.A.P. per bag of 50 Kg.	62.30	66.75	130.00

चौधरी मेहर चन्द : स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि जिन जरायत के लिये इतना महंगा खाद इस्तेमाल किया जाता है, क्या उनकी स्पोर्ट प्राइस फिकस करने का सरकार सोचेगी, विचार करेगी?

कर्नल महा सिंह : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ऐसे हर मामले में प्राइम फिक्स करती है । अगर अभी भी गेहूं की स्पोर्ट प्राइस 105 रुपये फिक्स होती तो हमारी स्टेट में बहुत सी जगहों

पर 105 रुपये प्रति क्विंटल से गिर जाती । यू ० पी० में और खास तौर पर वैस्टर्न यू ० पी० में भाव गिर गया । फिर भी मैं बता देता हू किं गवर्नमेंट हर जगह पर किसान की मदद के लिये स्पोर्ट प्राइस फिक्स करती है ।

चोधरी मेहर चन्द : स्पीकर साहब, या तो मिनिस्टर साहब के इलाके में गवार होती ही नहीं, बाजरा तो होता होगा, वहां प्राइसिज की क्या हालत है और इसके इलावा मैं यह पूछना चाहता हूं कि कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ गई है और कीमत गिर गई हैं तो इसके लिये किसान को रिलीफ देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

Mr. Speaker : Order Please रिलीफ देने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है is not a supplementary to this question यह तो खाद का सवाल है ।

चौधरी मेहर चन्द : स्पीकर साहब, खाद की कीमतों में बढ़ौतरी होने से ही कीमतों में बढ़ौतरी हुई एं ।

श्री अध्यक्ष : तो आप खाद के मुताल्लिक पूछिये कि सरकार खाद के मुताल्लिक क्या रिलीफ दे रही हे?

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, इंटरनैशनल मार्किट में यूरिया और दूसरी खादों की कीमतें काफी गिर गई हैं, यूरिपियन कंट्रीज में और इस्टर्न कंट्रीज में और अमेरिका जैसे मुल्कों में आप देखिये कि वहां पर 74 में जो खाद की कीमतें थीं

आज आधी से भी कम हो गई हैं तो इस चीज के पेशेनजर क्या मिनिस्टर साहब यह बता सकते हैं कि हिन्दुस्तान में कारसपांडिंगली फर्टीलाइजर की कीमतों में कमी क्यों नहीं हुई है?

कर्नल महा सिंह : अध्यक्ष महोदय, विदेशों का तो मुझे इलम नहीं लेकिन भारत सरकार ने पिछले साल भी 200 करोड़ की सब–सिडी पूल में फर्टीलाइजर के लिये दी है ताकि फर्टीलाइजर की कीमतें कम हो और साथ ही साथ राइस पर भी बोनस दिया गया है जिस पर करीब–करीब 10 परसैन्ट सब–सिडी दी गई है । फर्टीलाइजर की कीमतें कुछ घटा दी हैं ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि बोने के वक्त पर डीं० ए ० पी ० और सुपर–फासफेट पर सरकार ने सब–सिडी दी है? अगर दी हैतो कितनी कितनी दी है?

कर्नल महा सिंह : जी हां, 5 परसैन्ट सब–सिडी दी है ।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि जिस वक्त मई 74 में फर्टीलाइजर की कीमतें बढ़ों तो जो स्टाक्स आपके पास, मारकीटिंग फैडरेशन के पास या डिपोज पर था, क्या उस स्टाक को भी नये रेट से बेचा गया और उससे सरकार को कितना फायदा हुआ?

कर्नल महा सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर किसी व्यापारी के पास माल होता है तो जब कभी कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसको

फायदा होता है, जब कभी कीमतें घट जाती हैं तो फैडरेशन को उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है । अगर आनरेबल मैम्बर को आंकड़े चाहियें तो इसके लिये वह अलग से नोटिस दें ।

राव बंसी सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जिस प्रकार यूरिया वगैरह पर कन्सैशन दिया गया है उसी तरह से जो रेतीले इलाके, जैसे कि महेन्द्रगढ़ का इलाका है, वहां पर किसान यही खाद इस्तेमाल करता है, वहां पर कोई कन्सैशन देने का सरकार का विचार है?

कर्नल महा सिंह : अध्यक्ष महोदय यह देखा गया है कि किसान एक ही किस्म की खाद इस्तेमाल करते थे लेकिन हमारे प्रान्त में और दूसरे प्रान्त में जहां उत्पादन और तेजी से बढ़ा है, वह यह सारी खाद का परपोर्शन से इमाल करते हैं तो किसी को ज्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिये, ऐनकरेज करने के लिये कि किसान उत्पादन बढ़ाने के लिये सब किस्म का खाद इस्तेमाल करे, इसलिये यह सब–सिडी उनको दी गई है जिनको किसान कम ले रहे थे और दूसरा इसका इस्तेमाल करने से उत्पादन बढ़ सकता है । वह इरीगेटिड एरिया के अन्दर ही इस्तेमाल किया जा सकता है । महेन्द्रगढ़ में जब जवाहर लाल नेहरू कैनाल आ जाएगी तो वहां पर भी इस का इस्तेमाल किया जाएगा ।

चौधरी. रिजक राम : अध्यक्ष महोदय, अभी अभी मिनिस्टर साहब ने कन्सैशन का फरमाया है । वह कन्सैशन

डिस्ट्रीब्यूशन सैन्टर्ज के लिये सरकार ने मन्जूर किया है और फार्मर्ज को जो किमतें देनी पड़ती हैं उस में कोई कमी नहीं हुई है बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन –(विघ्न)

Mr. Speaker : Order please. You are supplying information.

ChaudhriRizaqRam : No, Sir. I am asking a supplementary question.

Mr. Speaker : Please put a supplementary question.

चौधरी रिजक राम : तो अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा था कि डिस्ट्रीब्यून सैन्टर्ज के कमिशन के रेट्स जो सरकार ने बढ़ाये हैं, उसके लिये जो सब–सिडी बढ़ाई है, क्या यह ठीक है?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, यह जो रियायत दी गई है यह किसान को दी गई है । अगर ये पूछना चाहते हैं तो मैं अलग अलग प्रकार की खाद की फिगर्ज भी दे सकता हूं । एक खाद है फासफेट, उसकी कीमत है 2205 रुपये पर–टन, 520 रुपये हम उसमें रियायत देते हैं, अथवा सब–सिडी देते हैं और उस की सेल प्राइस है 1685 रुपये और दूसरी जो सुपर फासफेट खाद है वह है 1072 रुपये पर–टन, उस पर 268 रुपये प्रति टन रियायत दी है, इसलिये इसकी सेल प्राइस 804 रुपये है और एम० पी० के0 की कीमत है 1900 रुपये, उस पर 287 रुपये पर–टन सब–सिडी देते हैं अतरू उसकी सेल प्राइस है 1613 रुपये ।

श्री हरि सिंहः अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि सरकार खाद किस कीमत पर खरीदती है? जब मैनुफैक्चर करते हैं तो इसकी क्या कास्ट पड़ती है?

कर्नल महा सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री महोदय ने यही बताया है जी ।

श्री ओमप्रकाश गर्ग : अध्यक्ष महोदय, मेरे नोटिस में यह बात है कि सब–सिद्धी 10 परसैन्ट की बजाए 25 परसैन्ट दी है, मिनिस्टर साहब चौक कर लें ।

कर्नल महा सिंहः अध्यक्ष महोदय यह ठीक कह रहे हैं । सब–सिडी 25 परसैन्ट है । यह मेरी गल्ती थी, मैं क्षमा चाहता हूं ।

B.A. B.Eds. and J.B.Ts. Registered with the Employment Exchanges

***1585. RaoDalipSingh :**Will the Minisier for Transport be pleased to state—

(a) the district-wise total number of persons with the qualifications of B.A. B.Eds. and J.B.Ts. registered with the Employment Exchanges in the State as at present; and

(b) the steps being taken by the Government for the employment to the persons as referred to in part (a) above ?

Transport Minister (Shri K. L. Poswal) : A

statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

(a) Information regarding district-wise total number of persons with the qualifications of B.A. B.Ed./B.T. and J.B.T. registered with the Employment Exchanges as on 31-12-1975 is given below :—

Name of District	Total number of persons with B.A. B. Eds./B . Ts . as qualification	Total number of persons with J.B.T. as qualification
Rohtak	890	1541
Ambala	757	816
Bhiwani	431	133
Gurgaon	1112	1065
Hissar	563	626
Jind	382	398
Kamal	458	647
Mohindergarh	582	50
Sirsa	163	207
Sonepat	403	784
Kurukshetra	423	334

Total : 6164 6901

(b) The matter is under consideration of Education Department.

राव बंसी सिंह : क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि बी० एड० और जे० बी० टी० के जिन लोगों के नाम एम्पलायमेंट हेतु दर्ज किये गये हैं, वे कितने हैं और इन मैं से कितने ऐसे हैं जिनका नाम एम्पलायमेंट एक्सचेंज में दर्ज हुए दो साल से अधिक हो गये हैं?

श्री के० एल० पोसवाल : इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज सिर्फ फिगर्ज मांगी हैं, दूसरी बात के। लिये आनरेबल मैम्बर सैपरेट नोटिस दें तो हम बता देंगे ।

राव दलीप सिंह : जैसे कि मन्त्री महोदय ने जयने उत्तर में बताया है कि स्टेट में बीं० ए० बी० एड० बी० टी० की क्वालिफिकेशन वाले कुल 6164 आदमी हैं और जे ० बी० टी ० वाले 6901 हैं । इसका मतलब यह है कि लगभग 12 हजार ऐसे पढ़े लिखे ट्रेड लोग हैं जो तीन–तीन चार–चार सालों से अन–एम्प्लायड हैं, क्या इन की समस्या को हल करने के लिये सरकार कोई कदम शीघ्र उठाने का विचार रखती है?

शिक्षा मंत्री (श्री माडु सिंह मलिक) : स्पीकर साहब, 2280 बी ० एड० टीचर्ज एड–हाक बेसिज पर काम कर रहे हैं और 7344 जे ० बी ० टी टीचर्ज एड–हाक बेसिज पर काम कर रहे हैं

। कल यहां हाउस के अन्दर एक माननीय सदस्य ने जो बहुत पुराने पार्लिया मेन्टेरियन हैं, कहा कि एस0 एस0 बोर्ड ने इन्हें 10 हजार आदमियों की सूची भेजी है । तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमने तो सिर्फ तीन हजार पोस्टें मांगी थीं । दस हजार ने इम्तहान दिया था और अभी उनकी इन्टरव्यू होनी है । दस हजार का पता नहीं इनको कहां से सपना आ गया । हमने एस० एस० एस० बोर्ड को लिखा है कि हमें सिलैक्ट हुए टीचर्ज की लिस्ट जल्दी भेजें । बाकी जो एड–हाक बेसिज पर लगे हुए हैं तीन हजार की लिस्ट आने के बाद उनको रेगुलराईज करेंगें ।

चौधरी रिजक राम : मिनिस्टर साहब ने क्वैश्चन का जवाब तो दिया नहीं है बल्कि वैसे ही फालतू बात की है तो मैं एक्सपलेनेशन के तौर पर कहना चाहता हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं

Mr. Speaker : This is not the time for such an explanation.

तारांकित प्रश्न संख्या 1445

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी दल सिंह, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1416

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी राम लाल वधवा, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Whole-time and Part-time Administrative Officers

***1536. Shri Om ParkashGarg :**Will the Minister for Local Government be pleased to state—

(a) the names of the Municipal Committees and Notified Area Committees in the State where the whole-time and part-time Administrative Officers are working as at present;

(b) the time by which the Administrative Officers are likely to be appointed in the remaining Municipal Committees and Notified Area Committees; and

(c) the time by which whole-time Administrative Officers will be appointed in all the Committees of State ?

State Minister for Development and Local Government (ChaudhriGordhanDassChauhan) :

(a) There are no Administrative Officers in the Municipal Committees and Notified Area Committees, but they are called

Administrators and Presidents, respectively. A statement
showing the names of the Municipalities and Notified Area Committees in the State where the whole-time and part-time Administrators and Presidents are working **at** present is laid on the table of the House.

(b) As would be clear from the statement laid on the table of the House, whole-time or part-time Administrators/Presidents are already working in all the

Municipalities/Notified Area Committees, except Notified Area Committee, Railway Workshop Jagadhri about which case is under consideration of the Government.

(c) As and when it is considered necessary and expedient in public interest and the financial position of the Committee permits the Government would make necessary arrangement for the appointment of whole-time Administrators/Presidents.

Statement

I. (i) Names of the Class-I Municipalities in which whole-time Administrators are working at present.

Sr. No	Name of the Municipality
1	Hissar
2	Bhiwani
3	Gurgaon
4	Rohtak
5	Ambala City

(ii) Names of the Class-I Municipalities in which part-time Administrators are working at present.

1	Yamunanagar
2	Karnal
3	Panipat

4 Sirsa

5 Jind

6 Sonepat

7 Thanesar

II. (i) Names of the Class-II Municipalities in which whole-time Administrators are working at present.

1 Shahbad

2 Palwal

3 Fatehbad

4 Mandi Dabwali

5 Rewari

(ii) Names of the Class-II Municipalities in which part-time Administrators are working at present.

1 Jagadhri

2 Narwana

3 Gohana

4 Pehowa

5 Jhajjar

6 Bahadurgarh

7 Hansi

8	Narnaul
9	Kaithal
10	Kalka
11	Charkhi Dadri

III. (i) Names of the Notified Area Committees in which whole-time Presidents are working at present.

1	Tosham
2	Siwani
3	Kalanaur
4	Ellenabad
5	Bhawani Khera
6	Hassanpur

(ii) Names of the Notified Area Committees in which part-time Presidents are working at present.

1	Ferozepur Zhirka
2	Safidon
3	Beri
4	Tohana
5	Hodal

6	Jakhal
7	Uklana Mandi
8	Kalanwali
9	Loharu
10	Gharaunda
11	Chhachhrauli
12	Buria
13	Sadhaura
14	Sohna
15	Farrukhnagar
16	Hailey Mandi
17	pataudi
18	Nuh
19	Uchana
20	Meham
21	Mahendergarh
22	Ateli
23	Kanina
24	Radaur

25	Pundri
26	Julana
27	Bawal
28	Ladwa
29	Nilokheri
30	Naraingarh
31	Ganaur
32	Maheshnagar
33	Pinjore
34	Narnaund
35	Sampla
36	Rania
37	Kunjpura
38	Indri
39	Rattia

Government Schools in Ambala District

***1563. ShriJagjit Singh Tikka :**Will the Minister for -Education be pleased to state—

(a) the Tehsil-wise total number of buildings of

Government Primary, Middle, High and Higher Secondary Schools which have not been handed over by the Education Department to P. W.D . (B&R) for maintenance purpose in Ambala District;

(b) the Tehsil-wise names of School buildings which have been handed over by the Education Department to P.W.D. (B&R) since 1.4.1974 to date in Ambala District together with the name of the Department which is responsible for the repair of the buildings which have not been handed over to P.W.D. (B&R) so far;

(c) the time by which all the Schools in Ambala District will be handed over by the Education Department to P.W.D. (B&R); and

(d) the total amount spent by the Education Department Tehsilwise and School-wise on the repairs of School buildings in Ambala District during the years 1974-75 and 1975-76 to date?

शिक्षा तथा परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) :

(क) विवरण पत्र विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत है ।

(ख) विवरण पत्र विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत है ।

(ग) इसके लिये कोई तिथि निश्चित नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसा करने से पहले कई औपचारिकतायें पूरी करनी होती हैं ।

(घ) विवरण पत्र विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत है ।

स्टेटमैन्ट

(ए) तहसील	प्राईमरी स्कूल	मिडिल स्कूल	हाई स्कूल	हायर सैकन्डरी स्कूल	जोड़
कालका	46	2	4	—	52
अम्बाला	239	20	15	—	264
नारायणगढ	169	21	11	—	201
जगाधरी	232	2	3	—	237
जोड़ :	676	45	33	—	754

(बी) तहसील	1—4—74 तथा उसके बाद लोक निर्माण विभाग की पुस्तक पर लाये गये स्कूलों की संख्या ।	स्कूल का नाम
कालका	शून्य	शून्य

अम्बाला	शून्य	शून्य
नारायणगढ	श्न्य	शून्य
जगाधरी	1	राजकीय उच्च विद्यालय खारवाना (जगाधरी)

जो भवन लोक निर्माण विभाग को समर्पित नहीं किये गये हैं उनकी मुरम्मत आम तौर पर ग्राम पंचायत और शिक्षा विभाग करते हैं ।

(डी) वर्ष 1974—7 5 के दौरान खर्च की राशि

तहसीलें	मुरम्मत	निर्माण	जोड़
कालका	शून्य	शून्य	शून्य
अम्बाला	5881.24	107067.76	112949.00
नारायणगढ	6288.00	20500.00	26788.00
जगाधरी	36106.00	52200.00	88306.00
जोड़	48275.00	179767.00	228043.00

वर्ष 1975—76 के दौरान खर्च की गई राशि

तहसीलें	मुरम्मत	निर्माण	जोड़

कालका	7420		7420
अम्बाला	4450	20105	24555
नारायणगढ	शून्य	61830	61830
जगाधरी	4460	195152	199612
जोड़	16330	277087	293417

वर्ष 1974–75 में तहसील अम्बाला के विद्यालय के भवनों पर मुरम्मता/निमार्ण कार्य पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा

क्रमांक	विद्यालय का नाम	भवन की मुरम्मत पर किया गया खर्च का ब्यौरा	निर्माण कार्य पर किया गया खर्च का ब्यौरा
1	राः माः विः राजोखेडी	139.80	--
2	राः प्राः पाः सालरहेडी	477.94	--
3	राः प्राः पाः दबियाना	500.00	--
4	राः प्राः पाः मछौन्डा	188.00	--
5	राः प्राः पाः खडा खुर्द	815.00	--
6	राः प्राः पाः करधान	1,500.00	

7	रा: मा: वि: मेंहसा देहरा	--	8,000.00
8	रा: पा: पा: ठाकरपुर	––	5,000.00
9	रा: पा: पा: बबियाल	-	7,000.00
10	रा: उ: वि: बलाना	-	2,200.00
11	रा: उ: वि: पन्तोखरा	-	12,000.00
12	रा: प्रा: पा: धुरखडा	-	6,000. 00
13	रा: प्रा: पा: सोहनपुर	-	2,000. 00
14	रा: उ: मा: वि: केसरी	--	10,000. 00
15	रा: प्रा: पा: कालका माजरा	-	4,000. 00
16	रा: मा: वि: जलबेडा	-	4,000. 00
17	रा: प्रा: पा: मुजफरा	1,000. 00	-
18	रा: प्रा: पा: अकबरपुर	-	4,000. 00
19	रा: मा: वि: सुलतानपुर	-	4,000. 00
20	रा: उ: वि: पंजोखरा	-	10,000. 00
21	रा: उ: मा: वि: अम्बाला	--	3,122. 00

	शहर		
22	रा: उ: वि: साहा	260.00	-
23	रा: प्रा: पा: बबियाल	-	10,378. 76
24	रा: प्रा: पा: रोलन	-	5,000. 00
25	रा: प्रा: पा: सीमला	1,000. 00	-
26	रा: उ: मा: वि: अम्बाला शहर	-	9,190. 00
27	रा: उ: मा: वि: अम्बाला शहर	-	1,177. 00
	कुल:	5,881. 24	1,07,067.76

स्कूल भवनों के निर्माण एवं मुरम्मत हेतु व्यय–तहसील नारायणगढ वर्ष 1974–75

क्रमांक	स्कूल का नाम	मुरम्मत	निर्माण कार्य पर खर्च	विशेष कथन

1	रा: मा: वि: शाहजादपुर	**1,400.00**	--
2	रा: मा: वि: लहारपुर	--	**5,500.00**
3	रा: मा: वि: वहारली	**300.00**	-
4	रा: मा: वि: काठामाजरा	**228.00**	--
5	रा: मा: वि: अकबरपुर	**80.00**	--
6	रा: मा: वि: काकरमाजरा	--	**2,000.00**
7	रा: मा: वि: गाधोली	**400.00**	--
8	रा: मा: विरू कुराली	**430.00**	--
9	रा: क: मा: वि: वरकलां	**150.00**	--
10	रा: उ: वि: सारावान	**500.00**	--
11	रा: उ: वि: खतौली	**400.00**	--
12	रा: उ: वि: रायपुररानी	**500.00**	--
13	रा: उ: वि: रायपुररानी	--	**3,000.00**
14	रा: मा: वि: राएवाली	--	**10,000.00**
15	रा: मा: वि: कोट	**1,100.00**	--

16	रा: उ: वि: बरवाला	**800.00**	--
	कुल :	**6288.00**	**20500.00**

वर्ष 1974– 75 में तहसील जगाधरी के विद्यालयों के भवनों पर मुरम्मता/निर्माणकार्य पर खर्च की गई राशि का व्यौरा ।

क्रमांक	स्कूल का नाम	भवन की मुरम्मत पर किए गए खर्च का ब्यौरा ।	निर्माण कार्य पर किए गए खर्च का ब्यौरा
1	रा: उ: वि: बिलासपुर	1,883.79	—
2	रा: उ: वि: छछरौली	460.74	—
3	रा: उ: वि: दामला	1,727. 24	—
4	रा: उ: वि: हरनौल	18. 00	--
5	रा: उ: वि: कलावड	80. 00	—
6	रा: उ: वि: मुस्तफाबाद	54. 00	--
7	रा: उ: वि: नागल	661.00	—

8	रा: क: उ: वि: बिलासपुर	—	13,200. 00
9	रा: जे: वी: सैन्टर, छछरौली	100. 00	-
10	रा: मा: वि: कुंजल जट्टा	200. 00	-
11	रा: मा: वि: मुगलवाली	310. 00	—
12	रा: मा: वि: पन्सरा	632. 00	—
13	रा: उ: वि: खारवा	—	4,000.00
14	रा: प्रा: पा: नाहनपुर	—	8,000. 00
15	रा: प्रा: पा: ककरोनी	—	3,500. 00
16	रा: पा: पा: हरियावास	—	7,000. 00
17	रा: प्रा: पा: रतनगड़	—	3,500. 00
18	रा: प्रा: पा: पन्जैटों	—	2,500. 00
19	रा: उ: वि: तलकोर	—	2,500. 00
20	रा: प्रा: पा: हमीदों	—	8,000.00
21	रा:क: उ: मा: वि: यमुनानगर	29,979. 73	—

जोड़ :	36,106. 50	52,200. 00

वर्ष 197 5–? 6 में कामका तहसील कालका स्कूल भवनों की मुरम्मत पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा ।

		मुरम्मत	निर्माण कार्य
	रा: उ: वि:		
1	वसीली	7, 42000	शून्य
		7, 42000	

वर्ष 1975 – 78 में तहसील अम्बाला के विद्यालयों के भवनो की मुरम्मत/ निर्माण कार्य पर खर्च की गई राशि का ब्यौर ।

क्रमांक	स्कूल का नाम	मुरम्मत पर खर्च की गई राशि	क्रमांक	स्कूल का नाम	निर्माण कार्य पर खर्च की गई राशि
1	रा: प्रा:पा: बिजलपुर	500.00	1	रा: उ: मा: वि:	2,005.00

			केसरी		
2	रा:प्रा:पा: जवाहर नगर	500.00	रा: प्रा: पा: चडियाला	2	9,000.00
3	रा: पा: पा: रामपुर छप्पर	500.00	रा: प्रा: पा: ठाकुरपुर	3	2,000.00
4	रा: पा: पा: प्रतापगढ़	500.00	रा: वि: पीलखनी	4	900.00
5	रा: प्रा: पा: महमूबपुर	500.00	रा: प्रा: पा: नाजगढ	5	1000.00
6	रा: प्रा: पा: सीमला	500.00	रा: पा: पा: नरसती	6	2,500.00
7	रा: प्रा: पा: गरनाला	500.00	रा: प्रा: पा: छवीयाना	7	1,000.00
8	रा: प्रा: पाभानो खेडी	450.00	रा: पा: पा: कंवाला	8	700.00
9	रा: प्रा: पा: बारा	500.00	रा: प्रा: पा: रामगढ़	9	1 ,000.00
	जोड़ :	4,450.00	जोड़ :		20,105.00

वर्ष 197 5–7 6 में नारायणगढ तहसील में स्कूलों के

भवनों पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा ।

1	राः माः विः शैदपुर	10,000.00	निर्माण
2	–सम– पठेरी	10,000.00	निर्माण
3	राः उः विः मौली	6,000. 00	निर्माण
4	राः प्राः पाः भाककुठा	2,000. 00	निर्माण
5	राः माः विः हमींदपुर	3,900. 00	निर्माण
6	राः माः विः ज्योली	4,000. 00	निर्माण
7	राः प्राः पाः अम्बली	4,000. 00	निर्माण
8	राः पाः पाः हंगोला	4,000. 00	निर्माण
9	राः प्राः पाः बारागोन	2,000. 00	निर्माण

			ा
10	रा: मा: वि: काकरमाजरा	4,000. 00	निर्माण ा
11	रा: मा: वि: अकबरपुर	4,000. 00	निर्माण ा
12	रा: उ: वि: मंधाना	7,930. 00	निर्माण ा
	जोड़ :	61,830. 00	

वर्ष 1975–76 में तहसील जगाधरी के विद्यालय के भवनों की मुरम्मत/निर्माण पर खर्च की गई राशि

क्र.	स्कूल का नाम	मुरम्मत पर खर्च की गई राशि	क्र.	स्कूल का नाम	निर्माण कार्य पर खर्च की गई राशि
1	राजकीय उच्च विद्यालय बिलास पुर	1561.00	1	रा: उरू वि: यमुनानगर	15000.00

2	रा : उ : वि : छछरौली	301.00
3	रा: उ: वि: दामला	60.00
4	रा: उ: वि: हरनीर	12. 00
5	रा: उ: वि: मुस्तफाबाद	100. 00
6	रा: उ: वि: बिलासपुर (कन्या)	1,801. 00
7	रा: उ: वि: जहदर	205.00
8	रा: मा: वि: कजलजटां	220.00
9	रा: मा: वि: मुगलवाली	200.00
	कुल :	4,460. 00

2	रा: उरू वि: सारवान	3000.00
3	रा: उ: वि: मुसीनवाल	10,000. 00
4	रा: उ: वि: महिलावाली	3,658. 00
5	रा: उ: वि: नांगल	15,689.00
6	रा: उ: वि: शाहपुर	1,926. 00
7	रा: उ: वि: लेड़ी	2,361. 00
8	रा: उ: वि: छछरौली (कन्या)	6,334. 00
9	रा: उ: वि: दामला	10,000. 00
10	रा: उ: वि: हरनाल	12,000. 00
11	रा: उ: वि: लेड़ी	5,125. 00
12	रा: मा: वि: यमुनानगर	95,000. 00

13	रा: मा: वि: हैदातपुर	9,259. 00
14	रा: मा: वि: यमुनानगर	5,000. 00
	कुल	1,95,152.00

श्री जगजीत सिंह टिक्का : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे यह इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है इसमें सारे 754 स्कूल ऐसे हैं जोकि एजुकेशन और पी० डबल्यू० डी० वालों ने टेक ओवर नहीं किये । मैंने पिछले सात्र भी सवाल पूछा था जिसमें बताया गया था कि राक स्कूल हैंड ओवर किया गया है तो मैं यह पूछना चाहता है कि बाकी स्कूल कब तक हैंड ओवर किये. जाएगे?

शिक्षा मैत्री (श्री माडु सिंह मलिक) : स्कूलों की बिल्डिंगें पी० डल्यू ० डी० वालों को देने के लिये भी कुछ नार्मज हैं । जब तक बिल्डिंग स्पैसिफिकेशन के मुताबिक न हो जाए तब तक पी० डब्ल्यू ० डी० वाले उसे नहीं लेते ।

श्री गौरी शंकर : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जो स्कूल की बिल्डिंग्ज नार्म के मुताबिक हैं क्या सरकार उनको लेने के लिये तैयार हे?

श्री माडू सिंह मलिक : यह तो पी० डबयू ० डी ० वालों ने देखना है हम तो लेने के लिये तैयार हैं ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि क्या यह बात समझ में आ सकती है कि 754 स्कूलों के लिये सारे साल के अन्दर 48, 275 रुपये उनकी रिपेयर के लिये रखे गये हैं जिसका मतलब है कि एक स्कूल पर तकरीबन 64 रुपये पड़ते हैं जिससे कि सफेदी भी नहीं हो सकता है। तो क्या इन स्कूलों को टेक–ओवर किया जाएगा ताकि रिपेयर वगैरह हो सके?

श्री माडू सिह मलिक : यह एजुकेशन डिपार्टमैंट के बस की बात नहीं हम तो सारी बिल्डिग लेने के लिये तैयार हैं अगर वे नार्म के मुताबिक हों । जहां तक रिपेयर का सवाल है

श्री अध्यक्ष : आप देने के लिये तैयार नहीं हैं या वे लेने के लिये तैयार नहीं हैं?

श्री माडू सिंह मलिक : पंचायत वाले बिल्डिग को नार्म के मुताबिक नहीं बनाते इसलिये नहीं लेते । जहां तक मुरम्मत का सवाल है हमारे पास बिल्डिग फंड होते हैं, उनसे करवा देते हैं लेकिन स्कूलों की तादाद ज्यादा है इसलिये सारी बिल्डिगें नहीं हो सकतीं ।

चौधरी मनफूल सिंह : पी० डब्ल्यू ० डी० वाले टेक ओवर करने से पहले क्या–क्या बातें देखते हैं जो नार्म के मुताबिक हों?

(कोई जवाब नहीं दिया गया ।)

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : जैसे मन्त्री महोदय ने अभी नार्म की बात कही । अब अगर एक पंचायत की बनाई हुई बिल्डिग है और उसकी हालत बहुत खस्ता है जिसके कभी भी गिर जाने से बच्चों की मौत हो सकती है तो क्या मन्त्री महोदय ऐसी बिल्डिग को लेने के लिये तैयार हैं ताकि उसकी रिपेयर हो जाहू और वह चलती रहे?

श्री माडू सिंह मलिक : मैं तो पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि हम तो लेने के लिये तैयार हैं ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : लाडवा के प्राइमरी स्कूल की कोई सरकारी बिल्डिग नहीं है वह किराए की बिल्डिग में चल रहा है जिस कई रिपेयर होने वाली है । तो क्या सरकार उसकी मुरम्मत करवाने के लिये खर्चा या नई बिल्डिग बनाने के लिये. पैसा देगी?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : ये लाखों रुपये खर्च करके कालेज की बिल्डिंग बना सकते हैं तो प्राइमरी स्कूल की बिल्डिग नहीं बना सकते?

श्री जगजीत सिंह टिक्का : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि बिल्डिगें जो पंचायतों ने बनाई हैं अगर इनकी रिपेयर न हुई और गिरने की वजह से किसी बच्चे का नुकसान हो! गया तो क्या होगा? तो क्या सरकार इसके लिये कोई इन्तजाम करेंगी?

श्री बनारसी दास गुप्त : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि ग्राम वाले अपने पेट पर पट्टी बांध कर स्कूल की बिल्डिग तैयार करते हैं परन्तु उनकी मेनटेनैसं करना उनके बस की बात नहीं है । हम डिपार्टमैंट की ओर से सारे हरियाणा के स्कूलों का सर्वे करवाएंगे और ऐसी बिल्डिगों को टेक–ओवर करने का जल्दी प्रबन्ध करेंगे (तालियां) ।

Government Cafeteria at Bus Stand

***1583. ChaudhriPhul Singh Kataria :**Will the Minister for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to start Cafeteria at Bus Stands at Rohtak and Bhiwani ?

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मन्त्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) : जी नहीं।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : जैसे मन्त्री महोदया ने कह दिया कि 'नहीं' तो रोहतक और भिवानी बड़े शहर हैं और वहां कैफेटेरिया की बड़ी जरूरत है और रोहतक तो एजुकेशन का सैंटर है तो क्या वहां कैफेटेरिया खोला जाएगा?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : अभी तजुरबे के तौर पर हमने अम्बाला, करनाल और पानीपत तीन जगह खोले हैं । वहां से जब पूरी जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद बाकी जगहों पर भी खोलेंगे ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मन्त्री महोदया बताएगी कि यह तजुरबा कितने दिनों तक तैयार हो जाएगा?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : जब उससे कोई फायदा नजर आएगा तब तजुरबा तैयार होगा ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : अभी कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला आ रहा है क्या वहां कैफेटेरिया खोलने की कृपा करेंगे ताकि जो दूर दूर से लोग आएंगे उनको अच्छा खाना और अच्छी चीजें मिलें और हरियाणा का नाम भी ऊंचा हो?

परिवहन मंत्री (श्री के० एल० पोसवाल) : हमने एक कैफेटेरिया पिपली में खोला हुआ है । गर्ग साहब जितने भी आदमी भेजना चाहें, भेज दें ।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि अम्बाला में जो 2– 3 साल पहले कैफेटेरिया खोला था उसको बन्द क्यों कर दिया गया है? उसकी बिल्डिग बेकार पड़ी खराब हो रही है तो उसको कब तक दुबारा चालू करने का विचार है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : ऐसी कोई इतलाह हमारे पास नहीं आई है । आनरेबल मेंबर अलग से नोटिस दे दें तो हम पता करके बता देंगे ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : एक कैफैटेरिया ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमैंट चलाता है और एक टूरीजम डिपार्टमैंट चलाता है । क्या

मन्त्री महोदय बताएंगे कि उन के स्टैडर्ड में इतना फर्क क्यों है? पानीपत और करनाल में जो कैफिटेरिए हैं उन में फर्क है । क्या मन्त्री महोदय इनके स्टैडर्ड को ऊंचा करने की कोशिश करेंगे?

श्री के० एल० पोसवाल : हर एक के स्टैडर्ड में फर्क होता है । वहां पर खाने वालों के स्टैडर्ड में भी फर्क है । (हंसी)

10.00 बजे

ROAD FROM SAFIDON TO MIMNABAD

***1572. Shri Dhaja Ram :** Will the Minister for Revenue be pleased **to state** -

(a) whether any road from Safidon to Mimnabad is being constructed at present; and

(b) whether the Government intends to extend this road upto Dadwara; if so, the time by which the said road is likely to be completed ?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma) :

(a) Yes, sir.

(b) No.

श्री धज्जा राम : मैं पंडित जी से गुजारिश करूंगा कि अगर गांव वाले मिमनाबाद से डडवाडा तक खुद मिट्टी डाल दें तो क्या मिनिस्टर साहब सड़क एक्सटैंड करने की कृपा करेंगे? वैसे

भी डडवाडा विलेज करनाल डिस्ट्रिक्ट की बाउंडरी के साथ लगता है, क्या मिनिस्टर साहब इसको कंसीडर करेंगे?

Pandit Chiranji Lal Sharma : Mr. Speaker, sir, it is a matter of policy. Dadwara is already connected with road from the other side. The request of the hon. Member to connect Dadwara with Mimnabad is genuine because Dadwara is the last village of Jind district on the border and people have to face difficulty in reaching the district headquarters. The difficulty of the people is genuine. But because there is a policy not to have duplicate links, the earth work alone will not do. However, the Government will certainly consider the desirabilty of connecting Dadwara with Mimnabad when this policy is revised.

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने इस सवाल का जबाब 'मस' में दिया है । क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि सफीदों से मिमनाबाद तक लम्बी सड़क पर कितना पैसा खर्च होगा और वह कब तक तैयार हो जाएगी?

Pandit Chiranji Lal Sharma : The road from Safidon to Dadwara will be 9.2 k.ms. in length and an estimate of Rs. 7,02,700/- was prepared in the year 1971 for this road. Out of this, the road from Safidon to Sohanpur (from 0 to 3 k. ms.) is being constructed under spill over scheme and from Sohanpur to Mimnabad (from 3 to 6.45 k. m.) under the minimum need programme.

श्री धज्जा राम : स्पीकर साहब, सफीदों में सब–जज की कोर्ट बन गई है । पहले लोग डडवाडा से असंध होते हुए

जींद चले जाते थे । अब नई कोर्ट क्रिएट हो गई है । इस चीज को मद्देनजर रखते हए, मिमनाबाद से डडवाडा तक दो अढाई किलो मीटर का रास्ता है, क्या मन्त्री महोदय यह लिंक रोड बना देंगे.?

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, I have already submitted that the hardships that the people have to face are genuine and we would certainly consider the desirability of connecting Dadwara from Safidon side as early as possible. But it all depends upon the availability of funds.

श्री प्रभु राम छछरोली : से चित्रपुरा एक अप्रोच रोड जाती है लेकिन बीच में एक फर्लाग पंचायत का कच्चा रास्ता है और पंचायत की सोलिग और रोडी हो चुकी है । क्या मन्त्री महोदय इस टुकड़े को पक्का बनाने की कृपा करेंगे?

Pandit Chiranji Lal Sharma : Well, sir, this supplementary does not arise out of this question. But, if it is a question of one furlong or so **and** if the material is lying at site, as has been said by the hon, Member, we would consolidate it.

श्री बिहारी लाल वाल्मीकि : बवानीखेडा से हसनपुर तक की सड़क पिछले दस साल से बनी हुई हे लेकिन पिंगोडा के पुल के पास 100 गज का कच्चा टुकड़ा बनाने के लिए पड़ा है । क्या मन्त्री महोदय इस टु कड़े को बनाने की कृपा करेंगे?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : कोई न कोई डिसप्यूट होगा या रिट होगी अगर ऐसा न होता तो 100 गज का टुकड़ा कच्चा न रहता ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : कुरुक्षेत्र की जुडिशियल कोर्ट पहले करनाल में थी लेकिन अब कुरुक्षेत्र में आ गई है । इस कोर्ट में आने के लिए इधर उधर से फिर कर आना पड़ता है । क्या मन्त्री महोदय कोर्ट को मिलाने के लिए लिंक रोड बनाएंगे?

Pandit Chiranji Lal Sharma : We would certainly consider such cases. The residents of the villages which have now become a part of Kurukshetra district have to face some difficulty in reaching the district headquarters. But, for that, as I have already submitted, we need money.

श्री अमर सिंह : जिन सड्कों पर रोड की कुटाई हो गई है, सिर्फ तारकोल और लास्ट फिनिशिंग–टच देना बाकी रहता है, अगर मन्त्री महोदय के नोटिस में ऐसी सडकें लाएं तो क्या वे उन सड्कों को बनवाने की कृपा करेंगे ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : We would certainly give priority to such roads where tarring is to be done.

Mr. Speaker : Question hour is over.

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Industrial Estate at Jind

***1444. Chaudhri Dal Singh :** Will the Minister for

Industries be pleased to state--

(a) whether Government intends to construct an Industrial Estate at Jind; and

(b) if so, the time by which the Estate as referred to in part (a) above is likely to be constructed ?

उद्योग मन्त्री (श्री हरपाल सिंह):

(क) जीन्द में कोई उद्योगिक सम्पदा स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है । उद्योग विभाग, जीन्द में उद्योगिक विकास कालोनी स्थापित करना चाहता है ।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

Government Agricultural Farms in the State

***1415. Chaudhri Ram Lal :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) the district-wise number and names of Government Agricultural Farms in the State togetherwith the amount of income derived therefrom during the years 1973-74 and 1974-75, separately; and

(b) the details of production of wheat, gram and sugar-cane from each of the said farms during the period referred to in part (a) above togetherwith the yield per acre, commodity-wise ?

Agriculture Minister (Col. Maha Singh) :

(a) A statement at Annexures 'A', 'B' & 'C' is

(b) laid on the table of the House.

ANNEXURE 'A'

Statement showing district-wise number, name and Income derived at Government Agriculture Farms in the State during the years 1973-74 and 1974-75

Sr. No.	Distt/Name of the Farm	Income in Rs.	
		1973-74	1974-75
A.	Amhala	35913.5	28857.7
1	Fatehpur	70830.9	32869.6
2	Nabipur	59713.5	77432.7
3	Ambala		
B.	Gurgaon	75608.1	5645.73
4	Daulatpur Nasirabad	3187.8	13171.4
5	Sarurpur	32980.6	11026.7
6	Bhopani	15301.7	42198.8
7	Seoli	19878	39E85.00
8	Sewari	4656.91	7192.61
9	Ferozepur Jhirka	59866.5	58973

10	Pingwan	5228.43	5194.92
11	Nuh		
C.	Mohindergarh	4134	7010.48
12	Dulehra Kalan	7982	48184.2
13	Tehna	3816.24	2499.15
14	Rampura	4733.03	59061.2
15	Gokalpur		
D.	Karnal	113168	NA
16	Karnal	172950	NA
17	Shamgarh	14930	21799.4
18	Shekhupura	3990.79	2332.38
19	Kabulpur Khera	12016.9	30518.3
20	Sewakheri		
E.	Kurukshetra	14799.3	NA
21	Cheeka	171384	NA
22	Pundri	24340.1	14657.2
23	Ramnagar	13315.3	14637.2
24	Ratgal	119628	NA
25	Fatehpur	8869.37	NA

26	Ladwa		
F.	Rohtak		
27	Rohtak	91457.4	119994
28	Gugaheri	67658.4	NA
29	Naya Bans	Nii	503.15
30	Bir Sunar Wala	10660	6541.55
G	Sonepat		
31	Panchi Gujran	19624.5	25794.4
32	Kharkhoda	18939.9	26128.6
H.	Bhiwani		
33	Kholawas	133439	transferred to H.S.D.C.
34	Nawan	166.2	585.55
I.	Hissar		
35	Hissar	1434123	transferred to H.S.D.C.
36	Agril. Station Hansi	330121	Do
37	Block Seed Farm Hansi	175895	NA
38	Barwala	(P & L A/C under Scrutiny)	

		9078.64	21672
39	Akkanwal	11148	9779.19
40	Bhuna	13804.8	22340.2
41	Fatehabad	5226.54	9710.73
J.	Sirsa		
42	Sirsa	302514	transferred to H.SD.C.
43	Mangiana	96135	76779.8
44	Natar	6537.97	38473.3
K.	Jind		
45	Kishanpura	under scrutiny	transferred to H.S.D.C.
46	Santok Majra	14930	14754.9
47	Amritsar	12269.2	20242.8

ANNEXURE 'B'

Statement showing Farmwise/ Crop-wise produce obtained and Average Yield/ acre during the year 1973-74.

Sr. No.	Distt./Name of Farm	Wheat Crop/ Yield		Gram Yield		Produce in qaintals Sugarcane	Av. Yield
		Total Produce	Average	Total Produce	Av. Yield		

		Produce				Total Produce	
	District Amhala						
1.	Fatehpur	153.20	6.83	0.70	0.29	-	-
2.	Nabipur	75.01	5.37	6.11	2.66	-	-
3.	Ambala	246.10	5.34	23.63	1.59	-	-
	District Gurgaon						
4.	Daulatpur Nasirabad	17.20	3.31	0.87	0.05	-	-
5.	Sarurpur	112.48	7.41	-	-	-	-
6.	Bhopani	91.30	5.63	7.58	1.82	-	-
7.	Seoli	147.00	7.17	-	-	-	-
8.	Sewari	190.00	7.76	-	-	-	-
9.	Ferozepur Jhirka	-	-	2.70	2.70	-	-
10.	Pingwan	150.85	14.92	-	-	-	-

11.	Nuh	-	-	9.03	0.91	-	-
	District Mohindergarh						
12.	Dulehra Kalan	17.10	4.96	1.44	1.00	-	-
13.	Tehana	20.00	1.96	-	-	-	-
14.	Rampura	-	-	12.00	0.96	-	-
15.	Gokalpur	24.78	4.20	1.01	0.15	-	-
	District Karnal						
16.	Karnal	447.15	9.44	18.40	3.59	-	-
17.	Shamgarh	670.50	8.67	14.50	2.63	383.56	132.25
18.	Sewakheri	256.00	10.07	-	-	455.70	151.90
19.	Kabulpurkheri	43.25	7.07	-	-	-	-
20.	Sheikhupura	313.52	12.93	-	-	-	-

	District Kurukshetra						
21.	Cheeka	87.20	6.81	17.20	2.15	-	-
22.	Pundri	450.76	11.31	17.22	4.21	254.42	254.42
23.	Ramnagar	139.27	5.68	-	-		-
24.	Ratgal	197.89	8.33	-	-	-	-
25.	Fatehpur	489.50	9.28	18.10	3.87	-	-
26.	Ladwa	222.77	6.93	-	-	-	-
	District Rohtak						
27.	Rohtak	427.32	11.25	-	-	-	-
28.	Gugaheri	197.61	6.45	35.06	2.39	200.00	200.00
29.	Naya Bans	8.40	4.66	-		-	---
30.	Bir Sunarwala	-	-	52.00	4.21	-	-
	District Sonepat						

31.	Panchi Gujran	74.44	8.40	-	-	-	-
32.	Kharkhoda	130.80	7.45	-	-	-	-
	District Bhiwani						
33.	Kohlawas	126.08	9.01	56.05	1.46	-	-
34.	Nawan	-	-	5.09	0.46	-	-
	District Hissar						
35.	Hissar	4340.69	8.15	244.32	3.46	-	-
36.	Agril. Station Hansi	1556.87	5.55	82.16	1.18	-	-
37.	Block Seed Farm Hans I	494.99	10.68	20.20	0.97	-	-
38.	Barwala	99.00	9.90	41.66	4.47	-	-
39.	Akkanwali	68.74	5.96	20.98	1.63	-	-
40.	Bhuna	183.70	11.97	4.95	3.41	-	-
41.	Fatehabad	55.40	7.28	24.90	1.78	-	-

42.	Sirsa	764.55	9.13	70.23	4.1?	-	-
43.	Mangiana	179.09	6.21	42.85	2.52	-	-
44.	Natar	80.00	7.10	-	-	-	-
	District Jind						
45.	Kishanpura	519.00	5.87	-	-	-	-
46.	Santokh Majra	46.00	2.99	20.70	1.85	-	-
47.	Amritsar	141.45	9,01	42.47	4,67	-	-

ANNEXURE 'C'

Government Agricultural Farms

Statement showing the Farm wise/Crop wise production obtained and Average yield/Acre during the year 1974-75

Sr. No.	District/Name of the Farm.	Crops Wheat Total produce	Av. Yield	Gram Total Produce	Sugarcan Total Produce	Av. Yield	Total Yields
	District Ambala						
1.	Fatehpur	95.50	3.51	-	-	-	-

2.	Nabi pur	101.65	5.62	5.25	2.62	-	-
3.	Ambala	440.94	7.15	2.95	1.07	-	-
	District Gurgaon						
4.	Daulatpur Nasirabad	42.00	6.00	-	-	-	-
5.	Sarurpur	68.00	4.82	-	-	-	-
6.	Bhopani	63.90	5.02	22.43	2.85	-	-
7.	Seoli	75 . 00	5.90	-	-	-	
8.	Sewari	244.45	9.40	-	-	-	-
9.	F. Jhirka	-	-	-	-	-	-
10.	Pingwan	303.55	10.78	-	-	-	-
11.	Nuh	-	-	-	-	-	-
	Mohindergarh						
	District						
12.	Dulehra Kalan	33.51	3.55	-	-	-	-
13.	Tehna	23.09	4.62	-	-	-	-
14.	Rampura	-	-	6.21	0.62	-	-
15.	Gokalpur	49.68	7.45	2.27	0.28	-	-
	Karnal District						

16.	Karnal	379.39	7.94	3.25	1.08	222.00	111.00
17.	Shamgarh	538.14	6.93	2.30	0.77	-	-
18.	Sewakheri	237.00	8.63	-	-	270.65	108.26
19.	Kabulpur-Khera	-	-	-	-	-	-
20.	Shekhupra	267.10	11.48	-	-	-	-
	Kurukshetra District						
21.	Cheeka	211.93	8.96	1.10	0.62	-	-
22.	Pundri	437.30	11.65	9.08	1,25		-
	Kurukshetra District Contd.						
23.	Ram Nagar	69.93	3.40	-	-	-	-
24.	Ratgal	122.91	6.32	-	-	-	-
25.	Fatehpur	397.54	7.66	2.22	0.98	-	-
26.	Ladwa	203.15	6.75	-	-	-	-
	Rohtak District						
27.	Rohtak	376.79	9.39	-	-	-	-
28.	Gugaheri	222.70	8.78	70.95	2.77	326.7	108.91

29.	Naya bans	7.20	3.95	-	-	-	-
30.	Bir-Sunarwala	17.49	6.31	8.37	2.20	446.91	153.05
	Sonepat District						
31.	Panchi Gujran	81.25	8.24	-	-	-	-
32.	Kharkhoda	75.24	10.00	-	-	-	-
	Bhiwani District						
33.	Kohlawas Transferred to the Haryana Seed Development Corporation						
34.	Nawan	-	-	11.60	1.06	-	-
	Hissar District						
35.	Hissar Transferred to Haryana Seed Development Corporation						
36.	Agril. Station Hansi	-do-					
37.	Block Seed Farm Hansi	535.31	10.42	14.25	1.20	-	-
38.	Barwala	43.75	6.41	0.11	2.28	-	-
89	Akkanwali	84.48	4.97	23.36	3.06	-	-

40. Bhuna	183.70	11.98	4.95	3.41	-	-
41. Fatehabad	52.41	6.88	24.90	1.78	-	-
District Sirsa						
42. Sirsa	Transferred to H.S.D.C.					
43. Mangiana	151.07	4.09	16.20	1.27	-	-
44. Natar	14.20	1.53	-	-	-	-
Jind District						
45. Kishanpura	Transferred to H.S.D.C.					
46. Santokh Majra	42.92	4.46	16.20	1.01	-	-
Amritsar	38.97	3.64	1.64	0.40		--

Fair Price Shops in the State

***1445 Chaudhri Dal Singh :** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state—

(a) the total number of Fair Price Shops in the State as on 31.3.75 ;

(b) the details of commodities supplied to public through the Fair Price Shops in the State during the year 1974-75;

(c) the rates of commodities wheat atta, sugar and rice at the Fair Price Shops as referred to in part (a) above ; and

(d) the total quantity of foodgrains and sugar

distributed to public through the said shops **in** the State during the years 1972-73, 1973-74, and 1974-75, separately?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (श्री श्याम चन्द) :

(क) 4508

(ख) गेहूं, गेहूं का आटा, चीनी और चावल ।

(ग) सूचना सदन की मेज पर रखी जाती है ।

(घ) सूचना सदन की मेज पर रखी जाती है ।

अनुबन्ध (ए)

31— 3— 75 को गेहूं! गेहूं का आटा, चावल, चीनी के भाव ।

	भाव प्रति क्विंटल।
	रुपये
1 चावल बेगमी (फेयर औसतन कवालटी)	174
2 चावल बासमति साधारण	210
3 चावल बासमति बढ़िया	257
4 गेहूं	136

5 गेहूं का आटा

142

6 चीनी 215

(नोट) रू परचून भाव के अतिरिक्त जो चार्जिज और लगाये गये –

(1) यदि गेहूं के भण्डार एक मार्किट के इलाके से दूसरी मार्किट में ट्रांसफर किये गये तो प्रति 100 रुपये पर मार्किट फीस 2 रुपये और लगा ।

(2) केवल अम्बाला छावनी बोर्ड इलाका में चुंगी का दर 0. 50 पैसे प्रति क्विटल वसूल किया गया ।

(3) ऐसे केसों में जहां भण्डार, मिल/सरकारी गोदाम स्टेशनों से गांवों के अन्दर ले जाए जाते हैं, वहां परचून मार्जिन के इलावा परिवहन का खर्चा जो कि पृथक–2 जगह ले जाने का भिन्न–2 होता है, उसके अतिरिक्त शामिल किया जाता है ।

अनुबन्ध (बी)

वर्ष 1972–73, 1973–74, 1974–75 में गेहूं, गेहूं का आटा, चावल और चीनी जो उचित दर की दुकानों द्वारा वितरित किया गया ।

मात्रा जो वितरित की गई (टनीज में (टनीज में)

)

वर्ष	गेहूं	गेहूं का आटा	चावल	चीनी
1972—73	63536	107258	5620	48008.2
1973—74	11355	67336	10802	52297.4
1974—75	34412	106884	16325	48468.1

अनुबन्ध ''सी''

राज्य में 31— 3—75 को कार्य कर रहे डिपुओं की कुल संख्या

क्रमांक	जिले का नाम	शहरी	देहाती	टोटल
1	सोनीपत	50	355	405
2	जीन्द	29	257	286
3	अम्बाला	173	313	486
4	गुडगांवा	190	326	516
5	नारनौल	61	366	427
6	करनाल	83	298	381

7	हिसार	103	405	508
8	कैथल	18	160	178
9	सिरसा	27	208	235
10	रोहतक	115	381	496
11	भिवानी	59	391	450
12	कुरूक्षेत्र	28	112	140
	कुल जोड	936	3572	4508

अनुबन्ध 'डी'

राज्य में 31–10–75 तक कार्य कर रहे डिपुओं की कुल संख्या

क्रमांक	जिले का नाम	कुल डिपुओं की संख्या	शहरी	देहाती	कोआप्रेटिव शहरी	सोसाइटींज देहाती	कुल जोड़	अनुसूचित जातियां शहरी	अनुसूचित जातियां देहाती	भूतपूर्व फौजी शहर	भूतपूर्व फौजी देहाती
1	सोनीपत	349	49	300	-	43	43	--	-	--	-	349
2	करनाल	385	85	300	10	29	39	2	7	1	3	385
3	कैथल	173	17	156	-	54	54	-	2	--	1	173
4	भिवानी	480	64	416	6	60	66	30	26	--	23	480
5	अम्बाला	440	157	283	32	94	26	30	12	-	-	440
6	जीन्द	251	29	222	-	35	35	50	50	2	43	251

7	रोहतक	559	116	443	4	49	53	4	43	--	-	559
8	गुडगावां	553	186	367	12	25	37	3	31	1	31	553
9	कुरूक्षेत्र	139	28	111	-	30	30	-	-	-	-	139
10	नारनौल	394	62	332	1	46	47	4	31	1	26	394
11	सिरसा	205	26	179	1	79	80	--	1	-	-	205
12	हिसार	523	106	417	5	117	122	3	18	10	38	523
	कुल जोड़	4,451	925	3,526	71	679	741	27	222	15	165	4,451

अनुबन्ध ''इ''

1–4–75 से 31– 10– 75 तक डिपु होल्डरों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की विवरणी

क्रमांक	जिले का नाम	जो डिपु कैन्सिल किये गये	जिन डिपुओं की प्रतिभूति जब्त की गई	जो केस पुलिस में रजिस्टर्ड किये गये
1	रोहतक	50	167	12
2	करनाल	14	31	4
3	अम्बाला	13	88	9
4	कैथल	8	62	4
5	भिवानी	29	106	6
6	जीन्द	23	32	9
7	गुडगांवा	54	236	13
8	सोनीपत	9	35	3
9	नारनौल	14	124	5
10	हिसार	19	178	2

11	कुरूक्षेत्र	5	11	3
12	सिरसा	9	26	4

Government Schools opened by the State Government

***1416. Chaudhri Ram Lal :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the teksil-wise number of Government Primary, Middle High and Higher Secondary Schools opened by the Government in the State during the years 1974-75 and 1975-76 (to-date), separately ; and

(b) whether the buildings and the teaching staff are available **in** such schools ?

शिक्षा मन्त्री (श्री माडू सिंह मलिक) :

(ए) शून्य ।

(बी) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Strength of Police

500. Shri Dhaja Ram : Will the Chief Minister be pleased to

state the Police Station-wise strength of Constables,

Head Constables, A.S.Is and S. Is. in the State as at present ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरणी में दी गई है ।

STATEMENT

1. AMBALA DISTRICT

	SIs	Ms.	HCs.	Consts.
1. P.S. Sadar Ambala	1	1	3	12
P.P. Nagal	—	1	—	6
P.P. Model Town	—	—	1	6
P.P. Baldev Nagar	—	—	1	6
P.P. Mahesh Nagar	—	—	1	6
Total :—	1	2	6	36
2. P.S. Jagadhri	1	2	3	14
P.P. Buria	—		1	—
P.P. City Jagadhri	—	—	1	8
Total :—	1	2	5	22
3. P.S. Sadhaura	1	1	-2	11
P.P. City Sadhaura	—	—	1	10
Total :—	1	1	3	21

4.	P.S. Chhaper	1	1	2	13
5.	P.S. Bilaspur	1	1	2	13
6.	P-S. Raipur Rani	1	2	2	13
7.	P.S. Kalka	1	1	2	11
	P.P. City Kalka	—	—	1	10
	Total :—	1	1	3	21
8.	P . S. Pinjore	1	1	2	15
	P.P. Surajpur	—	—	1	4
	P.P. Mughal Garden	—	—	1	4
	Total :—	1	1	4	23
9.	P.S. Mulana	1	2	2	13
	P.P. Barara	—	1	1	6
	Total :—	1	3	3	19
10.	P.S. Naraingarh	1	1	—	11
	P.P. Patwa	—	1	—	4
	P.P. City Shahzadpur	—	—	1	8
	Total :—	1	2	1	23
11.	P.S. Chandimandir	1	1	2	13

	P.P. Panchkula	—	1	1	8
	Total :—	1	2	3	21
12.	P.S. Chhachhrauli	1	1	2	13
	P.P. City Chhachhrauli	—	—	1	8
	Total :—	1	1	3	21
13.	P.S. Sadar Yamuna Nagar	1	1	3	15
14.	P.S. City Ambala	1	3	8	46
	Watch & Ward staff etc.	1	—	8	82
	Total :—	2	3	16	128
15.	P.S. Ambala Cantt.	2	4	19	121
	Watch & Ward staff etc.	2	1	10	123
	Total :—	4	5	29	244
16.	P.S. City Yamuna Nagar	1	3	7	9
	Watch & Ward staff etc.	1	—	8	79
	Total :—	2	3	15	88

2. KURUKSHETRA DISTRICT

1.	P.S. City Kaithal	3	—	3	17
	Watch & Ward staff etc.	—	—	3	26

Total :—	3	—	6	43
2. P.S. Sadar Kaithal	1	3	4	15
3. P.S. Pundri	1	1	4	11
Watch & Ward staff etc.	—	—	1	10
Total :—	1	1	5	21
4. P.S. Pehwa	1	1	5	10
P.P. Dhand	—	—	1	5
Total :—	1	1	6	15
5. P.S. Guhla	1	1	5	10
P.P. Cheeka		1	1	6
Total :—	1	2	6	16
6. P.S. Thanesar	1	1	6	9
Watch & Ward staff etc.	—	—	1	10
P.P. City Thanesar	—	1	—	6
P.P. Kurukshetra University	—	1	1	8
P.P. Pipli	—	1	1	8
Total :—	1	4	9	41
7. P.S. Radaur	1	1	2	11

8. P.S. Thaska	1	1	2	11
9. P.S. Shahabad	1	1	4	11
Watch & Ward staff etc.	—	—	2	15
Total :—	1	1	6	26
10. P.S. Ladwa	1	1	2	11

3. KARNAL DISTRICT

1. P.S. City Karnal	3	10	5	69
Watch & Ward staff etc.	1	1	13	78
Total : —	4	11	18	147
2. P. S. City Panipat	3	9	5	69
Watch & Ward staff etc.	1	1	12	75
Total :—	4	10	17	144
3. P.S. Sadar Karnal	1	2	6	11
P.P. Uchana Lake	—	—	1	4
Total : —	1	2	7	15
4. P. S. Sadar Panipat	1	1	5	10
5. P.S. Samalkha	1	1	2	13
6. P.S. Urlana	1	1	2	14
P. P. Naultha	—	1	—	5

Total :—	1	2	2	19
7. P. S. Gharaunda	1	1	3	13
8. P.S. Nissing	1	1	3	12
9. P. S. Assandh	1	1	3	12
10. P. S. Butana	1	1	3	12
P. P. Nilokheri	—	1	2	8
Total : —	1	2	5	20
11. P. S. Indri	1	1	2	13

4. SONEPAT DISTRICT

1. P.S. City Sonepat	3	—	8	28
Watch & Ward staff etc.	—	—	3	30
Total :—	3	—	11	58
2. P.S. Sadar Sonepat	1	1	2	13
3. P.S. Gannaur	1	2	3	13
P.P. City Gannaur	—	—	1	6
Total : —	1	2	4	19
4. P.S. Gohana	1	1	2	12
P.P. City Gohana	—	—	1	8
Total : —	1	1	3	20

5.	P.S. Rai	1	2	4	13
6.	P.S. Barauda	1	1	2	13
7.	P.S. Kharkhauda	1	1	2	11

5. ROHTAK DISTIRCT

1.	P.S. City Rohtak	2	3	9.	50
	Watch & Ward staff etc.	—	1	13	127
	P.P. Medical College Rohtak	1	1	—	15
	Total : —	3	5	22	192
2.	P. S. Sadar Rohtak	1	1	2	15
3.	P.S. Kalanaur	1	1	2	13
4.	P.S. Sampla	1	2	2	15
5.	P.S. Meham	1	1	3	12
	Watch & Ward staff etc.	—	—	1	12
	P.P. Lakhan Majra	—	1	1	4
	Total : —	1	2	5	28
6.	P.S. Beri	1	1	2	11
	Watch & Ward staff etc.	—	—	2	12

Total : —	1	1	4	23
7. P.S. Bahadurgarh	1	1	5	10
Watch & Ward staff etc.	—	—	1	8
Total : —	1	1	6	18
8. P.S. Jhajjar	1	1	3	12
Watch & Ward staff etc.	—	—	2	16
P.P. Dujana	—	1	—	4
Total : —	1	2	'5	32
9. P.S. Sahlawas	1	1	2	11
PP. Nahar	—	1	1	7
Total : —	1	2	3	18

6. GURGAON DISTRICT

1. P.S. City Gurgaon	3	—	6	45
- Watch & Ward staff etc.	—	—	1	10
Total :—	3	—	7	55
2. P.S. N.I.T. Faridabad	2	2	12	90
P.P. Old Faridabad	—	1	—	6
P.P. City Faridabad	—	1	4	37
P.P. Badkhal Lake	—	1	1	20

Total :—	2	5	17	153
3. P.S. Palwal	1	2	4	13
P.P. City Palwal	—	1	2	20
Total :—	1	3	6	33
4. P.S. Ferozepur Jhirka	1	1	2	13
P.P. City Ferozepur Jhirka	—	—	1	10
Total : —	1	1	3	23
5. P.S. Hassanpur	1	1	2	13
P.P. Hodel	—	1	1	10
Total :—	1	2	3	23
6. P.S. Ballabhgarh	1	2	3	12
P.P. City Ballabhgarh	—	—	1	10
Total :—	1	2	4	22
7. P.S. Pataudi	1	1	2	15
P.P. City Pataudi	—	—	1	8
P.P. Hali Mandi	—	—	1	6
Total : —	1	1	4	29
8. P.S. Sohna	1	1	2	13

P.P. City Sohna	—	—	1	10
Total : —	1	1	3	23
9. P.S. Nuh	1	1	2	13
10. P.S. Punhana	1	1	2	11
11. P.S. Chhansa	1	1	2	11
12. P.S. Taoru	1	1	2	11
13. P.S. Farrukhnagar	1	1	2	11
14. P.S. Sadar Gurgaon	1	2	4	13
15. P.S. Hathin	1	1	2	11
16. P.S. Central Faridabad	2	2	12	98

7. HISSAR DISTRICT

1. P.S. City Hissar	1	4	7	16
Watch & Ward staff etc.	—	—	9	91
P.P. H.T. M. City Hissar	—	1	1	10
Total :—	1	5	17	117
2. P.S. Sadar Hissar	1	2	5	15
P.P. Bal Samad	—	1	—	3
P.P. Adampur	—	1	1	10
Total :—	1	4	6	28

3.	P.S. Barwala	1	1	2	13
	P.P. Uklana	—	1	—	6
	Total : —	1	2	2	19
4.	P.S. Tohana	1	1	3	12
	P.P. Jhakhal	—	1	1	8
	P.P. City Tohana	—	—	1	11
	Total :—	1	2	5	31
5.	P.S. City Hansi	1	2	1	14
	Watch & Ward staff ctc.	—	—	5	36
	Total : —	1	2	6	50
6.	P. S. Sadar Hansi	1	2	2	14
7.	P.S. Narnaund	1	1	2	14
8.	P.S. Fatehabad	1	2	5	15
	P.P. Bhattu Kalan	—	1	—	6
	P.P. City Fatehabad	—	1	—	8
	Total :—	1	4	5	29
9.	P.S. Bhuna	1	1	3	14
10.	P.S. Ratia	1	2	4	11

8. BHIWANI DISTRICT

1.	P.S. City Bhiwani	1	3	5	15
	Watch & Ward staff etc.	—	1	10	97
	Total : —	1	4	15	112
2.	P.S. Sadar Bhiwani	1	1	2	13
3.	P.S. Tosham	1	1	2	11
	P.P. Kairon	—	1	—	6
	Total : —	1	2	2	17
4.	P.S. Siwani	1	1	2	11
5.	P.S. Loharu	1	1	3	15
	P.P. Cheharkalan	—	1	1	6
	Total : —	1	2	4	21
6.	P.S. Bawani Khera	1	2	3	12
	P.P. Dhanana	—	1	1	8
	Total : —	1	3	4	20
7.	P.S. Dadri	1	1	5	11
	P.P. City & Mandi Dadri	—	1	2	18
	P.P. Bond	—	1	1	8
	Total :—	1	3	8	37
8.	P.S. Satnali	1	1	3	15

9. P.S. Badhra		1	1	2	11

9. JIND DISTRICT

1. P.S. Jind		1	2	4	13
Watch & Ward staff etc.		—	—	3	28
	Total : —	1	2	7	41
2. P.S. Narwana		1	2	5	10
Watch & Ward staff etc.		—	—	2	16
	Total : —	1	2	7	26
3. P . S. Uchana		1	2	1	18
4. P.S. Kalayat		1	1	2	11
5. P.S. Jullana		1	1	2	11
6. P.S. Safidon -		1	1	3	10
Watch & Ward staff etc.		—	—	1	8
	Total : —	1	1	4	8
7. P.S. Rajaund		1	1	3	12

10. MOHINDERGARH DISTRICT

1. P.S. Narnaul		1	1	3	10
Watch & Ward staff etc.		—	—	3	30
	Total :—	1	1	6	40

2.	P.S. Nangal Chaudhri	1	1	2	11
3.	P.S. Mohindergarh	1	1	3	10
	Watch & Ward staff etc.	—	—	1	12
	Total :—	1	1	4	22
4.	P.S. Kanina	1	1	2	11
	P.P. Kanina	—	—	1	8
	Total :—	1	1	3	19
5.	P.S. Ateli	1	1	2	11
	Watch & Ward staff etc.	—	—	1	4
	Total :--	1	1	3	15
6.	P.S. Sadar Rewari	1	1	3	12
7.	P.S. City Rewari	1	1	3	10
	Watch & Ward staff etc.	—	—	8	61
	Total :—	1	1	11	71
8.	P.S. Jatusana	1	1	2	11
9.	P.S. Bawal	1	—	2	13
	Watch & Ward staff etc.	—	—	1	10
	Total : —	1	—	3	23
10.	P.S. Khol	1	1	2	12

11. SIRSA DISTRICT

1.	P.S. City Sirsa	1	2	3	14
	Watch & Ward staff etc.	—	—	5	48
	Total : —	1	2	8	62
2.	P.S. Sadar Sirsa	1	1	3	15
	P.P. Jamal	—	1	—	3
	P.P. Ding	—	1	—	6
	Total : —	1	3	3	24
3.	P,S. Dabwali	1	1	3	15
	P.P. Chutala	—	1	—	4
	P.P. City Dabwali	—	—	1	12
	Total : —	1	2	4	31
4.	P.S. Rania	1	1	3	14
	P.P. Elnabad	—	1	—	6
	Total :—	1	2	3	20
5.	P.S. Baragudha	1	2	3	18
	P.P. Kalanwali	—	1	1	8
	P.P. Rori	—	1	1	9
	Total : —	1	4	5	35

Govt. Railway Police, Ambala Cantt.

1. G.R.P.S. Ambala Cantt.				
PP/Staff	1	1	2	8
Platform staff	1	—	2	16
Out Post Jagadhri	—	1	—	4
Patrol staff	—	—	6	7
Total : —	2	2	10	35
2. G.R.P.S. KALKA				
Platform staff	1	—	1	6
PP/Staff	1	1	1	8
Patrol staff	—	—	1	3
Out Post Chandigarh	—	1	2	8
Total : —	2	2	5	25
3. G.R.P.S. KARNAL	1	1	1	8
Patrol staff Kurukshetra	—	—	—	2
Out Post Panipat	—	—	1	4
Out Post Kurukshetra	—	—	1	3
Sonepat	—	—	1	3
Total : —	1	1	4	20

4. G.R.P.S. JIND				
PP/Staff	1	1	1	8
Patrol staff	—	—	1	6
Platform Staff	—	—	—	-
Out Post Narwana	—	—	1	2
Out Post Rohtak	—	—	1	4
Total : —	1	1	4	20
5. G.R.P.S. HISSAR				
PP/Staff	1	1	1	8
Platform staff	—	—	1	3
Patrol staff	—	—	2	3
Out Post Bhiwani	—	—	1	3
Out Posr Jakhal	—	1	1	4
Out Post Sirsa	—	—	1	3
Out Post Dabwali	—	1	1	6
Total : —	1	3	8	30
6. G.RP.S. REWARI				
PP/Staff	1	1	1	8
Platform staff	—	—	1	4

Patrol staff	—	—	2	3
Out Post Loharu	—	—	1	4
Out Post Narnaul	—	1	1	3
Out Post Dadri	—	—	1	2
Out Post Palwal	—	—	1	2
Out Post Faridabad	—	—	2	8
Total :—	1	2	10	34

कार्य मंत्रणा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

Mr. Speaker: I have to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various business.

The Committee, after some discussion, recommended that the business on the 23rd, 27th and 28th January, 1976, be transacted as follows:—

Friday, the 23rd January, 1976 (9.30.A.M)

1. Questions Hour .

2. Second Report of the Business Advisory Committee.

3. The Haryana Appropriation Bill, 1976, on Budget. (Two Hours).

4. Discussion and voting on Supplementary Estimates (Second Installment) for the year 1975-76. (One

Hour).

Saturday, the 24th January, 1976 -- Off day.

Sunday, the 25th January, 1976-- Holiday.

Monday, the 26th January, 1976-- Holiday.

TUESDAY, THE 27TH JANUARY 1976

I. Questions Hour.

II. Papers to be laid on the Table

(1) Laying of the Supplementary Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1973-74 of the Government of Haryana.

(2) Laying of the Election Commission of India notification No. S. 0. 738(E), dated the 26th December, 1975, regarding amendment in Table B of the Delimitation Commission's order No. 28 of 2nd December, 1974.

(3) Annual Report of the Haryana Agricultural University Hissar **for** the period from Ist July, 1972, to 30th June, 1973.

III. Presentation of Report of the Committee.

Presentation of Third Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

IV. Presentation of Preliminary Reports of the Committee, of Privileges and extension of time for making the Final Report.

V. Motion regarding extension of terms of the existing Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes by a year i.e. upto 31st March, 1977.

VI. Official Resolution under article 252 (1) regarding amendments in the Indian Forest Act, 1927.

VII. Legislative Business.

The Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1976 on Supplementary

Estimates (Second Instalment) 1975-76.

2. Other Legislative Bills.

Wednesday, the 28th January, 1976 (9.30 A.M.).

I. Questions Hour.

II. Motion under rule 15 regarding non-stop sitting of the House.

III. Motion under rule 16 regarding adjournment of the House Sine-die.

IV. CONSIDERATION of Government Business entered in the List of Business for Tuesday, the 27th January, 1976 and not concluded on that day, and any other pending Business.

Transport Minister (Shri K. L.Poswal) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory

Committee.

Mr. Speaker: Motion moved-

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

हरियाणा विनियोग विधेयक, 1976

Finance Minister (Shri Ram Saran Chand Mital): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation Bill, 1976.

Sir, I beg to move—

That the Haryana Appropriation Bill be taken into consideration at once,

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation Bill be taken into consideration at once.

चौधरी रिजक राम (राई) : स्पीकर साहब, 19 76—77 के एप्रोप्रिएशन बिल पर मैं चन्द बातें अर्ज करना चाहता हूं । जनरल डिस्कशन के दौरान मुख्य मन्त्री जी ने बहुत सी बातों का

स्पष्टीकरण कर दिया, कुछ बातें उन्होंने बहुत साफ तौर पर ऐसी कही जिन के लिए मैं उनका धन्यवादी हूं । उन्होंने हाउस को यह यकीन दिलाया कि जहां तक हिन्दू सकसैशन ऐक्ट का ताल्लुक है वह सैन्ट्रल ऐक्ट है लेकिन फिर भी वे अपनी पार्टी में इसका निरीक्षण कराएंगे और जहां तक हो सकेगा इसमें तरमीम लाने की कोशिश करेंगे । मैं इसके लिए उनका धन्यवादी हुं लेकिन एक बात और अर्ज करना चाहता है । जहां तक हिन्दू मकसैशन ऐक्ट का ताल्लुक है वह बेशक सैन्ट्रल ऐक्ट है लेकिन वह कनकरैन्ट लिस्ट पर है । यह सैन्ट्रल लैवल पर भी ऐग्जामिन हुआ है ला मिनिस्ट्री में और वैसे भी लोकसभा में सन् 1967–68 में जब श्री हाजिर नवीस डिप्टी ला मिनिस्टर थे उस वक्त इस पर हाउस में भी बहस हुई थी और उन्हैंने जवाब दिया था कि इस सवाल की अच्छी तरह पड़ताल कर ली गई है और स्टेट लैजिसलेचर्ज इसमें तरमीम करने की पावर रखती हैं लेकिन जो तरमीम वे करें उसको प्रैजीडैन्ट की असैन्ट के लिए भेजना पड़ेगा । यह इसकी लीगल पोजीशन है लेकिन फिर भी ये अपनी पार्टी में, ला डिपार्टमैंट में एल० आर० साहब से और एडवोकेट जनरल आदि से, इनकी पार्टी में भी अच्छे अच्छे बकला साहबान हैं, उनसे ऐग्जामिन करा ले और जिन जिन क्लाजिज की वजह से ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में या स्टेट की इकौनोमी में बाधा पड़ती है उनमें तरमीम करने की कृपा करें । आज हम देखते हैं कि इस ऐक्ट की वजह से घर घर में तलखी आई हुई है, इतनी बड़ी तादाद में मुकदमे दायर हुए हैं अदालतों में जिसका कोई हिसाब नहीं है । सगे भाई हल्फ में

ब्यान देने पर मजबूर हो रहे हैं कि सगी बहन को कह देते हैं कि हम नहीं जानते । बेटी मां को, मां बेटी को, बहिन भाई को भाई बहिन को कोर्ट में घसीट रहे हैं । मैं ज्यादा न कहते हुए मुख्य मंत्री जी से एक बार फिर प्रार्थना करता हू कि वे इसका निरीक्षण करा लें और जो भी तरमीम हो वह इसमें जल्दी से जल्दी कराने की कृपा करें ।

स्पीकर साहब, इसके सम्बन्ध में एक बात मैं और अर्ज करना चाहता है । आज हरियाणा में जैसा उन्होंने माना बड़ा भारी कर्जा किसानों के जिम्मे है । मार्जिनल फारमर्ज पर, स्माल फारमर्ज पर, बड़े फारमर्ज पर भी, दूसरे आर्टिजन्ज और हरिजन्ज आदि पर भी बड़ा भारी कर्जा है और रिकवरी के लिए उनकी जमीन भी, मकान अगर यूक से ज्यादा हो तो वह भी, प्लौट भी नीलाम हो सकता है नेशनेलाइज्ड बैक्सं, कोआप्रेटिव वैक्स और प्राईवेट मनीलैन्डर्ज की डिग्रीज में । लैड एलियनेशन ऐक्ट प्रैजिडैन्शल आर्डर से खत्म हो गया है । उसके कुछ सैक्शज में इसके लिए कुछ प्रोटैक्शन थी लेकिन डिसक्रिमिनेटरी होने की वजह से वह ऐक्ट जो था वह रह कर दिया गया । तो मैं अर्ज करूंगा कि बिना डिस– क्रिमिनेशन के सभी किसानों को, चाहे वे किसी बिरादरी या सैक्शन से हों, हरिजन हैं या दूसरे हैं, प्रोटैक्शन दें कि किसी भी कर्जे की वसूली में चाहे वह नेशनेलाइज्ड वैक्स का हो, कोआप्रेटिव बैंक्स का हो या प्राईवेट मनी लैन्डर्ज का हो, जमीन नीलाम नहीं हो सकती । आप वसूली का इन्तजाम कर लें कि 20, 30 या 40

साल में वह रुपया वसूल हो जाए लीजिज के जरिए वरना आप देखेंगे कि पांच या दस साल में कितने किसान भूमिहीन हो जाएंगे । उनके पास साधन नहीं रहेगा कमाई का क्योंकि आज तक दूसरा साधन दे नहीं सके है । अगर जमीन भी नीलाम हो गई तो वह बिल्कुल बेवश हो जाएंगे । तो यह बात भी मैं मुख्य मंत्री जी के विचार के लिए पेश करना चाहता हूं क्योंकि यह बड़ा जरूरी मसला है । आज भी कितने लोग हैं, जो छोटे–छोटे उिकुए हैं भूमि के उनको बेचने लग रहे हैं कर्जा अदा करने के लिए और दूसरे साधन उनके पास हैं नहीं ।

इसके बाद, स्पीकर साहब, मैं एा और बात अर्ज करना चाहता हूं जो ऐमरजैन्सौ के मुताल्लिक है । इस आपात स्थिति में कितने आदमी हैं जो कि मिसा में बंद हैं । वह सरकार की नीति है और ऊपर के लेवल तक उसमें बहस मुबाहस चल रही है कि मिसा के तहत गिरफतारी हो या न हो, वह ठीक पकड़ा हुआ है या नहीं पकड़ा हुआ है द्वैं इस बहस में नहीं पड़ता लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हू कि मिसा के अलावा भी कितने पोलिटिकल वर्कर्ज हैं जो 107 और डी० आई० आर० में रोक गिरफ्तार होते हैं । स्पीकर साहब, दफा 107 और डी ० आई० आर० के तहत जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उनमें एम० एल० एज० और ऐडवोकेट्स भी शामिल हैं । इनके अलावा और भी बड़ी बड़ी इज्जत वाले शामिल हैं । उनके खिलाफ गिरफ्तारी के लिए आज पुलिस अनडिजायरेबल ऐली– मैन्टस, दस नम्बरिए और अपने

टाउटस को इस्तेमाल करने लग रही है । झूठी कंप्लेन्टस लेते हैं, उनके दस्तखत करवाए जाते हैं और मजबून पुलिस खुद बनाती है । बेशक आप गिरफ्तार करें अगर आपकी यही नीति है, सरकार को इससे यदि फायदा हए लेकिन पुलिस को जो आपने इतने अख्तियारात दिए हैं ये ठीक नहीं हैं । यह शिकायत करवाना कि मुझे एक एम० एल० ए० से खतरा है मुझे एक 60– 70 साल बूढे वकील से खतरा है, महज मजाक करना है । ये अख्तियार इतने मिस–युर हो रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है । अपि मालूम करें कि आज देहात में क्या हो रहा है । पुलिस की आज सबसे ज्यादा मौज हो रही है । पुलिस वाले तशदद कर रहे हैं । पुलिस अगर किसी घर में जाए तो वहां टैरर पैदा हो जाती है । अगर आपने ये अधिकार दिए रूल आफ ला को एक तरफ रख कर तो आयंदा इमसे बडी खराबी होगी । इसके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं कि मुख्य मंजी जी इस ओर पूरा ध्यान दें और पुलिस को ऐसे अख्तियार न दें कि वह झूठे केस बनाए । मेरी कई अफसरान से बात हुई । मैंने कहा कि आप क्या करें रहें हैं । आज लोगों को झूठे मुकदमे बना कर क्यों गिरफतार करते हो? कितने ही पुलिस अफसरान ने कहा कि क्या करें बहुत ज्यादा मुश्किल हमें हो रही है । हमें कंप्लेन्ट खुद करवानी पड़ती है, हमें कहानी भी खुद बनानी पड़ती है और लोगों को गिरफ्तार भी करना पड़ता है । मैं नुक्ताचीनी 'के ख्याल से यह नहीं कह रहा लेकिन इसका असर आगे के लिए बुरा पड़ेगा पुलिस को इस तरह के अख्तियारात देने के बाद ।

स्पीकर साहब, एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं । यह ऐग्रीकल्चरल लेबरर्ज और दूसरे इंडस्ट्रियल वर्कर्ज के बारे में है । श्री गुलाब सिंह जैन ने बोलते हुए फरमाया कि आपात स्थिति से और बीस प्यांयट प्रोग्राम से जो प्रधान मती ने रखा है, इन लोगों कि बहुत फायदा पहुंचा हैँ । मैं उनसे इतना ही अर्ज करना चाहता हूं औंर मुख्य मली जी का भी ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता है कि जहां आपने इंडस्ट्रियल वर्कर्ज को यह सहुलियत दी है और वे शेयर और प्लांट लेवल पर मैनेजमैंट में इछ शामिल हो सकते है कंसल्टेशंज में उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा हानिकारक बात हुस दौरान आर्डिनैन्स के जरिए की गई है वह है बोनस को खत्म करने की । सन् 1971 से आज तक जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर्ज थे उनको 8.30 फीसदी बोनस जरूर मिलता था । चाहे इंडस्ट्री या फैक्टरी यूनिट घाटे में हो या मुनाफे में हो 8.33 फीसदी बोनस अश्योर्ड था । यह हरेक एम्पलायर को देना पड़ता था आज सरकार ने जो पालिसी अपनाई है उसमें उसको मौडिफाई कर दिया है । अब चार परसैन्ट या साढ़े. चार परसैन्ट बोनस उस हालत में मिलेगा जब इंडस्ट्री में मुनाफा होगा और. तीन साल की ऐवरेज देखकर उस मुनाफा का फैसला किया जाएगा । अभी अभी परसों लोकसभा में भी इस सम्बन्ध में बहस हुई । एक सवाल का जवाब देते हुए इंडस्ट्री मिनिस्टर ने फरमाया कि उन्होंने तीन बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिटस जो हैं उनके ऊपर छापा मारा है और उनके अकाउंटस में कितनी ही कमियां पाई हैं । उन्होंने फर्जी हिसाब किताब रखे हुए हैं ।

उन्होंने जो फिगर्ज दी हैं वह इनफलेटिड दिखाई हैं । उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने प्रोडक्शन के लिए लिए गए आर्टिकल्ज की परचेज प्राईस भी ज्यादा दिखाई है और दूसरा खर्चा भी ज्यादा दिखाया है और इस तरह से मुनाफा को डिफ्लेट किया हुआ है । इसलिए यह मानते हुए कि जहां इंडस्ट्री का हिसाब किताब रखने के जिम्मेदार वे खुद हैं, उसमें हेरा फेरी होती है । 1500 करोड़ की वालेन्टरी डिस्कलोजर हुई है । यह वालेन्टरी डिस्कलोजर करने वाले कोई गरीब किसान और मजदूर नहीं हैं । 1500 करोड़ की हेरा फेरी तो बड़े–बड़े लोगों ने खुद मानी है । वह टैक्स का इवेजन है । 911 करोड़ के बड़े–बड़े मनौपली हाउसिज हैं, उनके जिम्मे टैक्स बकाया है, इंकमटैकस बकाया है । बहुत बड़ी हेराफेरी करते हैं । जहां आपने बोनस को इस मुनाफे के साथ मिलाया, तो क्या उन मजदूरों को बोनस मिल जाएगा? सरकार ने 1971 में फैसला किया था कि हर कारखानेदार को सवा आठ परसैन्ट बोनस जरूर देना पड़ेगा । उस वक्त यह हिसाब लगाया था कि यह जो बोनस है, यह कास्ट आफ प्रोडक्शन में शामिल है, जो खर्चा है उसमें शामिल है ।

श्री गुलाब सिंह जैन : आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर । मैं आपके जरिए चौधरी रिक्त राम जी से पूछना चाहता हूं कि वे सैन्ट्रल गवर्नमैंट की पालिसी पर बोल रहे हैं या हरियाणा के ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोल रहे हैं ।

चौधरी रिजक राम : दूसरी बात यह है कि जो ऐग्रीकल्चर लेबर के वेजिज मुकरर्र किये हैं उससे यह जाहिर करने की कोशिश की है कि ऐग्रीकल्चर लेबर को बहुत बड़ी सहूलियत दी है । सहूलियत मिलनी चाहिए और बेजिज भी मिलने चाहिएं । साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां आपने वेजिज मुकरर्र किये. हैं क्या उनको काम देने की कोशिश करेंगे? आज देहातों में 70–80 फीसदी लोग बेकार बैठे हैं उनको काम नहीं मिलता । सड़कों का जो कैश प्रोग्राम बनाया था, वह खत्म हो गया, बिजली के महकमें से जो काम मिलता था, वह खत्म हो गया । नहरें पक्की करने का काम था वह भी खत्म हो गया । आपके पास और दूसरा कोई काम नहीं है । डिवैल्पमैंट के काम के लिए रुपया नहीं है । आज मजद्ऊर रवाली बैठे हैं । उसको कोई काम नहीं मिलता । ने बेचारे मारे–मारे फिरते हैं ।

अभी कल पी० डबयू ० डी० मिनिस्टर ने कहा है कि एक करोड़ रुपया 197 5–76 मैं सड़कों के लिए खर्च कर पायेने । मैं, स्पीकर साहब, यह जानना चाहता हू कि कितने लोगों को काम मिला? दूसरे आप कहते हैं कि ऐग्रीकल्चर लेबरर से सड्कों पर काम करने वाले को कम वेजिज देते हैं । स्पीकर साहब, क्रैश प्रोग्राम देश में चला, उसमें तीन रुपए रोजाना मजदूरी मुकरर्र की औरऐग्रीक्लचर लेबर की मजटूरी ज्यादा फिक्स की । उसमें इस सरकार ने कितनी गड़बड़ की । जब सरकार को देना पड़ता हए तो तीन रुपए देते हैं और किसान से ज्यादा दिलाना चाहते हैं ।

बेशक ज्यादा दिलायें लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग बेजिज मुकरर्र करते हैं उनको देहातों की हालत का पता नहीं है । उनको पता नहीं कि देहात में मजदूर को कितनी मजदूरी मिलती है । गेहूं की कटाई के टाईम पर बीस पुली काटने पर एक पूली मिलती है । वहां कांट्रेक्स बेसिज पर शाम तक अच्छा मजदूर बीस– पच्चीस रुपए का काम कर लेता है । उसमें वह अनाज भूसा दोनों चीज मिलाकर बीस रुपए की मजदूरी कर लेता है लेकिन सरकार को जब अपनी तरफ से मजदूरी देनी पडती है तो तीन रुपये मुकरर्र करती है । बहुत कम मजदूरी मुकरर्र करती है । गांव में आपस के कांट्रेक्ट के आधार पर ज्यादा मजदूरी लेते हैं लेकिन सरकार खुद कम मजदूरी क्यों देती है । किसान से ज्यादा क्यों दिलवाना चाहती है । ऐसा सरकार क्यों कर रही है? इसलिए करना चाहती है कि मजदूर मोर किसान के बीच टैन्सन चलती रहे । मेहनत करने वाले किसान और मजदूर आपस में मिलकर देश की तरक्की का काम कर सकते हैं लेकिन सरकार तो ऐसी बात सोचती है कि उनके बींच आपस में फूट और टैन्सन बढ़ती जाये, चाहे लैन्ड रिफार्म– के जरिये, चाहे अनाज के भाव कम करके चाहे वेजिज बढ़ने के जरिये । मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता लेकिन यह मेरी कनविक्शन है, पोजेटिव कनविक्शन है ।

कल इरीगेशन स्टेट मिनिस्टर साहब ने भी और मुख्य मंत्री जी ने एक बात फरमायी । उन्होंने कहा कि हम जो अब

इरीगेशन का सिस्टम बनाने चले हैं चाहे वह नेहरू कैनाल है, चाहे सिवानी कैनाल है, चाहे जुई कैनाल है, चाहे लोहारु कैनाल है उनमें जो भी पानी आयेगा वह एक कतरा भी दूसरे इलाके की नहरों से नहीं लेंगे । उन्होंने फरमाया कि जहां वे नहर बनाने लग रहे हैं, एक सूखे इलाके में पानी दे रहे हैं उसके साथ–साथ हांसी का इलाका, दूसरे वैस्टर्न जमुना का, करनाल का, रोहतक और जींद का इलाका है उसमें जो वाटर लोगिग की प्रोब्लम है वह भी हल हो जायेगी । वाटर लौगिग का हल कैसे हुआ और सरकार का कितना कन्ट्रीव्यूशन है, वह सब को मालूम है । यूक तो सन् 1964–65 में भगवान् की मर्जी से बारिश कम हुई और सन् 1966–67 में कहत पड़ गया । बाद में भी लगातार कहत पर कहत पडता रहा और बारिश कम हो गई । वाटर टैबल कम हो गया । वाटर टैबल कहीं पर तीन फुट, दो फुट और एक फुट तक चला गया । वह वाटर टैबल इस बात का सबूत है । कुछ' सरकार के ट्यूबवैल्ज लगे, कुछ लोगों ने लगाये, इस तरह से वाटर टैबल कम हुआ और कुछ नहरें पक्की हो गई । इस तरह वाटर लोगिग कम हो गई लेकिन बरसात कम होने से भी वाटर लौगिग में फर्क पड़ा है । आपने जुई नहर निकाली है इस वजह से वाटर लौगिग कम नहीं हुई है ।

दूसरी बात यह है कि जहां यह फरमाते हैं कि दूसरे इलाकों का एक कतरा पानी नहीं लेगे, वैसे तो मैं आपकी अश्योरेंस का यकीन करता हू और आपका धन्यवाद करता हूं कि

आप सारे इलाकों के साथ अच्छा व्यवहार और न्याय करना चाहते हैं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं चाहे आप कितनी ही कोशिश करें, लेकिन उन इलाकों को इस तरह से पानी देना मुमकिन नहीं है । वैस्टर्न जम्उना ट्रेक ओर दूसरे इलाकों का पानी लिए बिना उन इलाकों को पानी देना नामुमकिन है । आप मुझे समझा दीजिए किस हिसाब से देना चाहते हैं । स्पीकर साहब, आपको मालूम है कि मेन ब्रांच जो आपकी वैस्टर्न जमुना ट्रेक है, उस पर महेन्द्रगढ़ का, भिवानी का इलाका छोड़. कर वैस्टर्न जमुना का पुराना इलाका है उसमें कोई 28 लाख एकड का सी ० सी० ए ० है । उसके बारे में जैसा आपने यकीन दिलाया कि आप उनको 42/50 परसैन्ट इनटेनसिटी फैक्टर पर पानी देना चाहते हैं । कम से कम .2! 5० परसैन्ट इनटेनसिटी फैक्टर पर इन इलाकों को पानी देना चाहते हैं । अगर यह पानी देना है तो मेन ब्रान्च पर 9100 क्यूसिक पानी की सप्लाई होनी चाहिए । मेन ब्रान्च से, मुनक से, आप जानते हैं दो नहरें निकलती हैं, एक हांसी ब्रान्च और एक देहली ब्रांच । साढे चार–चार हजार क्यूसिक की सप्लाई हरेक ब्रान्च में होनी चाहिए लेकिन इस तरह से यी सप्लाई नहीं चल सकती । आप रिकार्ड को देखें उसमें सर्दियों के मौसम में और उधर गर्मियों के मौसम में मई, बुन और अप्रैल में ईख और काटन को पानी की जरूरत होती है और इधर रबी की फसल के टाईम सर्दियों में पानी की जरूरत होती है तो उस वक्त दरिया में फुन्न दो हजार या 1800 क्यूसिक पानी होता है । एक तिहाई यू० पी० ले लेती है, कुछ पानी ऐबजार्बशन और लौसिज में चला जाता ीऐ

। जब पानी की सख्त से सख्त जरूरत किसानों को होती है दी भी 1500 या दो हजार क्यूसिक की सप्लाई होती है । तो आप कैसे पानी पूरा करेंगे? कुछ पानी आप ट्यूववैल्ज से शी डालते हैं । हुस हिसाब से 9100 क्यूसिक की रिक्वायरमैंट है और कुल पानी आपके पास 1500 या 2000 क्यूसिक है । आपको मालूम हए कि 2000 क्यूसिक पानी आप पूरा नहीं कर सकते । इसके साथ–साथ आपने जई कैनाल को पैरेनियल कर दिया है तो सर्दियों में या मई जून में पानी कैसे दे सकते हैं जब कि कम से कम पानी दरिया में है । तो अपि समझायें कि किस तरह से पानी बढ़ा है । में यह दावे के साथ कहता है कि दरिया का पानी अनसर्टन है, उसकी मिकदार कई बार बहुत कम हो जाती है । इसलिए आपको दिल्ली और हांसी ब्रांच रोटेशन से चलानी पड़ती है । पानी की कमी की वजह से जुई कैनाल बनने के बावजुद भी ऐसा कितनी ही बार हुआ जबकि सदी और गमी में एक–एक किसान को अपनी बारी के लिये चालीस–चालीस और ब्यालीस–ब्यालीस दिन तक इन्तजार करना पड़ा, उसकी टर्न नहीं आयी और आगुमेटेशन कैनाल बनने के बाद अब भी यही हालत चल रही है । आगुमेटेशन कैनाल आपने इस ख्याल से बनायी और यह कहा कि जो किसान की टर्न आफ वाटर 30 दिन या 40 दिन के अन्दर आती है, हम उसको कम करके हफता या 15 दिन तक ले आयेंगे., आपका यह अन्दाजा था । आपने इंजीनियर्ज की सलाह की बिना पर यह भी फरमाया कि 10 किलोमीटर लम्बी नहर जो जमुना नगर से मुनक तक बनेगी उसमें जो एडजौर्पशन लासिज 500 क्यूसिक के करीब

हैं, वह बिल्कुल खत्म कर देंगे या नोमीनल से रहेंगे । फिर आपने यह भी फरमाया कि जो ट्यूबवैल लगेगे उनसे भी हम 4– 5 सौ के करीब अडीशनल वाटर दे सकेंगे । आपका यह ख्याल था । इस तरह से आपका यह अन्दाजा था कि 900 क्यूसिक बाइससे फालतू पानी बढ़ जायेगा । आपने जो आगुमेंटेशन कैनाल बनायी उस पर 13 करोड़ के करीब खर्च किया । उसके सैकण्ड फेज में रुकावट आयी लेकिन इसके बावजूद आपने 150– 160 के लगभग ट्यूबवैल्ज उस एरिया में लगाये और नहर को पक्का बनाया । नहर पर इतना पैसा खर्च करने औंर उसको पक्का करने के बारे में मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूं । एक तो यह कि जो आपके इंजीनियर्ज ने जो यह सलाह दी कि जो कच्ची नहर के 500 क्यूसिक के करीब लासिज हैं, वे बिल्कुल खत्म हो जायेगे, वह बिल्बुब्ल गलत और बे–बुनियाद सलाह थी । चाहे आप बेशक पक्की नहर बना लें लेकिन कभी भी ये लासिज मुकम्मत तौर पर खत्म नहीं हो सकेंगे क्योंकि यह ठीक है कि सीमेंट थोड़ा सा कम पानी लेगा लेकिन ईटें तो पानी पीयेंगी । तो मेरा कहने का मतलब यह भी है कि उसमें आप आपरेशनल लासिज को भी खत्म नहीं कर सकते । जैसें मुख्य मंत्री जी ने फरमाया है, मेरे ख्याल में पक्की सानें निकालने से लासिज नहीं जागीयें लेकिन यह हो सकता है कि जो सीपेज है, वह कम हो जायेगी । पक्की नहरें निकालने या पक्की धाने बनाने से एब्जौर्पशन लासिज और इवैपोरेशन लासिज बिल्कुल रहेगा । तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप आगुमैंटेशन कैनाल की मिसाल ले लो और इसे बाकी

भी लागू करो । इंजीनियर्ज ने जो यह राय दी कि 500 क्यू सिक जो एन्कौर्पशन लासिज हैं, वे बिल्कुल खत्म कर देंगे, वह उन्होंने मिसलीड किया है और गवर्नमैंट को गलत सलाह दी है । पहले न तो इतने लासिज थे और न वे कन्ट्रोल कर पाये. । दूसरी बात यह है कि सरकार का यह अन्दाजा था कि हम आगुमैंटेशन ट्यूबवैल्व के जरिये 4– 5 सौ क्यूसिक के लगभग पानी बढ़ा सकेंगे वह भी पूरा नहीं हो सका क्योंकि आप ट्यूबवैल्ज ज्यादा नहीं लगा सके और वह इस– लिये कि यू० पी० से झगड़ा होगया । लेकिन जो भी ट्यूबवैल लगे उनकी कैपेसिटी के मुताबिक हमारा पानी नहीं बढ़ा । स्पीकर साहब, मैं इस बारे में ज्यादा समय न लेते हुए कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल ने जो आडिट रिपोर्ट' 1973– 74 की दी है, उसकी चन्द लाइनें हाउस के सामने रखना चाहता है । आडिटर जनरल ने आगुमैंटेशन कैनाल की सीपेज लासिज और कितना पानी बढा है, इसको एग्जामिन किया है और यह बड़ी स्पष्ट है ––

The estimated seepage loss of about 500 cusecs (on which the project was planned) was based mainly on the discharge data collected from Indri to Munak in 1965 and on theoretical calculations. A study of the departmental record of the discharge data for the three Rabi seasons prior to the commissioning of the Augmentaticn Canal hcwever, showed as under :

इसमें उन्होंने 1970– 71, 1971– 72 और 1972– 73 का डैटा दिया है । उन्होंने कहा है कि डिस्चार्ज इतना था, नैट

डिस्चार्ज. इतना था और एक्चुअल डिस्चार्ज इतना था । यह तफसील उन्होंने दी है । आखिर में उन्होंने लिखा है –

The discharge did not depict a uniform position. While the seepage loss ranged between 57 to 261 cusecs, in some months there was even regeneration effect ranging from 37 to 400 cusecs.

स्पीकर साहब, इस रिपोर्ट से आप साफ यह बात देखेंगे कि जो उन्होंने कहा कि हम 500 क्यूसिक लासिज बिल्कुल खत्म कर देंगे, वह तो निराधार बात थी । इसके साथ उन्होंनेरू यह भी कहा कि उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि जो कच्ची नहरें हैं, उनमें पानी री–जनरेट होता रखा है, जो पास का या बरसात का पानी है, वह भी वहां आता रहता है । रीजनरेशन से जो पानी बढता रहा है, उसकी एवरेज भी 37 से 400 क्यूसिक थी, इस बात का भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा । सिर्फ लासिज–लासिज को कह दियां कि हम ' इतनी लासिज खत्म कर देंगे, इतनी हमने खत्म कर दी है और जो रीजनरेशन थी, उसको ध्यान में नहीं रखा । जो आखिरी बात है, उसके बारे में उन्होंने यह कहा है रू–

After the commissioning of the Augmentation Canal in January 1973 the position of the seepage loss occuring between Dadupur and Munak and the supply augmented through tubewells was as under :—

Actual losses

कैनाल्ज की लाइनिंग होने के बावजूद जो एक्चुअल लासिज हुए हैं वे हैं

January, 1974	338 cusecs
February, 1974	466 „
ovember, 1974	84 „
December, 1974	649 „
January, 1975	495 „
February. 1975	684 „

Actual supply through tubewells-

इतनी मेहनत करने के बावजूद जो एक्चुअल सप्लाई है, वह कम हुई है, उसे भी आप देख लें :

January, 1973	269 cusecs
December, 1973	285 „
January, 1974	279 „
February, 1974	297 „
November, 1974	302 „
December, 1974	273 „
January, 1975	161 „
February, 1975	173 „

Net result in supply—

उन्होंने कहा है कि नैट रिजल्ट कम निकला है क्योंकि पानी कम मिलता है, जो पानी चला वह है –

January, 1974	59 cusecs
February, 1974	169 „
December, 1974	376 „
January, 1975	334 „
February, 1975	511 „

Despite construction of the Augmentation Canal, the seepage loss was not reduced, this loss ranged from nil to 684 cusecs during the Rabi season of 1973-74 and 1974-75 against an anticipated loss of 31 cusecs. The actual water supply through tubewells ranged from 161 to 302 cusecs against the target of 460 cusecs. The net supply of water augmented in the Canal between Dadupur and Munak thus varied from 269 cusecs to (—) 169 cusecs during November, 1973 to February, 1974 and 218 cusecs to (—) 511 cusecs during November, 1974 to February, 1975. The Department attributed (September, 1974) the continuous decline in overall augmentation effect to atmospheric and geohydrological conditions.

तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आगुमैंटेशन कैनाल की तो यह हालत है और बाकी कैनाल्ज के बारे में आप सारे हरियाणा के लोगों के सामने यह तखमीना दे रहे हैं कि हम

इनको पक्की कर रहे हैं और इससे जो पानी बचेगा उससे हमारी आबपाशी बढेगी । मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा कन्क्रीट सबूत हो नहीं सकता कि आपको इस मामले में जो इंजीनियर्ज गाइडैन्स दे रहे हैं, वह बिल्कुल गलत है । जो पानी इस इलाके का था, वह पैरेनीयल कैनाल बनाकर और दूसरी नहरें खोदकर, बगैर इस बात का हिसाब लगाये कि व्यास–सतलुज का पानी मिलेगा भी या नहीं वेस्ट करते जा रहे हैं और जिसकी वजह से हरियाणा की इकोनोमी जो आज तक चल रही थी, उसको बिल्कुल खत्म कर रहे हैं । उसको बिल्कुल खत्म करने लग रहे हैं (घंटी) बस मैं खत्म करने जा रहा हूं । स्पीकर साहब, आग देखें कि आपने फर्टीलाइजर दिया, आपने अच्छे सीड्ज दिए लेकिन आज इंजीनियर्ज और साईटिस्ट भी मानते हैं कि आपने जो नए बीज दिए हैं और खाद दिया हैं, गेहूं की फसल पकाने के लिए चार–पांच पानी दिए जाएं । अगर आप कम पानी देंगे तो फसल पकेगी नहीं । आप एक पानी मुश्किल से दे पाते हैं 40–42 दिन में और वे लोग नुक्सान उठाते जा रहे हैं मंहगे बीज का और महंगे खाद का । स्पीकर साहब, इसका सबूत मैं लास्ट पैरा पढकर दे देता हू

According to the Department (October, 1973) water was to be released in Delhi and Hansi Channels alternately at an interval of 8 days during October, November and December, 1973 and at an interval of 16 days from January, 1974 onwards till the end of the Rabi season 1973-74. Each channel was further divided into two groups for irrigation in turn for 4

to 8 days. Accordingly, a farmer was expected to get his turn after about 16 days' interval during October-December, 1973 and 32 days' interval during January, 1974 onwards. A test check of the records of three out of five divisions concerned indicated that the interval of water availability during Rabi 1973-74 was 44-45 days. The object of reducing the interval of water from 32-40 days to 16 days on completion of the original phase—I would not thus appear to have been achieved.

आज भी 44— 45 दिन में रबी सीजन में पानी देते हैं और समझते हैं कि वे लोग पैदावार कर सकते हैं । आज रेट आफ प्रोडेक्टिविटी गिरती जा रही है । इसका कारण है पानी का न दे सकना । स्पीकर साहब, राक बात को मानकर चलना पड़ेगा आखिर बैकवर्ड एरियाज जो हैं उनको भी पानी देना है इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता और उन इलाकों को भी खत्म नहीं करना है जो बैकवर्ड नहीं हैं क्योंकि पैदावार बढ़ानी है । अध्यक्ष महोदय, मैं एक तजवीज देना चाहता हूं मुख्य मंजी महोदय उस पर विचार कर लें । वह यह कि बैकवर्ड एरियाज में पैरेनियल नहर बनाना बेग्गयनी है, इससे ज्यादा गल्त बात कोई नहीं हो सकती । बल्कि आपको यह करना चाहिए कि आप क्रापिंग पैटर्न डिटरमिन करे । कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिन इलाकों में सरसों, तोरिया और चना पैदा होता है, आजकल तो चना गेहूं से भी ज्यादा फायदा देता है और कुछ इलाके जैसे रोहतक, सोनीपत और करनाल यहां तो स्पीकर साहब, चना होना बन्द हो गया है ओर ईख भी खराब होने लगी है, वहां लोग गेहूं काश्त करते हैं ।

आप गेहूं के लिए पानी दे सकते हैं । कल मंत्री महोदय ने जवाब देते हुए बताया कि जो ब्यास सतलुज से पानी मिलेगा वह कामन मूल में जाएगा । आज हमारी नहरों का सिस्टम भी इंटेगरेटिड है । एक सिस्टम से दूसरे में पानी लिया जा सकता है । स्पीकर साहब, अगर आपने हरियाणा की इकानामी को बढ़ावा देना है, अगर एग्रीकल्चरल प्रोडेक्शन को बढाना है तो एक ही तरीका है कि आप क्रापिंग पैटर्न को डिटरमिन करें और आप क्राप नीड्ज के मुताबिक पानी दें । पानी की तकसीम इस तरह से करें जैसी वहां की क्राप को जरूरत है ।

श्री अध्यक्ष : अब आप खत्म करे । आप काफी बोल चुके हैं । आपकी साइड से फिर किसी को टाइम नहीं मिलेगा ।

चौधरी रिजक राम : बस मैं खत्म करने ही जा रहा हूं जी । जुई कैनाल जो आपने पैरेनियल की है 1973 में सिर्फ 8 एकडु रकबे में गेहूं था । आप यह नहीं देखें कि हमने नहरें पैरेनियल करनी हैं । स्पीकर साहब, 1973 में मैंने सुजैशन दी थी कि चने की काश्त लोहारू, महेन्द्रगढ़ में कराएं । सरसों आप भिवानी में कराएं और उनको एक पानी दें जिससे फसल पक जाए और यहां से पानी बचाकर उस इलाके को ज्यादा दें जहां गेहूं की फसल होती है इससे हरियाणा की इकानामी में इजाफा होगा । अध्यक्ष महोदय मैं इन शब्दों के साथ खत्म करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं ।

श्री राम धारी गौड़ (गोहाना) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन' के सामने ऐप्रोप्रिएशन बिल जिसका रेजोल्युशन हमारे वित्त मन्त्री ने पेश किया और सदन से मांग की कि इसको पास किया जाए । इसमें किसी को एतराज कहीं है । यह बहुत बढ़िया बजट हए और इसका बेश्तर हिस्सा उन कामों के लिए.. है जिस से हरियाणा की इकानामी बढ़ेगी, पैदावार में इजाफा होगा । आप बजट को गौर से पढ़ें तो इरीगेशन, पावर और एग्रीकल्चर इनका बहुत घना सम्बन्ध है क्योंकि खेतीबाड़ी के लिए पानी. बिजली, खाद और बीज बहुत जरूरी है । ये उसके इनपुट्स हैं । आप देखेंगे कि बजट का कम से कम 80 फीसदी हिस्सा इन बढ़िया कामों के लिए, इन बढ़िया मद्दों के लिए रखा गया है । इसको पास करने मैं किसी को एतराज नहीं हो सकता । अभी मेरे साथी चौधरी रिजक राम ने बताया कि पहले वर्ष में ही कूओं का पानी खारा हो जाएगा क्योंकि आपने नहरों को और खालो को पक्का कर दिया । आज बहू कहते हैं कि सीपेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा । वह बताएं कि वह पानी कहां खारा हो रहा है । उन्होंने इंजीनियरों की बात को झुटला दिया । मैं कहना चाहता हूं कि इंजीनियर्ज ने हरियाणा की इकानामी को बढ़ाने में बड़ा अनथक काम किया है, अच्छी योजनाएं बनाई है और आप देखें कि वह हरियाणा जिसमें हम यूक लाख टन अनाज कामन पूल से मंगाते थे आज सरप्लस बन गर' हैं और सवा आठ लाख. एकड़ जमीन में ज्यादा पानी लग रहा है । अनाज की पैदावार में इसलिए बढ़ौतरी हूई कि ज्यादा पानी जमीन को दिया गया । यह

तो आंकड़े हैं कि सवा आठ लाख एकड़ को ज्यादा पानी लगने लगा है । आप बताईए कि अगर यह सीपेज कम न होंगे, आगमेन्टेशन कैनाल मैं पानी नहीं (ने जाते तो यह बढ़ौतरी कैसे हो सकती थी । मेरे मोहतरम साथी चौधरी रिजक राम ने आडिटर जनरल की रिपोर्ट पढी । अब हमको अपने इंजीनियर्ज की राय भी छापनी पड़ेगी क्योंकि वह पानी के बारे में ज्यादा जानते हैं अ और यह कहना कि रि–जनरेशन का पानी खत्म हो जाएगा, मैं कहता हूं कि वह खत्म नहीं हो सकता । आप देखेंगे कि जो पुरानी कैनाल हैं, जो कच्ची हैं अब भी रिजनरेशन का पानी उनमें आ रहा है । अगर यह आगमेन्टेशन नहर नहीं बनती तो रिजनरेशन का पानी कम आना था । तीन–चार सौ क्यूसिक पानी रिजनरेशन का आ रहा है । अगर हम करनाल के पास पुल पर से गुजरें तो देखेंगे कि वहां बुलवुले पानी में चलते दिखाई देते हैं । वह पानी कही से आता है, वह रिजनरेशन का पानी है । अध्यक्ष. महोदय, समय बहुत थोड़ा है इसलिये मैं अपने हल्के गुहाने के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हू । आज मुझे इन बातों को कहने का मौका मिला है कि सन् 1972– 73 के अन्दर लाठ माइनर के लिये एक बिल पास हुआ था, उसके लिये पैसा भी सरकार ने सैन्कशन कर दिया था लेकिन 72 के बाद आज तक उस का पता नहीं चलता कि वह सभी एस्टीमेट्स कहां गये', उस माईनर पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है । अध्यक्ष महोदय, गुहाने का बहुत बड़ा इलाका है जहां के लोग पानी के लिये तरह रहे हैं, लोगों को वहां पर पानी नहीं मिलता बल्कि वहां के लोगों

ने तो यहां तक कह दिया था कि इस काम के लिये हम भी कुछ पैसा देंगे और अब सरकार की नीति बदल गई है । अध्यक्ष महोदय, राक बार इस सदन के अन्दर जो चीज पास हो जाए तो उस पर अवश्य शीघ्र ही सरकार की ओर से कार्यवाही की जानी चाहिये, मैं आप की मारफत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और अपने वचन को पूरा करने की कृपा करे ।

अध्यक्ष महोदय, एक और बात मैं आपको उस इलाके की बताता हूं कि गुहाने का इलाका पशु धन के लिये बहुत मशहूर है, वहां की गाएं भैसें उत्तम कोटि की हैं, और वह मारा इलाका फरटाइल इलाका है और लोग पशु पालन में दिलचस्पी रखते हैं । अध्यक्ष महोदय जब हरियाणा नहीं बना था तो सब से पहले गुहाने में मिल्क प्लांट लगने की मंजूरी हुई थी और वहां पर विभाग के आदमी भी पहुंच. गये थे, सभी प्रकार का सर्वे भीहो चुका था लेकिन बाद में वाइट रेवेल्युशन आया और गुहाना भी लांग गये, जींद भी लांग गये कहीं पर भी न टिक सके, आग देखिये कि अब अम्बाला में भी मिल्क प्लांट बन गया है जितने भी मिल्क प्लांट बने हैं सब उसके बाद में ही बनें हैं लेकिन गुहाने में अभी तक मिल्क प्लांट नहीं बना है तो आपके द्वारा मैं डेयरी डिवैल्पमैंट विभाग वालों से यह दर्खास्त करूंगा कि गुहाने का सर्वे किया जाए । वहां पर दूध काफी मिकदार में मिल सकता है ।

अध्यक्ष महोदय, यूक दो बातें और मैं यहां पर सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि गोहाना में कोई इंडस्ट्री नहीं है,

अतः गुहाने को इंडस्ट्रीलाईज किया जाए । काकी देर से यह इलाका इग्नोरड है, सरकार इस तरफ ध्यान दे जहां हरियाणा के अन्दर कई विकास के कार्य हो रहे हैए, उन में कुछ हिस्सा गुहाने को भी मिलना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, वैसे गोहाना में इंडस्ट्रियल एरिया भी मन्जूर हो चुका है, सभी कागज पल भी कम्पलीट हो चुके हैं लेकिन पता नहीं कि वह सारा कैस कहा पर छुपा पड़ा हए, वहां पर कोई काम भी नहीं हुआ है । अतरू सरकार इस ओर ध्यान दे और शीघ्र ही इलाके की खुशहाली का प्रबन्ध करे ।

अध्यक्ष महोदय, आपको भी जैसे पता है कि गुहाना तहसील में सब से ज्यादा गन्ना पैदा होता है लेकिन किसान जो है वह कंफयूजड है कि वह अपना गन्ना कौन सी मिल में ले जाए, पानीपत की मिल में ले जाए, रोहतक की मिल में ले जाए या सोनीपत की मिल में ले जाए, कहा ले जाए । सरकार को कोआपरेटिव सरकारी मिलें लगानी चाहिये ताकि गन्ना बेचने में किसान को आसानी हो सके । जहां सरकार जगह जगह पर मिलें लगा रही है क्हं सरकार गोहाने की तरक्की के लिये भी कुछ ध्यान दे जोकि बैकवर्ड प्रिया है, जहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं है । अध्यक्ष महोदय, वैसे वहां के लोग बड़े हिम्मती हैं, उन्होंने अपने मामूली से साधनों से ही एक निवार की इंडस्ट्रीज गोहाना में लगा रखी हैं और दो या ढाई करोड़ रुपये की निवार एक्सपोर्ट की है, यह तौ उनरू लोगों की अपनी हिम्मत थी जो आगे निकल गये अगर

सरकार उस इलाके के हिम्मती लोगों का थोड़ा सा साथ दे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस इलाके के लोग सारे हरियाणा का नाम दूसरे प्रान्तों में, दूसरे देशों गे ऊँचा कररू सकेंगे । जैसे मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा था कि हम लैन्डलैस लोगों को, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, कोई साधन नहीं हैं, काम धन्धा देने के लिये एक निगम बना रहेहैं तौ मुझे इस काम से बड़ी खुशी है कि सरकार ऐसे उत्तम कदम उठाने जा रही है, इससे हरियाणा के अन्दर काफी हद तक बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और जो लैन्ड लैस आदमी हैं, जो सहमा हुआ बैठा है, सरकार की ऐसी नीति से उस में हौसला आएगा, वह आगे बढ़ेगा और देश व अपने प्रान्त का नाम ऊचा करेगा । और दूसरी तरफ देश में गरीबी दूर करने के लिये हमारी मोहतरिमा प्रधान मन्त्री श्रीमती गांधी ने अपने 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने का आदेश दिया है, कदम उठाया है और उन पर अमल करने से ही यह देश की गरीबी दूर हो सकेगी, जिसके लिये हमारी हरियाणा सरकार वचनबद्ध है । हरियाणा प्रदेश सबसे पहला प्रदेश है जिसने प्रधान मन्त्री के 2० सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने के लिये अपने बजट में इस का विवरण दिया है और दृढ़ निश्चय किया है कि इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम पर बड़ी शीघ्रता और कठोरता से अमल किया जाएगा । (इस समय उपाध्यक्षा चेयर पर आई) आज सरकार ने मजदूर की मजदूरी बढ़ाई है यह बहुत अच्छी बात है. पानी के लिये, खेतीबाड़ी के लिये खाद का उचित दरों पर प्रबन्ध किया गया है ताकि लोगों को इससे राहत मिल सके । और दूसरे कई

छोटे–छोटे धन्धे भी जैसे नू में, भिवानी में बनकरों के लिये सोसाइटीज बनाई गई हैं अतः इस तरह की सोसाइटीज हरेक जिला में होनी चाहिये । डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज बुनकरों का जो धन्धा था, उसको आज बिडला ने अपने हाथ में ले लिया है और दूसरे कई ऐसे गरीब आदमियों के काम धन्धे हैं जो पैसे के जोर से मिल मालिकों ने अपने हाथ में ले लिये हैं, हम यह चाहते हैं कि लुहार का जो काम था वह लुहार के गाम रहे. टाटा के पास क्यों जाए जो कुम्हार का काम है वह कुम्हार के पास रहे, वह बाबा के क्यों जाए. मोची का जो काम है वह मोची के पास जाए बाटा क्एरू पास क्यों जारा तो यह सभी बातें तभी सम्भव हो सकती हैं जबकि हम गरीब आदमी को पैसे से दूसरे साधनों से सुसज्जित करें ताकि गरीब आदमी अपने धन्धों को दुबारा अपने हाथों में ले सकें क्योंकि आज अमीर आदमी ने अपने पैसे के जोर से सभी छोटे–छोटे धन्धे अपने हाथ में ले लिये हैं और वह उन को बढ़ा कर लाखों करोड़ों और अरबों रुपये कमा रहा है और दूसरी ३ तरफ गरीब आदमी अपने बच्चों को पालने के फिकर में लगा हुआ है । एक मोची अच्छे से अच्छे जूते बना सकता है लेकिन कमी एक बात की है कि उसके पास कोई साधन नहीं हैं., अतरू वे सभी साधन सरकार मुहैया करे और उस गरीब का बना हुआ माल सरकार खरीदे और अपने उसके स्टोर बनें । जहां कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उस गरीब आदमी का माल वहां जाए । बेचारा कर्जा वगैरह उठाकर माल तो तैयार कर लेता है लेकिन उससे होता क्या है कि उसका माल उठाने वाला कोई नहीं होता

अतरू मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन छोटे लोगों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिये । सरकार ने कर्जे का बिल लाकर यह तो अच्छा किया कि गरीब आदमियों को उनके चंगुल से निकाला गया लेकिन पैसा उसको मिलना चाहिये और उस पैसे से जो वह पैदा करे उसके लिये सरकार की जिम्मेदारी हो कि वह माल स्टोरों और एम्पोरियमों में जाए और जितने हम लोग हैं हम भी अपना इरादा यह बना कर जाएं कि हुमने गरीब मोची के माल को खरीदना है । महात्मा गांधी जी ने भी स्वदेशी कपडा पहनने के लिये नारा लगाया था क्योंकि विदेशी कपड़ा खरीदने के साथ हमारा बहुत सारा पैसा इंग्लैंड चला जाता था । गांधी जी ने स्वदेशी कपड़े के लिये नारा इसलिये लगाया था ताकि यहां का पैसा यहां ही रहे । तो मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने बजट तैयार करते समय हमारी प्रधान मन्त्री के बीस सूत्री प्रोग्राम को ध्यान में रखा है और मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसे ही बजट आते रहे तो एक दिन हरियाणा का नक्शा बदल जाएगा और प्रधान मन्त्री का जो बीस सूती प्रोग्राम है इसको सफल बनाने में हरियाणा सबसे पहले नम्बर पर होगा और इस प्रोग्राम को अमली जाना पहना कर गरीबी को दूर करने के लिये हरियाणा पहले नम्बर पर होगा । इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

11.00 बजे

श्री के ० एन० गुलाटी (फरीदाबाद) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो बिल इस समय हमारे सामने है मैं भी इसको पास करने के हक में खड़ा हुआ हूं । मैं आपकी मार्फत यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है, बहुत अच्छा बजट हमारे सामने है और मैं तो यह समझता हं कि हमारी हरियाणा सरकार, चीफ मिनिस्टर साहब और सारे मिनिस्टर साहिबान दिन रात एक करके, अपनी सारी ताकत लगा कर और उसके साथ साथ सारे एम ० एल० एज० की बातें सुन कर, उनके दिल और दिमाग की बात सुन कर फिर कोई स्कीम बनाती है । इन्हीं स्कीमों के असर से आज हमारा हरियाणा हर पहलू से सब से आगे है । कुछ हमारे विरोधी भाई खामखाह नुक्ताचीनी करते रहते हैं । उनको चाहिये कि वे अच्छाई की तारीफ करें और जहाँ किसी छोटे मोटे सुझाव की जरूरत हो बहु दें । लेकिन उनकी तो हूर काम में नुक्ताचीनी करने की आदत हो गई है । मैं इस बिल की भी तारीफ करता हूं और सरकार की भी तारीफ करता हूं कि उसने इतना अच्छा बजट तैयार किया हए । इसलिये मैं चाहूंगा कि यह बिल पास किया जाए । इसके बाद मैं कुछ बातें आपकी मार्फत कहना चाहूंगा । टैक्सेशन के बारे में कहना चाहता है कि हुमारे सेल्ज टैक्स का यूनिफार्म रेट बनाया जाए । जो हमारे साथ लगती दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान और यू ० पी० की स्टेटें हैं इनके साथ हमारा सेल्ज टैक्स का यूनिफार्म रेट होना चाहिये ।

इसके बाद मैं प्रोफैशनल टैक्स के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे पब्लिक सैक्टर में बहुत एम्पलाईज हैं जिन पर प्रोफैशनल टैक्स लगता हए मैं चाहता हूं कि इसका खत्म कर दिया जाए या बीस सूजी प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए जैसे इन्कम टैक्स को खत्म कर लिमिट 6 हजार से बढ़ा कर दम हजार कर दी गई है उसी तरह प्रोफैशनल टैक्स भी दस हजार से ऊपर लगना चाहिये । इसके बाद मैं यी चाहता हूं कि हाउस टैक्स और प्रोपर्टी टैक्स को मिला कर एक कर दिया जाए । मेरा अगला प्वांयट यह है कि फरीदाबाद में सेल्ज टैक्स के दफतर अलग अलग जगह पर हैं अगर उनको एक जगह इकटठा कर दिया जाए तो अफसरों का आपस में तालमेल रह सकता है इसलिये जल्द से जल्द वहां पर एक सेल्ज टैक्स आफिस बना दिया जातु । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं हैल्थ के बारे में अर्ज करुंगा कि आज हैल्थ डिपार्टमैंट पर बहुत खर्चा किया जा रहा है । मैं देखता हूं कि आज होम्योपैथिक इलाज पर बहुत कम खर्च होता है और यह इलाज इस वकत बहुत कामयाब भी है, इसलिये इस तरफ सरकार ध्यान दे । बजट में नई एलोपैथिक डिसपैसरियां खोलने के लिये प्रोवीजन रखी गई है और मुझे उम्मीद है कि फरीदाबाद और बल्लभगढ को इग्नोर नही किया जाएगा । इससे आगे मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां जहां हस्पतालों में स्टाफ की कमी है और खास तौर पर क्लास वन और टू को यहां वहां पर यह स्टाफ फौरन भेज दिया जाए । इसके बाद मैं फैमिली प्लानिंग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि यह कानून बना दिया जाए कि जो खुशी से

आप्रेशन करवाना चाहे उसका आप्रेशन किया जाए, जबरदस्ती न की जाए । मैं चाहूंगा कि फैमिली प्लानिंग के लिये. एक सैल बिस्कूल सैपरेट होना चाहिये जो सिर्फ फैमिली प्लानिग का काम करे ताकि दूसरे मुलाजिमों को की कर दिया जाए ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मैं फूड एंड सप्लाई के बारे में कहना चाहता हूं किसी भेंट के परमिट के लिये 15– 15 दिन लग जाते हैं जबकि आज कल सीमेंट की पोजीशन ठीक हए इसलिये मैं चाहता है कि सीमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन फ्री कर दी जाए जिससे कि लोगों को भी सहूलियत मिलेगी और महकमे वाले भी अपना कोई और काम कर सकेंगे । इसके बाद मैं डिपोज के बारे में बात करना चाहता हूं कि डिपो होल्डर्ज को दाल और चीनी में मार्जिन. आफ प्रोफिट बहुत कम है । मैं चाहूंगा कि मार्जिन आफ प्रोफिट बढ़ा दिया जाए ताकि डिपो होल्डर ईमानदारी से काम कर सकें । थोडा मार्जिन होने की वजह से या तो वे बेइमानी करते हैं या कोई साइड बिजनैस करने लग जाते हैं । डिप्टी स्पीकर साहिबा फरीदाबाद के डी० एफ० एस० ओं ० के दफ्तर की बिल्डिग के बहुत कम कमरे हैं और वहां फोन भीनहीं–है–... इसलिये सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए । इसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हू कि एस० डी ० ओ० सिविल और एस० डी० एम० की एक ही पोस्ट है जिसकी वजह से अफसर के पास बहुत काम रहता है और काम पीछे पड़ जाता है इसलिये मैं चाहूंगा कि ये

पोस्टें अलग अलग कर दी जाएं तो ज्यादा तेजी से काम चल सकेगा । इसके बाद एस० ए० एस ० के जो सीनियर आडिटर हैं उनकी जो सी० आर० है वह फाइनैसं डिपार्टमैंट लिखे न कि उनके सीनियर अफसर । इस कारण से कई जगह आपस में झगड़ा हो जाता है जिसकी वजह से सरकारी काम में रुकावट आती है । अगर फाइनैसं डिपार्टमेंट वाले उनकी सी० आर० लिखें तो अच्छा रहेगा और सरकार को भी रैवेन्यू का फायदा होगा क्योंकि वे मिल जुल कर काम करेंगे इसलिये ज्यादा फायदा होगा । इसके बाद मैं यह चाहता हूं कि पैनशन के मामले में बहुत देर लग जाती है हुसके लिये ए० जी० और कंसर्न्ड डिपार्टमैंट को मिल कर तेजी से काम करना चाहिये ताकि रिटायर होने वाले आदमी को तकलीफ न हो । जहां तक डोनेशज और लोन्ज का संबंध है, एच ० एस० इ ० बी० और दूसरे डिपार्टमैंटस के लिये सरकार लोन लेती है, ठीक है चूंकि जरूरत पड़ती है लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके लिये भी सैपरेट सैल हो और इसके लिये सबडिवीजज के दूसरे अफसर काम न करें । इससे भी काम में तरक्की होगी और डोनेशज और लोन्ज ज्यादा इकट्ठे होंगे । इसके बाद पब्लिक हैल्थ और बी ० एंड आर० को जो काम सौंपा जाता है वह टारगेट के अन्डर नहींहो पाता, मैटीरियल सही नहीं लगता और ट्रेनिंग ठीक नहीं चलती तो इसके मुताल्लिक भी ध्यान दिया जाए । कुछ काम तो इन डिपार्टमैंट्स में बहुत अच्छे चल रहे हैं लेकिन उनको ज्यादा तेजी से चलाने के लिये मैं यह सुझाव दे रहा हूं । 19 सैक्टर में काफी देर पहले लोगों ने प्लाट के पैसे

जमा करवा दिए हैं और डिमारकेशन की जा रही है लेकिन अभी तक प्लाट्स नहीं दे सकी । मैं सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी डिमारकेशन करवाकर लोगों को प्लाट दिए जाए । अगर कोई अड़चन हो तो जो पैसा उन से लिया है उस पर कम से कम सूद ही दे दिया जाए । वह दरम्याना तबका है, गरीब है, या तो उनको प्लाट दे दिए जाएं या उनकी रकम का सूद दे दिया जाए ।

अगली बात यह है कि शॉप–ऐक्ट को पूरी तरह लागू' किया जाए । संडे को दुकानें पूरी तरह से खुली होती हैं और लेबर इनपैक्टर के पास इतना टाईम नहीं होता कि सारी दुकानों को चौक करे । मैंने देखा है कि 50 परसैटं दुकाने संडे वाले दिन खुली रहती हैं ।

मैं सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि एक शाप–इन्स्पैक्टर और होना चाहिए । इसके इलाया फरीदाबाद में एक. ही लेबर कोर्ट है । काम ज्यादा है इसलिए एक की बजाए दो लेबर कोर्ट की जाएं ।

स्पीकर साहबो फरीदाबाद में रीहैबिलिटेशन के लिए सैन्ट्रल गवर्नमेंट की जमीन है । जब तक वह जमीन स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं आ जाती तब तक वाटर सप्लाई और सैनिटेशन में तेजी से तरक्की नहींहो सकती । पंडित चिरंजी लाल जी एक दो मीटिंग्ज में भाग ले चुके हैं लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला ।

मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस जमीन को ले ले ताकि सैनिटेशन और वाटर सप्लाई का काम तेजी से हो सके ।

एक बात मैं सोशल वैल्फेयर के बारे में कहना चाहता हू । वहां पर बैगर हाउस है । उसका स्टाफ तो पूरा है लेकिन बैगर्ज नहीं है । जो बैगर्ज हैं वे मंगल और शनिवार के दिन मार्किट में घूमते रहते हैं । मैं सरकार से कहूंगा कि सोशल वैल्फेयर और पुलिस' डिपार्टमैंट आपस में कोआर्डिनेशन करके बैगरी–एक्ट के तहत ज्यादा से ज्यादा बैगर पकड़े और उन से काम लें ताकि वे बाजार में मांगते न फिरें । इसके इलावा फरीदाबाद के सेवा सदन भवन की बाउंडरी–वाल टूटी हुई है जिसकी वजह से उसमें चोरियां होती हैं । इसलिए सरकार उस बाउंडरी–वाल को बनवाए ताकि उस में रहने वाली औरतें सुख का सांस ले सकें ।

हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो आफिस हैं उन का शनिवार को खुलने का टाईम अलग अलग है । एस० डी० ओ० औररू एक्स०ई० एन० का आफिस शनिवार को खुलता है जबकि चण्डीगढ और एस० इ ० के आफिस बन्द रहते हैं । या तो सारे बन्द रहें या सारे खुलें । अलग अलग समय पर खुलने से काम में रुकावट पड़ती है । इसलिए सरकार से प्रार्थना है कि या तो सब दफतर शनिवार को खुलें या बन्द हों, एक ही नीति अपनानी चाहिए । इसके इलावा वहां एक झाडसेतली गांव है जिसमें बिजली के कुनैक्शन–घर की लाईट के लिए, स्ट्रीट की लाईट के लिए

और एग्रीकल्चर के लिए जो बिजली देते हैं उसका कुनैक्शन एक ही है जिससे कई बार ब्रेक–डाउन हो जाता है । इसलिए घर की लाईट के, स्ट्रीट लाईट के और एग्रीकल्चर लाईट के कुनैक्शन अलग अलग कर दिए जाएं । रात को वैसे ही वोल्टेज कम हो जाती है, इसलिए उसकी वोल्टेज भी बढ़ा दी जाए।

जहां तक इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है, अब सब चीजों का आराम हो गया है । हिन्द सरकार का और हरियाणा सरकार का बहुत अच्छा स्टाफ है जिन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी । लेकिन स्टीम–कोल की बड़ी तकलीफ है । स्टीम कोल हर फैक्टरी में बड़े खुले दिल से देना चाहिए ताकि लेबर फले फूले ।

स्पीकर साहब, फरीदाबाद मार्केट कमेटी के बारे में कहा जाता है कि उसकी बड़ी आमदनी है । ठीक है आमदनी है लेकिन ओल्ड फरीदाबाद, एन० आई० टी० की सब्बी मदनी और अनाज मण्डी की हालत बहुत खराब है । इस पर ज्यादा खर्च किया जाए और लिंक रोड्ज कुनैक्ट करके इसकी हालत को सुधारा जाए । बहां परएक एक्स–सैनिक सोसायटी है जो कोआप्रेटिव बेसिज पर चल रही है । उसके दो हजार के करीब मेम्बर हैं जिसमें ज्यादा तर एक्स–सर्विस मैन हैं । ये सब गरीब आदमी हैं इन से पैसा इकट्ठा करके सोसायटी ने 20 लाख रुपये की जमीन खरीदी और कहा कि प्लाट देंगे । सोसायटी ने पैसा खर्च कर दिया जमीन खरीद ली और ये गरीब आदमी पिछले छः साल से तड़प रहे हैं, न उनको प्लाट देते हैं और न पैसा । उन दो हजार मैम्बरों ने

अपने खून पसीने का पैसा दिया है, या तो सरकार उनको कानूनी ढंग से प्लाट ले कर दे या उस जमीन को एक्वायर करके मेम्बरों का पैसा वापिस करे । मैम्बर पिछले छ साल से तड़प रहे हैं, सोसायटी पर एक्शन लिया जाए और गरीब एक्स–सर्विस मैन के खून पसीने की कमाई को वापिस करवाया जाए ।

इसके इलावा फरीदाबाद में एक कंज्यूमर स्टोर है जिस पर साढ़े तीन लाख रुपया खर्च हुआ है लेकिन उसका प्रौफिट बहुत कम है । इसकी पेपर पर इन्कवायरी हो रही है और मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस केस को जल्दी से जल्दी फानेलाइज किया जाए और जिस व्यक्ति ने गड़बड़ की है उस पर रिस्पासिबिलिटी फिक्स की जाए ।

टूरिजम डिपार्टमैंट ने हरियाणा के अन्दर बहुत शानदार काम किया है । टूरिजम डिपार्टमैंट ने हरियाणा को सारे भारत में चमकाया है । मैं एक बात और आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि फरीदाबाद ओल्ड में जो एक तालाब है, सरकार उसकी तरफ ध्यान दे और उसे तालाब से लेक बना दिया जाए ताकि लोग फायदा उठा सकें । बडखल लेक से सिर्फ दिल्ली वाले धनवान लोग ही फायदा उठाते हैं, गरीब लोग नहीं उठाते । इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस तालाब को लेक बना दिया जाए ।

मैं थोड़ा सा फरीदाबाद कम्पलैक्स के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । यह कम्पलैक्स 1971 में बना था इससे पहले

म्युनिसिपल कमेटी थी । वहां पर 1966 के पहले जो खोखे लगे थे उन को ही दुकानें दी जा रही हैं लेकिन जो 1971 से पहले लगे हैं उन को नहीं दी जातीं । मैं चाहता हू कि 1971 तक जितने भी खोखे लगे थे उन सब को दुकानें दी जाएं इससे 20 सूत्रीय कार्यक्रम को ताकत मिलेगी । 1966 से पहले के जो खोखे हैं उन को दुकानें दी जाती हैं और बाकियों को उजाड़ दिया जाता है । इसके इलावा रेढी वालों को लाइसैसं नहीं दिए जाते बिजनैस बढ़ाने के लिए जरूरी है कि रेढी वालों को लाईसैसं दिए जाएं । अगर लाईसैंस नहीं मिलते तो इससे एक तो टैक्स का नुक्सान होता है और दूसरे 20 सूत्रीय कार्यक्रम को नुक्सान पहुंचता है । 20 सूत्रीय कार्यक्रम को समझना चाहिए और जो लाइसैसं मांगे उसको देना चाहिए ।

स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि जहां जहां लोकल बाडीक का स्टाफ कम है वहां भेजते हैं । फरीदाबाद ओल्ड के लिए एक थर्ड एड– मिनिस्टेटर की जरूरत है । उसके फण्ड्ज रिजर्व हैं, सरकार वहां एक एडमिनिस्ट्रेटर भेज दे । मैं एक बार फिर बिल की हिमायत करता हूं कि हरियाणा सरकार बढ़े अच्छे ढंग से शानदार काम कर रही है, इसमें कोई कमी नहीं । कोई भाई इसकी नुक्ताचीनी न करे बल्कि सुझाव के रूप में अपने ख्यालात सदन में रखे तो ठीक रहेगा ।

श्री जोगी राम (राजौंद) : स्पीकर साहब, मैं सदन के सामने प्रार्थना करूंगा कि जो हमारे अपोजीशन के भाई नुक्ताचीनी करते हैं, वे बेमायनी करते हैं । (व्यवधान)

Mr. Speaker : No interruptions. Let him speak.

श्री जोगी राम : हमारी स्टेट में बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत तरक्की हुई है और आगे भी होनी चाहिए । स्पीकर साहब, बहुत सी दूसरी स्टेटों में मैं भी गया और मैंने देखा कि उन सब स्टेटों में हमारा हरियाणा सोने की चिडिया है । 1966 से पहले, हमारा हरियाणा हर स्टेट से पीछे था और पिछड़ा हुआ था और अब सब से आगे है । स्पीकर साहब, मैं सदन का ज्यादा समय न लेता हुआ यही प्रार्थना करूंगा कि बहुत से लोग कहते थे कि हर जगह सड़कें नहीं पहुंची, यह नहीं हुआ वह नहीं हुआ । मैं कहता हूं कि हरियाणा में बहुत तरक्की हुई है, हर एक जगह सड़के पहुंची हैं, हर जगह पक्की नहरें पहुंची हैं जिससे जमींदार को, किसान को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है । पहले नहरें पक्की न होने के कारण कट जाती थीं और जमींदार को पानी का बड़ा नुक्सान होता है । स्पीकर साहब, पक्की नहर होने से किसानों और जमींदारों को बड़ा फायदा है । मुझे खुशी है कि हमारी सरकार और हमारा मंत्रिमंडल मिलजुलकर अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है । स्पीकर साहब, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी प्रधान मन्त्री जी ने जो बीस सूत्री कार्यक्रम रखा है उससे हर आदमी को फायदा पहुंचा है, हर गरीब को लाभ

पहुंचा है । स्पीकर साहब, आपके द्वारा मेरी सरकार से एक छोटी सी डिमांड है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट जींद के अन्दर एक शुगर मिल अगर लग जाए तो उससे वहां के जमींदारों को बड़ा फायदा पहुंचेगा । वहां बहुत अच्छा गन्ना होता है । मेरी सरकार से यी भी प्रार्थना है कि गन्ने की अच्छी कीमत . किसान को मिलनी चाहिए ।

स्पीकर साहब, हमारे अपोजीशन के भाई फिजूल ही नुक्ताचीनी करते रहते हैं । (विघ्न) हूं तो मैं भी अपोजीशन में लेकिन हम तो हमेशा गवर्नमैंट का साथ देते रहे हैं और देते रहेगे । (सरकारी बैचों से तालियां) हमारे पिता जी ने पहले गवर्नमैंट का बहुत साथ दिया । मैं मानता हूं कि शुरू में मैंने गवर्नमैंट का साथ नहीं दिया लेकिन बाद में मैंने भी पूरी तरह से इनका साथ दिया । शुरु शुरु में हम नए नए पालिटिक्स में आए थे, हमें सारी बातों का पता नहीं था । जिस प्रकार बकरी के बच्चे को हरी डाली दिखा कर पीछे लगा लेते हैं इसी तरह से अपोजीशन पार्टी के लोगों ने भी नुक्ताचीनी करके हमें पीछे लगा लिय था । लेकिन अब हमें सब बातों का पता लग गया है और हम इनकी बातों में नहीं आते । स्पीकर साहब, मैं ज्यादा टाईम न लेते हुए आपसे माफी चाहता हूं । (सदस्य बोलने के लिए खडे हुए)

श्री अध्यक्ष लाला गौरी शंकर : (विघ्न) ये न गवर्नर ऐडैरस पर बोले हैं, न बजट पर बोले हैं और न डिमांडज पर बोले हैं ।

लाला गौरी शंकर (नरवाना) : आदरणीय स्पीकर.साहब, हमारे फाईनैन्स मिनिस्टर साहब ने जो ऐप्रोप्रिएशन बिल पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार का जो बजट इस दफा है वह बहुत अच्छा है और बहुत लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए फायदामन्द है क्योंकि यह हरियाणा की तरक्की के लिए बहुत अच्छा है । मैं इसका अनुमोदन करते हुए थोड़ी सी बातें स्पीकर साहब, अपने हल्के के बारे में कहना चाहता हूं । स्पीकर साहब, दो तीन साल से हुमारे ऐग्रीकल्चर सैक्टर में जो बीज आता है वह अच्छी क्वालिटी का नहीं आता । पता नहीं कहां से उसे खरीदते हैं । मिसाल के तौर पर दो तीन साल से बाजरे का जो सीड सप्लाई होता है वह बहुत नाकाम है, उसकी पैदावार कुछ भी नहीं हई । उससे सीटा सा निकल आता है और फूल बिगड़ जाते हैं । जिस कम्पनी से वह खरीदा गया है, चाहे वह सरकारी है या प्राईवेट है, उसके खिलाफ ऐक्शन होना चाहिए । इसके अलावा कुछ ब्लौक लेवल के कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी शिकायत मेरे नोटिस में आई है । वे लोग वहीं से कुछ बीज लेकर इसमें मिलाते हैं जिससे उसकी पैदावार जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं होती । इस बात की पूरी तरह इन्क्वायरी की जाए कि दरअसल यह किसकी खामी है । इसके ऊपर ध्यान देकर आगे के लिए इसका पूरा इन्तजाम किया जाए ।

एक बात, इरीगेशन के मुताल्लिक भी, स्पीकर साहब आपकी मारफत मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं । हमारे यहां मुदड़ी से लेकर क्लैथ तक सारे एरिया में सेम आई हुई है । इसके लिए मैंने पहले भी सरकार से आपके द्वारा प्रार्थना की थी लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । वहां पर यदि डई ट्यूबवैल्ज लगाए जाएं तो उनसे उस एरिया को ज्यादा पानी मिल सकता है क्योंकि नरवाना तहसील में खारे पानी की वजह से दूसरे लिऊबवैल्ज कामयाब नहीं हुए हैं । इसके अलावा स्पीकर साहब, मेरी आपके द्वारा सरकार से यह प्रार्थना है कि दमतान रजवाहे में पानी बढ़ा कर खरल माईनर, भौलखेडी माईनर और पीपलथा माईनर को ऐक्सटैन्ड किया जाए ताकि नरवाना तहसील में पानी की जो कमी है उसको दूर किया जाए । सर्वे करके इस पर जल्दी से जल्दी गौर किया जाए ताकि हमारे जो किसान भाईयों को पानी की दिक्कत है वह दूर हो ।

एक बात थोड़ी सी, स्पीकर साहब, मैं और अर्ज करना चाहता हूं । हमारे मुख्य मैली जी ने एक बात कही कि साहूकार के कर्जे से कई कई साल तक पिस कर लोग अब उसमें से निकल रहे हैं । मुख्य मन्त्री जी की बात तो ठीक है लेकिन इसके मुताल्लिक थोड़ी सी वातावरण की बात मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं । दरअसल बात यह थी पहले जिस वक्त यह लेन देन का सिलसिला था, हमारे अनाज की कीमतें जो थीं वह एक रुपये मन, बारह आने मन और चौदह आने मन थीं । इसके कारण

जमींदार की आय बहुत कम होती थी । मिसाल के तौर पर कोई जमींदार अगर 100 मन अनाज भी पैदा करता था तो उसकी आमदनी केवल सौ रुपये होती थी । इसमें से 80 रुपये तो उसके मामले में ही चले जाते थे । केवल बीस रुपये उसके पास बचते थे जिससे वह अपना कोई भी खर्च पूरा नहीं कर सकता था । इसके लिए उसे मजबूरन इधर उधर से सौ दो सौ रुपये कर्ज के रूप में लेने पड़ते थे । वापस न करने की वजह से यह बढ्ता रहता था । इस कर्जे का दूसरा कारण स्पीकर साहब यह था कि पहले कोई बैंक नहीं थे । न कोआप्रेटिव बैंक्स थे और न ही दूसरे वैक्स थे ।

पुश्तों से वे साहूकारों से कर्जा लेते आए थे । ऐसी कोई बात नहीं थी जो साहूकार की बेईमानी की वजह से या और बात करने की वजह से वे कर्जे खत्म नहीं होते । असल बात यह है कि एक तो उनकी आमदनी बहुत कम थी और सूद की वजह से वे बढ़ते रहते थे । मैं यह मानता हू कि एक आध परसैन्ट बेईमान आदमी सब जगह होते हैं लेकिन इससे सारी कौम पर बेईमानी आने की बात नहीं है ।

स्पीकर साहब, एक बात इंडस्ट्री के मुताल्लिक भी आपके द्वारा मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं । आज सरकार की जितनी भी आमदनी है वह सरकार को 80 परसैंट से भी ज्यादा टैक्स के रूप में मिलती है । जितनी भी आमदनी होती है उसमें से 55 परसैन्ट टैक्स के रूप में चली जाती है 45 परसैन्ट

इनडिविजुअल को चली जाती है, इस 45 परसैन्ट में से भी कुछ टैक्स वगैरह और लग जाते हैं । मुश्किल से 20 परसैन्ट आमदनी उसके पास रहती है । 80 परसैन्ट अपने कारखाने की कमायी का हिस्सा सरकार को देता हैं । हमारी सरकारी इन्डस्ट्री कभी भी इतनी कमायी नहीं देती है । सरकार की काफी इन्डस्ट्री कोआपरेटिव सैक्टर में लगी हुई है और सरकार और इन्डस्ट्री भी लगाने जा रही है लेकिन वे इतना मुनाफा कमा कर नहीं देती हैं जितना प्राइवेट सैक्टर वाली इन्डस्ट्री कमा कर देती हैं । इसलिए मैं सरकार से अर्ज करना चाहता हं कि जितनी कोआपरेटिव सोसाइटीज की या गवर्नमैंट की इन्डस्ट्री हैं वे इतनी कमायी नहीं देती हैं, उनको बढ़ावा देने की बजाए प्राइवेट इन्डस्ट्रीज को दिया जाये ताकि सरकार को अधिक आमदनी हो सके । ऐसा करने से लोगों को भी ज्यादा काम मिलेगा । हर जिले में और सब डिविजनल लैवल पर एक एक या दो दो बड़ी इन्डस्ट्रीज होनी चाहिए । जब तक बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज नहीं होंगी तब तक स्माल स्केल यूनिट कामयाब नहींहो सकती । हमारे यहां फरीदाबाद में स्माल स्केल इन्डस्ट्री क्यों कामयाब हैं क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज लगी हुई हैं, उनके साथ छोटी इन्डस्ट्री भी पनप सकती है । मैं फिर अर्ज करूंगा कि सब डिविजनल लेवल पर और जिला लैवल पर बड़ी इन्डस्ट्री जरूर लगायी जायें ताकि छोटी इन्डस्ट्रीज कामयाब हो सकें ।

स्पीकर साहब, मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि जो पुराने खागड और झोटे की नसल है वह बिल्कुल खराब है । उनको जल्दी से जल्दी खस्सी करा कर नयी नसल के झोटे खागड गांवों में छोड़े जायें ताकि अच्छी नसल के पशु पैदा हो सकें ।

दूसरे हमारा जो कोआपरेटिव डिपार्टमैंट है, उसका जो काम है वह पूरी तरह से पूरा नहीं कर रहा है । आज तक किसी भी कोआपरेटिव सोसाइटी ने कोई भी मुनाफा नहीं दिया । हमारे यहां नरवाना कोआपरेटिव सोसाइटी ने 6 लाख रुपये का गबन किया है लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ । जितने आपके यहां सुपर बाजार हैं उनसे भी कोई फायदा नहीं हुआ है । आज तक किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी फायदा नहीं हुआ है । तो इन कोआपरेटिव सोसाइटीज को और सुपरबाजारों को अच्छे ढंग से रिओर्गेनाइज किया जाये । जितने भी बेईमान आदमी हैं उनको इनसे निकाला जाये ।

हमारे यहां पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है । लोन, हरनाम सिह कला गांवों में बहुत हों कडुवा पानी है । इसलिए वहां पर पीने के पानी का प्रबन्ध किया जाये ।

दूसरे हमारे यहां सड्कों की भी बड़ी दिक्कत हैं । हमारे यहां. कालन्द से टुहांना और खरडूवाल से सैमान । इन सड़कों का बनना बहुत ही जरूरी है । कुछ तो सड़क बन चुकी है

लेकिन तीन मील का टुकड़ा बाकी पड़ा हुआ है । यह टुकड़ा बनाना बहुतही जरूरी है क्योंकि सारे इलाके के लोगों को मंडी में जाने में चक्कर लगा कर जाना पड़ता है । नरवाना, टोहाना जाने के लिए 1 5– 20 मील का चक्कर लगा कर जाना पड़ता है । इसलिए. इन सड़को को जल्द से जल्द बनाया जाये । चौधरी शिव राम वर्मा अध्यक्ष महोदय.. मरा तो आपने नाम भी लिया था और यह कहा था कि टाईम मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष : टाईम के बारे में तो मैंने पहले ही कहा था कि मेम्बर साहिबान जरूरत से ज्यादा टाईम ले गये हैं । बिजनैस एडवाइजरी कमेटी ने अप्रोप्रियेशन बिल पर डिस्कशन के लिए दो घन्टे मुकर्रर किये थे और हाउस ने वह रिपोर्ट एडोप्ट भी कर ली तो आप झउद ही देख सकते हैं कि मैंने इस साइड (अपोजीशन) वालों को ज्यादा टाईम दिया है ।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, आज भी दूसरी तरफ से कुछ ऐसी बातें उठायी गई, जिनका जवाब देना मेरे लिए जरूरी हो गया । जहां तक मेरे काबिल दोस्त चौधरी रिजक राम जी का प्रश्न है या तो वे इन सब बातों को समझते नहीं, यदि समझते हैं तो जानबूझ कर ये सब बातें कहते हैं । जहां तक पहली बात का सम्बन्ध है उसमें तो मैं विश्वास नहीं करता कि उनको जानकारी नहीं है । मैंने पहले भी अर्ज की है कि वे सयानपत (सोनीपत) के रहने वाले हैं स्याने आदमी हैं इसलिए जानते तो सब बांतें हैं । दूसरी बात हो सकती है कि वे

जान–बूझ कर कुछ बातें कहना चाहते हों या तो इसलिए कि वे विपक्षी दल के नेता हैं, कुछ न कुछ बातें कहनी ही हैं और सिर्फ नुक्ताचीनी के लिए कह देते हैं । खैर यह तो उनकी अपनी समझ हद कि वे किस दृष्टिकोण से कहते हैं, किस उद्देश्य को लेकर ये सब बातें कहते हैं परन्तु मेरा निवेदन यह है कि जहां तक उत्तराधिकारी बिल का प्रश्न है उसके बारे में मैंने पहले भी जवाब दिया था कि हम अपने विधायक दल में इस पर गम्भीरता के साथ विचार करेंगे । (तालियां) मैं यह भी सदन के नोटिस में लाना चाहता हूं कि एक बार पहले भी हरियाणा सरकार ने उत्तराधिकार बिल में कुछ संशोधन का सुझाव स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजा था परन्तु उन्होंने स्वीकृति प्रदान नहीं की । इसलिए वह संशोधन हम नही कर पाये, इसके बावजूद भी हम इस पर पुनरू विचार करेंगे और केन्द्रीय सरकार के साथ इस बारे में विचार–विमर्श करेंगे । जो भी आवश्यक संशोधन है, हम किसान के हित में, करने की पूरी चेष्टा करेंगे । (तालियां)

' जहां तक कर्जों की वसूली का सवाल है और उसेंके लिए जमीन ' बेचने की बात है इसके बारे में जैसा कि चौधरी रिजक राम जी ने अभी जिक्र किया कि कर्ज की वजह से लोग जमीनें बेच रहे हैं, मैं ऐसा नहीं समझता कि बैकों या दूसरी फाइनेन्शयल इक्टीच्यूशन के कर्ज चुकाने के लिए कोई किसान जमीन बेचता हो । मैं तो समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है । कभी कोई एक! दो मामले गांवों में, देहातों में हो गये हों तो मैं कह

नहीं सकता । हां यह ठीक बात है कि जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होती जा रही है । उसके अनेक कारण हैं जिनकी चर्चा चौधरी साहब ने भी की थी और मैंने भी जिक्र किया था ।

एक बात चौधरी रिजक राम जी ने पहले भी कही थी और उस रोज जब मैं अपनी बात सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा था तो उस बात को टच करना भूल गया, वह बात हए आपात स्थिति के सम्बन्ध में । अध्यक्ष महोदय, चौधरी रिजक राम जी ने फरमाया कि शरीफ आदमियों के खिलाफ झूठे केसिज बनाये जा रहे हैं और जो समाज का बैड एलीमेंट है उनसे शहादतें दिलवायी जा रही हैं । अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल गलत है ऋ निराधार है । किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी झूठा केस कम से कम हरियाणा प्रदेश में नहीं बनाया जाता है । (तालियां) किसी भी केस का कोई आधार होता है, उसका कारण होता है जिसकी वजह से मजबूर हे कर उस आदमी पर हाथ डालना पड़ता है । आज सारे हरियाणा प्रदेश में जिसकी आबादी एक करोड़ 1 3 लाख के करीब बतलायी जाती है, कुल 500 के लगभग लोग जेलों में बन्द हैं । आपात स्थिति लागू हे के पश्चात इतने लोगों को बन्द किया गया है इनमें कुछ पोलिटिशन भी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, विरोधी दल के कार्यकर्ता हैं और समाज विरोधी तत्व भी शामिल हैं ।

एक बात मैं साफ तौर पर अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि जब प्रधान मती जी ने आपात स्थिति इस देश में

लागू की तो आम जनता ने इसका भारी स्वागत किया । (तालियां) अध्यक्ष महोदय आप भी देहातों में जाते हैं और हम भी जाते हैं, लोग आज की स्थिति से कितने प्रसन्न हैं, कितने खुश हैं, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है । जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि आपात स्थिति क्यों लागू करनी पड़ी इसका सब से बड़ा कारण बार बार हमारी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे दूसरे नेताओं ने और हमने भी जगह जगह बताया है कि आपात स्थिति लागू होने से पहले देश की क्या स्थिति थी । जैसा कि अभी चौधरी रिजक राम जी ने फरमाया था कि बुनियादी अधिकारों पर छापा मारा गया । बोलने लिखने की स्वाधीनता खत्म की गई, तो अध्यक्ष महोदय आपात स्थिति का यी उद्देश्य नहीं है । बात दरअसल यह है कि लिखने और बोलने की आजादी का इतना भारी दुरूपयोग हुआ, इतना भारी गलत इस्तेमाल हुआ कि जिसकी कोई सीमा नही रही, उसकी कोई हद नहीं रही । आप अखबार उठाकर देख लीजिये । कितनी गलत बातों को प्रकाशित किया जाता था । लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था । छोटे–छोटे कस्बों और छोटे–छोटे शहरों में बीस–बीस, तीस–तीस वीकली अखबार नये निकलने शुरू हो गये और उनका धन्धा केवल यह था कि लोगों को धमकी दी जाये और उनसे पैसा ऐन्ठा जाये । मेरी व्यक्तिगत जानकारी में कुछ मामले ऐसे हैं कि किसी व्यक्ति का किसी ठेकेदार का, किसी अफसर का, किसी कारखानेदार का थोड़ा सा जिक्र एक अंक में कर दिया और यह लिख दिया कि इसका पूरा विवरण अगले अंक में पढ़िये और अगला अंक प्रकाशित होने से

पहले ही उनकी पूजा हो जाती थी और वह चीज समाप्त हो जाती थी । और अगर पूजा नहीं होती थी तो शरीफ आदमियों की पगड़ी उछाली जाती थी यह तो छोटे–छोटे पत्रों की बात है । जो बड़े–बड़े पत हैं और जिस (प्रेस) पर पूंजीपतियों का अधिकार है, यदि आपात स्थिति से पहले का आप कोई उनका एव उठाकर देखे तो पता चलेगा कि इतना अनुचित ट्रैन्ड उन लोगों का था कि उस बात को कोई सहन नहीं करसकता । अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहता हूं कि हमारी प्रधान मन्त्री जी, हमारी कांग्रेसी सरकार, जनतनत्र में बड़ा भारी विश्वास रखती हैं, इतने सालों तक उन्होंने इतनी बेहूदा बकवास को सहन किया । यह बात तो तब करनी पडी जब देश में लोकतन्त्र को खतरा पैदाहो गया, देश की आजादी को खतरा हो गया और इस बोलने और लिखने की आजादी का इतना ज्यादा दुरूपयोग हुआ कि उसकी कोई सीमा नहीं रही । विपक्षी दल के बोलने वाले भाई क्या भाषण देते थे अध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब को भी मालूम है कि उनमें कितनी सही बातें होती थीं और कितनी गलत बातें होती थीं । इस प्रकार की गलत बातें कही जाती थीं कि जिनका कोई आधार नहीं था । अध्यक्ष महोदय, आपको तो पता है कि ऐसी–ऐसी गलत बातें बीसों माल तक इस देश के अन्दर चलती रहीं, लोगों को भडकाया गया, उकसाया गया, लोगों कोहिमा केलिये और तोड़–फोड़ के लिये उकसाया गया । यह बातें सारे देश के अन्दर हुई । तमाम देशके वातावरण को दूषित करने के लिये और देश में हिंसा का वातावरण तैयार करनेके लिये कोई कमर नहीं उठा रग्बी गयी और

उसी के नतीजे के तौर पर मजबूर होकर आपात स्थिति लागू करनी पड़ी । आपात स्थिति लागू करने के पश्चात् आज आप देखतेहैं कि तमाम देश का वातावरण बदल रहा है, एक अनुशासन का वातावरण पैदा हो– रहा है । आज के युग के और इस समय के महान सन्त बिनोवा जी ने भी यह कहा है कि यह आपात स्थिति नहीं, यह तो अनुशासन पर्व है । (थम्पिग) तो इस आपात स्थिति लागू करने से इस देश का कितना लाभ हो रखा है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं । आज हमारे कालेजों और स्कूलो में ठीक ढंग से शिक्षा चल रही है । हमारे जो बच्चे हैं, वे आराम से शिक्षा प्राप्त करते हैं । पहले क्या होता था. रोज नारेबाजी । हमारे ये जो विरोधी दरर के भाई हैए, हमारे उन दूध–मुहं बच्चों के कन्धों पर बन्दूक रखकर चलाते थे, नेतागिरी खुद करतेथे, राजनैतिक स्वार्थ सिदधु खुद करते थे लेकिन उन भोले–भाले बच्चों को आगे करदेते थे । मैंने वह दर्दनाक सीन अपनी आंखों से देखा है । भिवानी वैश्य कालेज के अन्दर जब यहां सूबा–ऐजीटेशन चल रही थी तो हमारे इन विपक्षी दल के भाइयों ने कालेज के लड़कों को भडकाया, उनमें इतनी आग भर दी कि वह सब कुछ तोड़–फोड़ करने को तैयार हो गये । डाकखाना जला दिया, तार घर को आग लगा दी, तहसील को आग लगा दी, एस० डी० ओ० के आफिस को जला दिया और उसके बाद जब गोलाबारी शुरू हुई, पुलिस को मजबूर होकर ला एण्ड आर्डर को बनाये रखने के लिये जब बन्दूक उठानी पड़ी तो वे तमाम लीडर भाग गये और निशाना कौन बना ? एक गरीब

किसान का बेटा जो अपने मां–बाप का इकलौता बेटा था । उसके मां–बाप की आंख के आंसू आज तक सूख नहीं पाये । तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसी हालत इस देश के अन्दर इन लोगों ने बना रखी थी । आज कालेज भी चलते हैं, स्कूल भी चलते हैं, पढ़ाई भीठीक ढंग से होती है, कारखानों मेंकोई हड़ताल नहीं, कोई तालाबन्दी नहीं, प्रोडक्शन खूब हो रही है, रेलों में हड़ताल नहीं, बिजली के महकमे में कोई हड़ताल नहीं यानी किसी प्रकार का न रगड़ा और न झगड़ा । सारे लोग खुश, सारा देश खुश और भगवान भी खुश । भगवान ने भी खुश होकर इस बार अच्छी बारिश की है । आज सारे देश कें–अन्दर शान्ति है । अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसके बावजूद भी, अगर इस आपात स्थिति के लागू करने से किसी को तकलीफ हुई है तो वे मुट्ठी भर लोग हैं । इनमें कुछ तो वे आदमी हैं जो यह चाहते हैं कि जायज नाजायज, देश के हित में, देश के अहित में, कुछ भी करते हुए, किसी प्रकार कुर्सी मिल जाये और वे उसके लिए प्रयत्नशील थे । चाहे उन्हें गलत बात कहनी पड़े, चाहे हिंसा का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे देश को भडकाना पड़े, चाहे प्रोडक्शन में बाधा हो या किसी प्रकार का संकट पैदा हो लेकिन उन्हें कुर्सी अवश्य मिले । तो, कुछ तो वे लोग परेशान हैं या फिर वे परेशान हैं जो बैड एलीमैंट्स हैं, समाज–विरोधी तत्व हैं–जों दूसरों की कमाई पर छापा मारकर फायदा उठाते थे, क्योंकि उनके घरों पर छापे पड़े, वे पकड़े गये, मीसा में गिरफ्तार हुए, तरह–तरह की उनके खिलाफ कार्यवाही हुई । दो तरह के ही आदमी आज इस

आपात स्थिति में परेशान हैं और इन दो प्रकार के आदमियों की गिनती आप अगर अन्दाजा लगायें तो मैं समझता हूं कि सारे देश में 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है । (विध्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि 95 प्रतिशत मानता इतनी संतुष्ट है, इतनी प्रसन्न है, इतनी खुश है कि जिसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता । चौधरी साहब पिछली दफा बोलते हुए यह कह रहे थे कि ऐसी स्थिति को नौजवान बर्दाश्त नहीं करेंगे । मैं चौधरी साहब को दावत देता हूं कि वे मेरे साथ चलें और खुद देखें कि नौजवान आज की स्थिति में हमारे साथ हैं अथवा उनके साथ । (विध्न) मैंने तो बार–बार कहा है और हमारी प्रधान मंत्री ने भी बार–बार एलान किया है कि जो लोग अन्दर बन्द हैं यदि वे अपने विचार बदलें तो फिर हम उनको बाहर निकालगें के लिये तैयार हैं । भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करे, उनके विचार ठीक हों । तो फिर उनको अन्दर रखने की आवश्यकता नहीं । (विध्न) जहां तक नौजवानों का प्रश्न है, मैं चौधरी साहब को दावत देता हूं, मैं उनको नौजवानों के अन्दर अपने साथ लेकर चलता हूं (विध्न) नौजवान कभी डरता नहीं है । डर से कभी कोई ऐजीटेशन आज तक दुनिया के अन्दर दबी नहीं । मैं यह समझता हूं कि जितना डर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का था, उतना डर आज नहीं हो सकता और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का आंतक होते हुए भी कभी नौजवान डरते नहीं थे । भगत सिंह जैसे फांसी पर झूल गये और हमारे जैसे गोली और लाठी के सामने सीना तानकर खड़े होते थे (थम्पिग) लाठी से कोई आन्दोलन नहीं दब सकता, प्रैशर से कोई

आन्दोलन नहीं दब सकता, आन्दोलन वही दबता है जिसको जनता का समर्थन प्राप्त न हो । यह जो आन्दोलन था, यह सिर्फ नेताओं का आन्दोलन था और यह सिर्फ कुर्सी केलिये था इसलिये यह आन्दोलन उभर नहीं पाया? यह आन्दोलन या तो कुर्सी के लिये था या फिर समाज विरोधी तत्व उनके पीछे थे या फिर विदेशी शक्ति इनके पीछे थी, वह हर प्रकार के फरेब इस्तेमाल करती थी और उनके हाथ में कठपुतली बनकर वे देल का सर्वनाश करने पर तुले हुए थे । यह ऐसे लोग थे जिन्होंने सारे देश के अन्दर विध्वंसक वातावरण पैदा किया । अब बिल्कुल आराम से देश चलता है, सुख है, शान्ति है । नौजवान, मजदूर, किसान यानी कि हर प्रकार के वर्ग का पूरा समर्थन इस आपात स्थिति को प्राप्त है । मैं यह बात दावे के साथ और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं । चौधरी साहब, ने पिछले दिनों किसान के दु:ख की बात कही थी आज इन्होंने मजदूरों के दु:ख की बात कही है । मजदूर के लिए इनके दिल में बहुत ज्यादा दर्द है । यह कहते हैं कि बोनस की परसेन्टेज कम कर दी । अध्यक्ष महोदय, आज से दों–तीन साल पहले, ठीक तारीख तो मैं नहीं बता सकता 8. 33 परसेन्ट बोनस किया गया था लेकिन उससे पहले चार परसेन्ट ही था । 1973 से पहले चार प्रतिशत मिनिमम बोनस देना लाजमी था और अब फिर चार प्रतिशत कर दिया और इसलिए कर दिया कि उद्योग–धधों की तरफ भी छगन देना जरूरी था । जैसा कि चौधरी साहब ने बताया कि उद्योग–धंधे वाले बेलेन्सशीट डुप्लीकेट बनाते हैं, मुनाफे को छुपाते हैं, यह बात मैं मानता हूं । स्पीकर साहब, जो ऐसा करते

हैं उन सब पर रेड भी हुए हैं । वह रेड भी कोई बी० एल० डी० ने नहीं किया । आज जितने लोगों पर रेड हुए हैं और जितना बैड ऐलीमेंट पकड़ा गया है वह इसी सरकार ने पकड़ा है और देश के अन्दर यह कम्पैन पूरे जोर से चल रही है ऐसे समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी और ऐसे तत्वों को शान्ति के साथ नहीं बैठने दिया जाएगा । अगर आप देखें तो इस बैड ऐलीमेन्ट से जितना पैसा आप लोगों को मिलता है उसका एक प्रतिशत भी हमें नहीं मिलता । अगर आप चाहें तो मैं इसकी एक लिस्ट भी दे सकता हूं । हरियाणा प्रदेश की एक लिस्ट दे सकता हूं कि ऐसे मुनाफाखोरों से, पूंजीपतियों की तरफ से जनसंघ और बी० एल० डी० को कितना चन्दा मिलता है (व्यवधान)

चौधरी शिव राम वर्मा : आप वह लिस्ट सरकार को भी दें और दूसरी पार्टियों को भी दें (व्यवधान) ।

Mr. Speaker : Order, order please. No interruptions.

श्री बनारसी दास गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि काले धन का पैसा भी इनको ही मिलता है । बोनस का जहां तक प्रश्न है, उद्योग धन्धों की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है । यह बात मैं मानता हूंकि गल्त हिसाब किताब रखते हैं, गल्त बेलेन्सशीट बनाते हैं इन सब बातों की रोकथाम के लिए हमारी प्रधानमन्त्री ने एक और बात का एलान किया है जिसको हम बहुत तेजी से लागू करते जा रहे हैं कि मैनेजमैंट में मजदूरों का हिस्सा

हो ताकि उद्योगपति हेराफेरी न करें, गल्त बेलेन्सशीट न बनाएं । गल्त तौर पर मुनाफाखोरी न कर सकें और हमने अपने प्रदेश के अन्दर यह बात जोर से लागू करनी शुरू कर दी है । अभी कुछ दिन पहले चौधरी साहब के शहर में एटलस साइकिल के अन्दर मैंने इस स्कीम का स्वयं उद्घाटन किया और अध्यक्ष महोदय मैनेजमैन्ट के अन्दर मजदूरों को प्रतिनिधित्व दिया गया । इससे बड़ी बात अध्यक्ष महोदय और क्या हो सकती है । मजदूर अब वहां मैनेजमैंट में बैठेगा और वहां बैठकर देखेगा कि कोई गलत काम नहो ।

मिनिमम वेज की बात कही और कहा गया कि मिनिमम वेज इतना रखा है कि उससे ज्यादा तो मजदूर किसान से पहले ही ले रहा है । स्पीकर साहब, जब कटाई का सीजन आता है तो मजदूरों की बहुत कमी पड जाती है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मजदूरी देकर मजदूरों को लेना पड़ता है । चौधरी साहब, यह तो मिनिमम वेज हमने फिक्स किए हैं, ज्यादा देने पर तो कोई पाबन्दी नहीं है । अगर मिनिमम वेज पांच–दस रुपया फिक्स किया है और चौधरी साहब बीस रुपया दें तो उन पर कोई पाबन्दी नहीं है । ज्यादा देने पर तो कोई पाबन्दी है ही नहीं । इसलिए न्यूनतम मजदूरी सिर्फ उन मजदूरों के लिए ही फिक्स नहीं की जो कि खेतींमें काम करते हैं बल्कि और भी कई प्रकार के क्षेत्र हैं जहां यह न्यूनतम मजदूरी फिक्स की एं ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं पानी की बाबत कहना चाहता हूं । यह बात मैंने पहले भी स्पष्ट की और इस बात कोड़ आज फिर स्पष्ट करदेता हूं' कि जितनी नई नहरें निकाली गई हैं उन नई नहरों के लिए हम एक कतरा पानी भी दूसरे इलाके का नहीं काटेंगे । इस बइतको मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह सकता हूं । अगर चौधरी साहब, पानी की तकसीम का एक–एक दिन का हिसाब देखना चाहें तो मैं एक–एक दिन का हिसाब दिखा सकता हूं । अगर कोई और भाई देखना चाहे तो वह भी देख सकता है । अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी रिजक राम की इस बात से सहमत नहीं हूं कि क्रापिंग पैटर्न बना दिया जाए । इसका मतलब यह हुआ कि एक पंडित जी भागवत की कथा कररहे थे । उसमें उन्होंने यह कह दिया कि इस जन्म में जो औरतें हैं वह अगरने जन्म में भी औरतें ही रहेंगी और जो आदमी हैं वह अगले जन्म में आदमी ही रहेंगे । इसको सुनकर राक औरत उठकर चल पड़ी और कहने लगी कि अब सुनने का क्या फायदा जब हमारे भाग्य में चूल्हा चक्की करना ही लिखा है । चौधरी साहब, आपका मतलब यह है कि महेन्द्रगढ़ जिला में बाजरा बोया जाता रहा है तो वहां बाजरा ही बोया जाता रहे और आप गेहूं, गन्ना बोते रहे । चौधरी साहब, आज से 15– 20 साल पहले हमारे यहां यह हालत थी कि जब मेहमान कोई आ जाया करता था तो हम काख पीटते थे कि आज गेहूं के माड़ मिलेंगे । शुक्र करो भगवान का और चौधरी बंसी लाल का जिसकी कृपा से यी हो गया कि आज उस इलाके में भी गेहूं की खेती होती है । मैं तो यह चाहता हू कि जिस प्रकार

करनाल और कुरुक्षेत्र में चावल बोया जाता है, गेहूं बोया जाता है, गन्ना बोया जाता है जहां भी सम्भव होगा हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार की फसल सभी स्थानों पर पैदा करने का प्रयत्न करेंगे । जहां तक पानी का सवाल है चौधरी साहब ने आडीटर जनरल की रिपोर्ट से कुछ फिगर्ज पढकर बताई । जिस रिपोर्ट का वह हवाला दे रहे थे वह रिपोर्ट अभी अन्डर एग्जामिनेशन है । अभी हम उसको देख रहे हैं कि क्या–क्या आबजैक्शन्ज हैं, क्या–क्या आपत्तियां आडीटर जनरल ने उठाई हैं । उनका बाकायदा जवाब दिया जाएगा । मैं र'क बात बतलाना चाहता हूं जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि यह आगमेन्टेशन कैनाल बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ और पक्की नहर बनाने या पक्के खाल बनाने से सीपेज बन्द नहीं हुई । स्पीकर साहब, मैं आपके नोटिस मैं यह बात लाना चाहता हूं कि अगर आज हम ताजेवाला जो हमारी कच्ची नहर है उससे तीन–चार हजार क्युसिक पानी छोड़ तो मुनक तक पहुंचते–पहुंचते पांच सौ क्युसिक पानी कम हो जाता है सीपेज की वजह से और अगर हम पक्की नहर से छोड़ तो केंवल 25 या 30 क्युसिक पानी की सीपेज होती है । कहां पांच सौ क्युसिक और कहां 25 या 30 क्यूसिक ।

चौधरी रिजक राम : यही तो कंट्राडिक्ट किया है ।

श्री बनारसी दास गुप्त : अगर कंट्राडिक्ट किया है तो हम जवाब देंगे । हम आपको भी मौके पर ले जाकर दिखला देंगे । कहां तो पांच सौ क्युसिक ओर कहां 25 या 30 क्युसिक पानी

इस प्रकार 475 क्युसिक पानी बच जाएगा । लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं चौधरी साहब से कि उस रोज तो वह बोलते हुए वे यह आशंका महसूस कर रहे थे कि नहर और खाल पक्की होने से सब सावल पानी खराब हो जाएगा और आज यह कहते हैं कि नहर पक्की करने से सीपेज बन्द नहीं होती । मैं यह कहता हूं कि नहर पक्की करने से सीपेज बन्द होती है और उस सीपेज के बन्द होने से वाटर टेबल पर कोई फर्क नहीं पड़ता । अब सीपेज होती है तो उसका फायदा नहर और कैनाल के नजदीक के लोगों को ही होता है और जब सिपेज केवल नहरों में न होकर सारे फील्ड में होगी तो सारे इलाके को फायदा होगा । इसके अलावा एक और बात कहना चाहता हूं । चौधरी साहब ने कहा कि आग्मेन्टेशन कैनाल बनने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ, कोई पानी नहीं बढ़ा और जूई नहर निकलने के बाद यहां का पानी कट गया । स्पीकर साहब, मैं यह आंकड़े देना चाहता हूं कि किस प्रकार हमारी इरीगेशन बढ़ी है । 1970– 71 में हमारा टोटल सिचित त्रिया था 14 लाख 41 हजार एकड़ और रबी का था 851 लाख एकड । 1971– 72 में बढकर हो गया 15.09 और 922 लाख एकड । 1972–73 में कुछ कम हो गया यानी 1483 लाख एकड हो गया । शायद दरिया में पानी कम आया हो, बारिश कम हुई हो या बर्फ कम पड़ी हो । 1973– 74 में फिर बढ़कर 1684 लाख पकड़ हो गया । तो इस तरह से इरीगेशन का एरिया तो बढ़ता रहा है । अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं इरीगेशन कम हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ है, मैं कहता इंद्र बढ्ता रहा है, मेरे पास फिगर्ज हैं,

आंकडे हैं । इसके इलावा चौधरी साहब कहते हैं कि आग्मेन्टेशन कैनाल बनने से कोई फायदा नहीं हुआ, इस बारे में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं । कल 22 जनवरी, 1976 को ताजेवाला पर हरियाणा के शेयर का पानी था 2310 क्युसिक और म्यूनिक पर पहुंचा 3893 क्यूसिक, यह कहां से बढ गया ।

12.09 बजे

चौधरी रिजक राम : गल्त लिख दिया होगा ।

श्री बनारसी दास गुप्त : गल्त लिख दिया होगा तो मैं बैरीफाई करने के लिये तैयारहूं मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ यह बात कहता हूं कि अगर कोई गल्त बात है तो हम उसको वेरीफाई करेंगे, यानी कल हमारे हिस्से का पानी था 2310 क्यूसिक, म्युनिक में पहुंचा 3893 क्युसिक लेकिन इस में ।!ऋक बात जरूर हए कि इस में 990 'क्यू सिक पानी वह भी शामिल है जो एम ० बी० के० द्वारा इधर दिया गया है । अगरइमको कम कर दिया जाए तो इसके बाद भी 2903 क्यूसिक बच जाता है––विघ्न––

चौधरी रिजक राम : रि–जनरेशन का भी आता है ।

श्री बनारसी दास गुप्त : रि–जनरेशन का कितना आता है यह हिसाब तो अलग बताऊंगा लेकिन मैं एक बात बताता हूं कि अगर आग्मेन्टेशन कैनाल न होती तो म्युनिक में यह पानी 1800 क्युसिक पहुंचता क्योकि 500 सीपेज में चला जाता । वहां. से चलता 2310 क्युसिक जितना कि हमारा हिस्सा था और म्युनिक

में पहुंचता 1800 क्यूसिक और उसकी बजाये पहुंचा है 2900 क्युसिक यानी एक हजार क्युसिक पानी सिर्फ आग्मेन्टेशन कैनाल और आग्मेनटेशन ट्यूबवैल्ज की वजह से बढ़ा है जिसके बारे में चौधरी साहब यह. कहते हैं कि यह कैनाल बनने का कोई लाभ नहीं हुआ, यह बात मैं उनके सामने अर्ज करता हू (श्री रिजक. राम जी की तरफ से विघ्न) आग्मेन्टेशन टयूबवैल्ज जो इस में लगाये गये हैं उन से भी पानी बढ़ा है–

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है । जो आग्मेन्टेशन कैनाल है उसकी कुल कैपेसिटी बढ़ाने से 900 क्यू सिक की बढ़ौतरी हुई थी और अब चीफ मिनिस्टर फरमा रहे हैं कि 1000 क्यूसिक बढ़ा है बल्कि इससे ज्यादा डिपार्टमैंट ने क्लेम भी नहीं किया?

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, यह प्वांयट आफ आर्डर तो बना नहीं ।

श्री बनारसी दास गुप्त : मैं आपकी बात मान लेता हूं । कुछ पानी रि–जनरेशन से बढ़ जाता होगा लेकिन ज्यादा जो इससे फायदा हुआ है, ज्यादा जो हिस्सा है 1000 क्युसिक नहीं तो 900 क्युसिक पानी बढ़ा होगा लेकिन इतना पानी जितना इंजीनियर्ज ने क्लेम किया था और जिसके आधार पर यह स्कीम बनाई गई थी, वह पूरी तरह से कामयाब हुई है, सफल हुई है, इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं और

अधिक समय न लेते हुए आपके द्वारा इस सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि जो इलाके ऐसे हैं जो वर्ष्षो से कहत के शिकार होते रहे हैं, मरते रहे हैं जिनको यह पता नहीं था कि इन्सान की जिन्दगी कैसी होती है और चौधरी साहब व उनके साथी तो मान्डे भी उड़ाते रहे, हल्वा भी उड़ाते रहे, पूरी मौज भी करते रहे, तो हम उन कमजोर इलाके के आदमियों को उनके स्तर पर लाना चाहते हैं और लाएंगे (तालियां) उस में कोई हम पर एतराज करता रहे या कोई चीख पुकार करता रहे, इन बातों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं है । हमारा यह इरादा है कि समाज के, प्रदेश के कमजोर इलाके और कमजोर वर्ग को ऊंचा उठाएं और बराबर के स्तर पर लाएं, यह हमारी प्रधान मन्त्री जी की नीति है और इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा (तालियां)

Mr. Speaker : Order, order please. No interruptions.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will take up the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 & 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr . Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill. The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Shri Ram Saran Chand Mital) : Sir, **I** beg to move—

That the Haryana Appropriation Bill be passed.

(इस समय चौधरी रिजक राम बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब इसके लिये तो टाईम मुकर्रर था, जो पूरा हो चुका है ।

चौधरी रिजक राम : ठीक है जी, तो मैं बैठ जाता हूं ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation Bill be passed,

The motion was carried.

वर्ष 1975–76 के अनुपुरक अनुमानों (दूसरी किश्त) पर चर्चा तथा मतदान

(i) Discussion on the Estimates of the expenditure charged on the Revenues of the State.

Mr. Speaker : Those hon. Members who wish to discuss the charged items, may do so.

(No Hon. Member rose to speak).

(ii) Discussion and voting of the Demands for Supplementary Grants.

Mr. Speaker : According to the previous practice and in order to save the time of the House all the Demands for

Grants appearing on the Order Paper will be deemed to have been read and moved together. The Hon'ble Members can raise discussion on the Demands hut while speaking they will have to indicate the Demand number on which they want to raise discussion.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,45,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10,43,022 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 2—General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,59,29,670 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 3—Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 45,43,880 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 4—Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,97,10,910 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 6—Finance.

That a supplementary sum not exceeding Rs.

89,87,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 8—Buildings and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,22,29,147 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st.March, 1976 in respect of Demand No. 9—,Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 14,27,900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 11—Urban Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,81,450 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 12—Labour and Employment.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 52.89,450 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 13—Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10,66,88,430 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 15—Irrigation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 16—Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,59,77,760 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 17—Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 18—Animal Husbandry.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7,28,430 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 20—Forest.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 26,10,380 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of pay ment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 21-- Community Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 6,47,830 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 22—Cooperation.

That a supplementary sum not exceeding Rs.

8,80,760 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 24—Tourism.

That a supplementary sum not exceeding Rs 9,53,85,410 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 25—Loans and Advances by State Government.

चौधरी शिव राम वर्मा (नीलोखेडी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना तो एप्रोप्रिएशन बिल पर चाहता था लेकिन समय न मिल सका, इसलिये अब जो सप्लीमेंट्री डिमांडज की दूसरी किश्त हमारे सामने आई है, उनके बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूं । सब से पहले तो मैं डिमांड नम्बर 2 व 3 हैं इनको इकट्ठा ही लेता हुं जोकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और होम के बारे में हैं और' यह दोनों ही महकमे मुख्य मन्त्री महोदय के पास हैं ।. मुख्य मन्त्री महोदय ने 20 तारीख को बोलते हुए कुछ निराधार बातें भी कहीं थीं—

Mr. Speaker : Order please. No reference to previous speech. You should confine yourself to the discussion on the supplementary demands.

चौधरी शिव राम वर्मा अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री इसी साल का है जी, सारा, जिस पर बोल रहा हूं । मुख्य मन्त्री महोदय ने कई बातें यहां पर बोलते ' हुए कहीं । अंगूठे तो सदा ही लगते रहे लेकिन इन्होंने चूतड़ के चूतड़ शब्द भी और झूठ शब्द भी

कहे, यह उनको शोभा नहीं देते थे और मैं यह समझता हूं कि वे अन–पार्लियामेन्टरी भी थे चूतड़ इसी राज में पता नहीं लगे या न लगे होंगे–शोर–या गुप्ता जी ने कोई नया रूल निकाला होगा चूतड लगाने का, इससे पहले तो कभी सुनें नहीं थे, तो इस लिये मैं कह सकता हूं कि उनकी बातों का कोई आधार नहीं था, निराधार बातें कहीं उनको ऐसी बातें कहना शोभा नहीं देती थीं, इस बारे मैंने उस वक्त भी उनको याद दिलाया था–

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि कोशिश यह होनी चाहिये कि कोई भी लफज ऐसा जो या तो किसी आनरेबल मेम्बर को पिन्च करता हो या कोई शोभा न देता हो, वह नहीं कहना चाहिये ।

चौधरी शिव राम वर्मा : स्पीकर साहब, उस वक्त मैंनें आपको भी याद दिलाया था ।

Mr. Speaker : Nobody raised any point of order.

चौधरी शिव राम वर्मा : स्पीकर साहब, मैं एक बात जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और होम के बारे कहना चाहता हूं कि जैसे मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा कि आपात स्थिति से लोग बहुत खुश हुए हैं, आपात स्थिति से सारी बातें काबू में आ गई हैं । आखिर सरकार के पास इतनी शक्ति है, बहुमत भी इतना है कि किसी बात का कोई खतरा नहीं है, कोई कानून कैसे ही बना ले, किसी तरह उसको चला लें तौ फिर आपात स्थिति की जरूरत क्या पड़ी थी?

इसका मतलब तो मैं लेता हूं कि अपने पाप कांपते है । और इसलिये वह ठीक तरीके से चलने की बजाए दूसरा ढंग ऐसा अपनाते हैं जिससे लोगों को दबा कर रखा जाए । इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि काफी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, उनमें एक दो सही हो सकती हैं लेकिन बहुत सी गलत इलजाम लगा कर की गई हैं । अगर वह अदालत के सामने आएं तो सही पोजीशन का पता चल सकता है लेकिन वह अदालत के सामने नहीं आएगी । मैं आपको एक दिन कीघटना बताऊं कि करनाल में कुछ गिरफ्तारियां हुई–

परिवहन मन्त्री (श्री के० एल० पोसवाल) : स्पीकर साहब, मेरा प्यांयट आफ आर्डर है कि ये कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं । ये तो पुरानी स्पीच की बातें हैं ।

चौधरी शिव राम वर्मा : यह भी इसी साल में आता है । करनाल में एक घटना हुई । पुलिस हथकडियां लगा कर कुछ आदमियों को न्यायालय में पेश करने आई जो डी० आई० आर० या और किसी केस में आए थे । जब वे पेश होने के बाद अदालत से निकले तो उन्होंने नारा लगा दिया कि ''भारत माता की जय'' उसके बाद पुलिस ने उन लोगों कौ हथकडियो समेत कचहरी के अहाते में इतना पीटा कि लोगों ने दांतों तले अंगुलियां दबा लीं, इतना आतंक छा गया कि लोग सोचने लगे कि क्या यही अपना राज है या यही जनतन्त्र है । क्या फिर अंग्रेजी राज तो नहीं आ

रहा है? पुलिस वालों ने उनको बहुत बुरी तरह से पीटा और वह एक बहुत बुरा दृश्य था ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : स्पीकर साहब, मेरा प्यांवयट आफ आर्डर है कि क्या आनरेबल मैंबर साहब भी उस वक्त वहां थे और क्या उनको भी कोई जूता या लाठी लगी?

चौधरी शिव राम वर्मा : यह तो इन्होंने अपनी आदत के अनुसार कह दिया

श्री अध्यक्ष आर्डर प्लीज : यह डिस्कशन सप्लीमेंटरी डिमांडज पर है, मेन बजट पर नहीं है । इस पर वही रूल्ज लागू होंगे जो सप्लीमेंटरी डिमांडज के मुताल्लिक हैं । मैं आपका ध्यान रूल 201 की तरफ दिलाता हूं–

"The debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same and no discussion may be raised on the original grants. . .

जो इसमें आइटम है, आप उसके ऊपर बोल सकते हैं । यह नहीं कि बजट डिस्कशन फिर शुरू कर दो, बजट पास हो चुका है उसके ऊपर मैं डिस्कशन अलाऊ नहीं करूंगा ।

चौधरी शिव राम वर्मा : मैं तो केवल यही निवेदन कर रहा था कि मुख्य मन्त्री महोदय के नोटिस में अगर यह बात न हो तो उनकी जानकारी में आ जाए ।

श्री अध्यक्ष : यह तो फिर उसी तरह से चल पड़ेगी । मैंने आपको बताया किं आप जिस डिमांड पर बोलना चाहते हैं, उस डिमांड का नम्बर बताएं और उस पर बोलें ।

चौधरी शिव राम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह कहा है कि लोगों को न्याय मिलना चाहिये और आगे से ऐसी बात न हो तो किसी को एतराज नहीं होगा । इसलिये इस ओर ज्यादा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । जो गलत किस्म के लोग हैं उन्हीं को सजा मिले बजाए इसके कि जिससे किसी की दुश्मनी हो उससे ज्यादती की जाए यह अच्छी बात नहीं है । घर के अन्दर या प्रदेश के अन्दर शान्ति या अमन तभी रहेगा जब सबको न्याय मिलेगा इसलिये इसमें सरकार को पूरा सतर्क रहना चाहिये और केवल इस किस्म के लोग जो गलत प्रकार की बातें करके ही अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं उन की चालाकियों और एसे लोगों की बातों को ठीक प्रकार से सोच समझ कर ही दूसरे लोगों की गिरफ्तारी करनी चाहिये । इससे आगे चल कर मैं बिल्डिग्ज और रोडज के बारे में कहूंगा कि इसके लिये भी बहुत थोड़ी रकम रखी गई है । इसमें जो सड़कें अधूरी पडी हैं उनका नम्बर तो देर में आउगा जो पैसा है वह तो बिल्डिग्ज पर ही खर्च हो जाएगा । जिन सड्कों में मैप्स पड़े हैं वे सड़कें अधूरी पड़ी हैं उनको पूरा किया जाए । इसी प्रकार से एक सड़क तरावडी से वाया सोखडा पडवाला होती हुई रमाना रमानी गई है और वह सड़क रमाना रमानी गांव तक भी पहुंच गई है लेकिन बीच में एक

रजवाहा पड़ता है जिसका पुल बहुत पुराना बना हुआ था, आप वहां जाकर देखें और बस की बात तो छोड़िये उसको पार करने में बैल गाड़ी को भी खतरा रहता है कि वह पुल से गिर न जाए । उस पुल को जैसा कि उसका एसटीमेट बनाया गया था उसके अनुसार जल्द से जल्द बनाया जाना चाहिये ताकि रमाना रमानी गांव तक लोग आसानी वे आ जा सकें । इसी प्रकार एक बात मैं और कहूंगा कि निसंग ब्लाक में एक गांव हथलाना है और उसके पास से एक ड्रेन गई है जिसके ऊपर भी पुल का बनाया, जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वह गांव के बिल्कुल साथ है और सारा रकबा दूसरी तरफ है । बरसात के दिनों में लोगो को घास लाना भी मुश्किल हो जाता है । वह पुल कई बार कच्चा बनाया गया है लेकिन बरसात के दिनों में टूट जाता है इसलिये उसको बनाया जाना बहुत ही जरूरी है । इसी प्रकार की यूक सडक जी० टी ० रोड से भैणी खुर्द होते हुए सुलतान पुर गई है और बीच में भैणी खुर्द के पास उसका टुकड़ा कच्चा पड़ा है, वह पूरा किया जाना चाहिये । उसके बिना वह सारी सड़क बेकार पड़ी है । इसके आगे दो तीन मील पर ललियानी से तरौडी सड़क पड़ती है जो कच्ची है । इस दो तीन मील के टुकड़े के कच्चे रह जाने के कारण लोगों को 12– 13 मील का चक्कर डाल कर तरावडी मंडी में आना पड़ता है इसलिये वह सड़क ललियानी से तरोडी तक भी पूरी की जाए । मुझे पता चला है कि यह मंजूर तो हो चुकी है इसलिये इसको जल्दी पूरा किया जाए । इसी तरह से डिमांड नम्बर 9 जो शिक्षा के बारे में है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा

मन्त्री महोदय इधर ध्यान दें । शिक्षा का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि–

शिक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक): अध्यक्ष महोदय यह एक करोड़ 22 लाख रोहतक ब्निवर्सिटी के लिये हैं इसलिये इस पर इनको कोई एतराज हो तो बता दें ।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है कि ये जो डिमांडज हैं ये 31 मार्च, 1976 तक के खर्चे के लिये हैं लेकिन मैंबर साहब जो बात कर रहे हैं यह अगरने साल के लिये कर रहे हैं । अगले साल के लिये इन्होंने बात करनी थी तो बजट पर जनरल डिस्कशन के समय कहते । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो बोल रहे हैं क्या वह रैलेवेंट है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

चौधरी शिव राम वर्मा : मुझे रोहतक यूनिवर्सिटी के बारे. कोई एतराज नहीं है वह बननी चाहिए । मैं तो अपनी बात शिक्षा मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि 56 लड़की ने इम्तहान दिया और केवल एक पास हुआ । तो इस साल भी अगर यही परिणाम रहा तो क्या होगा यह आप देख लीजिये । मास्टरों को आपने इतना बेचौन कर दिया है कि जो पढ़ाने वाले थे वे भी रगडे गये । जो निकम्मा आदमी है उसको सजा दीजिये जो काम करने वाला है आपने तो उसको भी बीस मील से परे ट्रांसफर कर

दिया था । जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उन को हौसला दिया जाए, इन्सैंटिव दिया जाए और जो निकम्मे हैं उन को सजा दी जाए । सब को एक लाठी से हांकना समझदार आदमी का काम नहीं होता । जैसा आदमी होगा उसके साथ वैसा ही बर्ताव करें मैं शिक्षा मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर विशेष ध्यान दें ।

अब मैं सोशल वैल्फेयर और रीहैबिलिटेशन के बारे अर्ज करना चाहता हूं । सोशल वैल्फेयर के अन्दर हरिजनों को, बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को प्लाट्स दिए गए प्लाटों की संख्या लाखों की तादाद में बताई गई । ये प्लाट्स तब काम आएंगे जब सरकार उन को प्लाट पर मकान बनाने में सहयोग देगी, सहारा देगी । मकान बनाना उन के बस की बात नहीं है । अगर सरकार उनके साथ सहयोग नहीं करेगी, मकान बनाने में सहारा नहीं देगी तोये प्लाट्स बेकार पड़े रहेंगे । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस काम के लिए उन गरीब लोगों को बिना जमानत और बिना ब्याज के कर्जा दें, और ग्रांट भी दी जाए । अगर कर्जा ही दिया गया तो उन को उतारना मुश्किल हो जाएगा । उनके मस्तिष्क में कर्ज का बोझ सवार रहेगा और उनको बसना मुश्किल हो जाएगा ।

इसके बाद इरीगेशन डिपार्टमैंट की बात आती है । इरीगेशन बहुत आवश्यक चीज है इसके बिना कोई काम चरनने वाला नहीं है । इरीगेशन के बारे में मैंने एक दिन आंकड़े दिए थे उन मेरे आंकड़ों को मुख्य मन्त्री महोदय झुठला नहीं सके ।

क्योंकि वे आंकड़े सरकारी किताबों में से निकाल कर दिए गए थे सरकार जो गिरवा दिखाती है कि इतना एरिया इरीगेट हो गया, वास्तव में इतना होता नहीं है, कम होता है । यह इस तरह दिखाते हैं कि जैसे सावनी की फसल बोई गई, चुंकि वह नहरी है, उस में नहरी पानी लगता है इसलिए उसको इरीगेटिड एरिया दिखा दिया । अगली बार उस प्रिया में चने की फसल बोर्ड गई और अधिकारीगणों ने उर्स को नहरी जमीन दिखा दिया । वह नहरी जमीन गिन ली जाती है । इसी तरह अगर उस में गेहूं बो दी जाए और उसको एक आध पानी मिल गया तो उसको भी नहरी गिन लिया जाता है । इम तरह बढ़ा चढ़ा कर बताने से कोई फायदा नहीं है । इरीगेशन को सही मायनों में बढ़ाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए इधर उधर से आंकड़े जोड़ कइर बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए तो देश की पैदावार सही मायनों में नहीं बढ़ सकती । म्उख्य मन्त्री महोदय ने पैदावार की जो बढ़ौतरी बताई. है, बहु इन की किताबों में क्यों नहीं दिखाई गई? किताबों में क्यों बढ़ौतरी नहीं दिखाई? मैंनै कहा था कि अगर किताबों में. –लिख देते तो हम भी पढ लेते लेकिन बढ़ोतरी है ही नहीं । पर–हैक्टेयर यील्ड बढ़ी ही नहीं । वैस्टर्न जमना कैनाल का जो एरिया है उसमें 30 से 53 परसैटं के करीब

चौधरी मेहर चन्द : आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर । क्या इस हाउस में गलत इन्फर्मेशन दी जा सकती है? ये ग्रौस

एरिया की बात करते हैं । जहां ग्रौस एरिया लिखा है वहां नैट एरिया भी लिखा है, वह भी पढ़ लो कि कितना इरीगेट हुआ है?

चौधरी शिव राम वर्मा : मैं तो यह कहूंगा कि जब तक इरीगेशन नहीं बढ़ेगी तब तक देश की पैदावार आगे नहीं बढ़ सकती । मैं वैस्टर्न जमना कैनाल के बारे में चर्चा कर रहा था । वहां 30 परसैटं जमीन को पानी लगता था । अब पता नहीं शायद 35 परसैटं हो गया होगा लेकिन वास्तविक तौर पर पानी बढ़ा नहीं है क्योंकि मेरा गांव नहर के साथ है वहां भी नहर का पानी लगता है । जितना रकबा पहले भरता था अब उसका तिहाई या चौथाई भरता है? पानी कम मिलता है और प्रचार ज्यादा करते हैं । प्रचार चाहे कितना हो, इससे वास्तविकता नहीं बदल सकती । सरकार इस ओर ध्यान दे, जितनी अश्योरेंस दी जाती है उसके मुताबिक उस रकबे को पानी मिलना चाहिए क्योंकि लैड सीलिंग भी इसी बिना पर की जाएगी । अश्योर्ड इरोगेटिड एरिया वह होगा जहां नहरी पानी लगता होगा, जिसमें सिंचाई के साधन पूर्ण रूप से हों । जिस इलाके में बारिश न हो और नहर का पानी भी पूरा न हो तो वहां पांच मन दाने भी नहीं हो सकते । इसलिए सही मायनों में अश्योर्ड इरी– गेटिड एरिया वही होगा जहां यदि बारिश न भी हो और फिर दोनों फसलें ठीक तरह से पूरी लग जाएं, तब हम समझेगे कि अश्योर्ड इरीगेटिड एरिया है । इस ओर ध्यान देना आवश्यक है कि अश्योर्ड इरीगेटिड एरिया वह होगा जिसमें दोनों फसलें, बिना बारिश से भी पके, उसी को अश्योर्ड इरीगेटिड एरिया

मानेंगे, दूसरे को नहीं, अगर 30 परसैटं का चकमा दे दिया गया और पूरा पानी मिला ही नहीं तो उसका फायदा क्या हुआ । जितना पानी चकबंदी में लिखा है उतना तो मिलना ही चाहिए, चाहे बारिश हो या न हो । इसके साथ ही साथ, डेरनेज के बारे में डिमांड है, यह भी इरीगेशन के अन्दर ही आती है । लिंक ड्रेन्ज शीघ्रता से पूरी होनी चाहिएं, क्योंकि उन के बिना छोटे छोटे रकबे खराब हो जाते हैं जब बारिश ज्यादा हो जाए तो फालतू पानी 'का निकास शीघ्रता से हो ।

अब मैं एग्रीकल्चर के बारे में कहना चाहूंगा । एग्रीकल्चर की कई बातें हाउस में आई हैं जिन में से एक विशेष बात यह है कि जमीदारों को बीज तसल्लीबख्श नहीं मिलता इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । जमींदार को कई फसलें पैदा करनी पडती हैं कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पैसा ज्यादा खर्च करना पडता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट किसान का ध्यान रखे। कई बार हम कुछ कहते हैं, लोग कुछ कहते हैं और सरकार यह कहती है कि किसानों को बड़ा प्रौफिट हो गया है लेकिन मैं कहता हूं कि पिछले दो सालों से किसान लगातार घाटे में जा रहा है क्योंकि जिन चीजों की किसान को आवश्यकता होती है उन के भाव उछाल खा गए हैं । यह एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट का काम है कि सरकार के नोटिस मे लाए कि किसान की पोजीशन क्या है । किसान को आवश्यक चीजें, इनपुट्स वगैरा ठीक समय पर और ठीक भाव पर मिलने चाहिए । बीज किसान के लिए

आवश्यक चीज है । जिस भाव पर किसान को 'पड़ता' खाए उस भाव पर मिलना चाहिए और एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट किसान को अच्छे से अच्छा बीज दे और अच्छी से अच्छी गाइडैसं दे और इनपुट्स ठीक भाव पर दे ताकि किसान की हालत बेहतर हो सके । इसके साथ ही साथ हम देखते हैंकि फसलों में कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं । लोग कहते हैं कि फलां बीमारी लग गई है । हमने किसी को कहा कि भाई, जो इन्स्पैक्टर है उसेको बताओ । उसने कहा कि बताया था और दवाई भी छिडकवाई थी । पौधे भी दिखाए थे लेकिन लाभ नहीं हुआ । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दवाई छिडकवाने का इन्तजाम ठीक ढंग से होना चाहिए ताकि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मर सकें । इस साल सरसों और तोरिया की फसल बिल्कुल खत्म हो गई कृ षि विभाग के सभी सप्रेयर बिगड़े पड़े थे । (घंटी) मैं जल्दी ही खत्म करने वाला हू । इस तरफ सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए । अगर ' पैदावार नहीं बढ़ेगी तो हरियाणा प्रान्त की बढ़ौतरी नहीं हो सकती, विशेषकर खेती हरियाणा का आधार है, इस तरफ सरकार का पूरा ध्यान होना चाहिए । बिजली का भी पूरा प्रबन्ध होना चाहिए । कई बार बिजली देर से मिलती है, और बीच में कई बार इन्ट्रप्शन्ज हो जाती हैं, लोग बिजली के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, उनके आने जाने में टाईम खर्च होता है । कई बार वोल्टेज कम चलती है । करनाल के आस पास तो ऐसी तकलीफें बहुत बढ रही हैं । शाम और सुबह के वक्त बिजली घरों में लाईट के लिए भी नहीं मिलती, जब बच्चों के पढ्ने का

समय दोनों वक्त होता है । सवेरे पांच बजे बिजली अधिकतर भागती है, कभी ही 6– 7 बजे तक रहती है । (विघ्न) इसलिए मेहरबानी करके बिजली सप्लाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । इसके बिना न खेती का काम और न लोगों के विकास के दूसरे काम चलेंगे ।

स्पीकर साहब, ऐनीमल हसबैन्डरी के बारे में भी मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं । मेरी प्रार्थना यह है कि जहां–जहां दूध पैदा करने वाले इलाके हैं उनका सर्वे किया जाए । जहां लोग पशु पालते हैं, जहां दूध ज्यादा पैदा हो सकता है, वहां थोड़ा सा सरकार का सहयोग मिलने से दूध की और बढ़ोतरी हो सकती है । नीलोखेडी का इलाका भी ऐसा है । वहां सर्वे करके दूध की पैदावार बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए और उसके आस पास नीलोखेडी में या करनाल में दूध का संयंत्र लगाया जाए ताकि लोग ज्यादा दूध पैदा करें, उसकी खपत ज्यादा हो सके । और उनकी माली हालत भी सुधर सके । बिना जमीन का आदमी भी इससे अपना गुजारा कर सकता है अगर उसे दूध का ठीक दाम मिलने का आश्वासन मिल जाए, बैक से समय पर सहायता मिल जाए और एक भैस के दूध से भागने पर दूसरी भैस का भी प्रबन्ध हो जाए । यदि यूक भैस के दूध से भागने पर दूसरी भैस आपने नहीं दी तो पिछले पैसे भी आपके रूक जाएंगे क्योंकि कोई रोजगार उसके पास होगा नही । इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

स्पीकर साहब, आखिर में एक बात मैं इंडस्ट्रीज के बारे में कहना चाहता हूं । इंडस्ट्रीज की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए । काटेज इंडष्ट्रीज जो हैं, घरेलू धन्धे जो हैं, उनकी ओर जब तक सरकार का ध्यान नहीं जाएगा बड़े उद्योगों से समानता नहीं आएगी, लोग बेकार फिरेंगे । जिस फैक्टरी में एक हजार मुलाजिम काम करते हैं वहां बड़ी–बड़ी मशीनें लगने से केवल 20– 30 आदमी ही काम कर लेते हैं । इससे बेरोजगारी बहुत बढती है । इसलिए छोटे छोटे कारखाने चलाने के लिए सरकार को योजना बनानी चाहिए और योजना बनाकर उसको गांव में चालू करना चाहिए । इसके बिना देश की समस्यायें हल नहीं होंगी ।

स्पीकर साहब, कहना तो मैं और भी चाहता था लेकिन क्योंकि आपकी घंटी बज ली है इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हु और सरकार से आपके द्वारा प्रार्थना करहा हूं कि वह इस ओर विशेष ध्यान दे ताकि हरियाणा के लोगों की समस्याओं का पूरा और सही –हूल हो । धन्यवाद ।

श्री मंशा राम (नौलथा) : स्पीकर साहब, हरियाणा के अन्दर इतनी तरक्की हो रही है कि कही जाकर देख लो चार चांद हरियाणा में लगे हुए हैं । हरियाणा मैंने उस टाईम भी देखा जब हैदराबाद में कांग्रेस सैशन हो रहा था । वहां जितने भी डैलीगेट्स गए थे एक धर्मशाला में ठहरे थे । हमारे मुख्य मन्त्री भी हमारे साथ थे । हुक गाड़ी हमें लेने आती थी लोग मजाक

किया करते थे कि ये आया राम और गया राम के प्रदेश से आए हैं । मैंनै आज का हरियाणा भी देखा जब मैं पंजाब का सैशन देखने गया । एक कामरेड ने जब हरियाणा ट्रांसपोर्ट की प्रशंसा की तो खुशी कें मारे मैं इतना फूल गया कि मेरे कोट के बटन भी टूट गये । यह कोई तारीफ की ही बात नहीं है । असल में बहुत अच्छी तरक्की हुई है । मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि मैँने जब अपना इलैक्शन लड़ा तो मुझे कहीं कार से नहीं उतरना पड़ा, यह बात दूसरी है कि छोटे मोटे झगड़ों की वजह से कुछ एक टुकड़े कहीं कहीं पड़े हों ।

स्पीकर साहब, मैं अपने हल्के की कुछेक बातें आपकी मारफत सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं । कुछ दिन पहले पौ हलके में पिछले मुख्य मन्त्री चौधरी बंसी लाल जी गए थे । उनसे हुमने प्रार्थना की थी कि नम्बर 9 रजबाहे में से असराना जौन्दन के बीच से कारद, परदाना और शाहपुर माईनर्ज बननी बड़ी जरूरी हैं । इन गांवों का दस हजार एकड़ रकबा है । उसमें अपने गुप्ता जी ने भी सरकारी ट्यूबवैल लगाने वालों को वहां भेजा था लेकिन वे भी वहां नाकामयाब रहे। नम्बर 8 रजबाहे के बारे में भी मैं एक अर्ज करना चाहता हु । बलाना इसकी टेल है । बलाना से पलडी और माडी से धिमराडा माईनर्ज भी बननी चाहिए । इनका भी दस हजार एकड़ रकबा है । अगर ये बन जाए तो काफी एरिया की आबपाशी इनसे हे सकती हैं ।

स्पीकर साहब, मललौडा ब्लॉक एरिया में पानी खारी निकलता है । अपने टयूबवैल वहां कामयाब नहीं होते । इसलिए प्रार्थना है कि सरकारी ट्यूबवैल लगा कर वहां पानी दिया जारा । यह होना भी, स्पीकर साहब, बहुत जरूरी है ।

स्पीकर साहब, नौलथा हलके में बहुत ज्यादा ड्रेन्ज हैं । बिना खुदी होने के कारण चौमासे में उनमें बहुत ज्यादा पानी चढ़ जाता हए । मिसाल के तौर पर जैसे अटौला ड्रेन है । बिना खुदी होने के कारण उसमें पानी रूक जाता है । किसान को इससे बहुत' नुकसान होताहै । इसी तरह मांडो ड्रेन है । यह नई मन्जूर हुईहै । वह बाद और पुठर की तरफ नहीं जानी चाहिए । यह चमराडा मोडी की सोम को खोदकर ड्रेन नम्बर 8 में डाली जाए ।

स्पीकर साहब, मेरा बडा सादा सा हलका है । वहां नौलंथा में एक कालेज होना भी जरूरी है । शहर में जाए बिना ही बच्चे अगर वहां पढ़ जाएं तो बडी अच्छी यति होगी क्योंकि शहर में जाकर बच्चे बिगड़ जाते हैं ।

स्पीकर साहब, तीन चार गांव जैसे कायत, शाहपुर, बुआनालाखु और सराहना, ऐसे हैं जिनमें खारी पानी है । लोगों को बहुत इर से पानी लाना पड़ता है । एक टंकी का वहां होना बहुत जरूरी है ।

स्पीकर साहब, सरकार ने उरलाना कलां में एक मंडी मंजूर की थी । मती महोदय से मैं प्रार्थना करता हूं कि वह मंडी जल्दी से जल्दी बनाई जाए ।

स्पीकर साहब, नहर बुटाना ब्रांच पर घोड़ापुली है । वह टूटी है । उसको गाड़ी का पुल बनवाया जाए ।

एक हस्पताल के लिए अहर गांव में स्पीकर साहब, सात लाख रुपये मंजूर हैं । उसको पचास बैड का हस्पताल बनाया जाए, सरकार से मेरी यह प्रार्थना है । इन शब्दों के साथ, स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग (थानेसर) : स्पीकर साहब, वैसे तो मैं बजट के ऊपर बोल चुका हूं लेकिन चूंकि उस समय मैं अपने हलके की डिमांडज के बारे में नहीं कह सका इसलिए अब मैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान आपके द्वारा दिलाना चाहता हूं । सबसे पहले मैं डिमांड नम्बर तीन को लूंगा । लाडवा के अन्दर एक पुलिस स्टेशन है । इसकी बिल्डिंग बड़ी पुरानी है । वह किसी वक्त पुराना किला था । उसमें रिहायशी क्वाटर्ज भी हैं । लोग वहां बड़े तंग और परेशान हैं । जमीन सैक्शन चार में कई साल से आई हुई है लेकिन अमल में अभी तक कुछ नहीं आया । मैं आपकी मारफत सरकार से यह दरख्वास्त करता हूं कि उस पर अमल दरामद करके थाना जल्दी से जल्दी बनाया जाए । रिहायशी क्वाटर्ज और बैरेक्स भी वहां बनवाई जाएं ।

डिमांड नम्बर 8, स्पीकर साहब, सड्कों के बारे में है । इसमें कोई शक की बात नहीं कि सड़के हरियाणा में बहुत बनी हैं लेकिन इनमें गैप्स बहुत पड़े हैं । मैं आपसे क्या अर्ज करूं कि मेरे हलके में मैप्स ही गैप्स हैं । लाडवा से मुस्तफाबाद वाली सडक को ही ले लीजिए । इस सडक पर अभी कुछ दिन पहले चौधरी माडू सिंह जी ने कालेज की क्लासिज का इनआगुरेशन किया था, माननीय चौधरी बंसी लाल जी ने कालेज का फाउंडेशन स्टोन रखा था, और कालेज का नाम इंदिरा गांधी नेशनल कालेज है । आपको जानकर खुशी होगी कि अपने माननीय गवर्नर साहब ने तीस नवम्बर को बिल्डिग का इन–आगुरेशन किया था । लेकिन इस सड़क पर भी गैप है । पुल एक बनना है । वह अगर बन जाए तो जहां लोगों को, कालेज के विद्यार्थियों को फायदा पहुंचेगा वहां ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट को भी इतना फायदा पहुंचेगा जिसका कोई शुमार नहीं क्योंकि लाडवा से मुस्तफाबाद की ट्रैफिक चालू हो जाएगी । इसी नाम से यह सड़क मन्जूर है । इसी तरह से बवैन से अकालगढ की सड़क के मुताल्लिक आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गांवों वालों ने इस सड़क के लिए शेयर दिया हुआ है लेकिन अभी भी अधूरी पड़ी हुई है । इस सडक के अन्दर गैप है जिसकी वजह से सारी सड़क बेकार है । लाडवा पिपली से गाढली सड़क, लाडवा पिपली से मुमीयापुर, मैदाना से बगरट, पहलादपुर से जलाउदीन माजरा, लाडवा से. सम्भालखा इन सड्कों को भी बनाना बहुत ही जरूरी है । आपको यह बात सुनकर ताज्जुब होगा कि लाडवा से हनौरी वाली सड़क बहिन प्रसन्नी देवी

जी के हलके में भी जाती है । उस सड़क का शेयर एक लाख से ऊपर रुपया लोगों ने भी दाखिल किया हुआ है । यह सड़क अब भी अधूरी पड़ी हुई है । यह खादर का एरिया है । इस सड़क को कभी चालू कर देते हैं और कभी बन्द कर दिया जाता है । मेरी आपसे दरखास्त है कि इसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाये । लाडवा से बपदा, लाडवा हनौरी रोड से बपदी, लाडवा से रायपुर वाया पडोत सलीम पुर वाया रायतखाना, त्नाडवा से भूत माजरा, जीन्द हैडा से छलौन्दी आदि सड़कों को भी बनाया जाना बहुत जरूरी है ।

आपको यह जानकर ताज्जूब होगा कि भिवानी खेड़ा से लूखी का अभी तक पुल नहीं बना । पुल न बनने के कारण वह सडक बेकार होती जा रही छउ । अगर वहां पर पुल बना दिया जाये तो वह बड़ी अच्छी सड़क चल सकती है । जोतिसर से इनदबडी वाली सड़क भी बननी बहुत ही जरूरी है । इसके न बनने से लोगों को काफी दिक्कत है । कुरुक्षेत्र से बखयाला वाली सड़क में गैप है इसको भी पूरा कर दिया जाये तो लोगों को आराम हो सकता है । इस गैप के होने से सड़क बेकार है ।

आपसे मैंने पहले भी अर्ज की है कि लाडवा मंडी बहुत बढ़िया मंडी बनी है । फौरन की जब कोई टीम आती है तो लाडवा मंडी को दिखाने के लिए ले जाते हैं । हिन्दुस्तान भर में लाडवा मंडी जैसी मंडी नहीं है लेकिन इसके साथ ही साथ वहां पर अरबन अस्टेट की भी आवश्यकता है । जब तक वहां पर

अरबन अस्टेट की कालोनी नहीं बनेगी तब तक लोगों को काफी परेशानी और दिक्कत रहेगी । वहां के लोगों की बड़ी जबरदस्त डिमान्ड है । वहां पर सैक्शन चार के नोटिस इशू करा कर जमीन एक्वायर कर ली जाये । पहले एक बार नोटिस इशू कराकर जगह एक्वायर क्र लें, फिर अपने ढंग से जैसा भी ठीक समझें वैसा कर लें।

दूसरी डिमान्ड मेरी इरीगेशन के मुताल्लिक है । इरीगेशन और बिजली के बारे में जो काम हमारी गवर्नमैंट ने किया वह मेरे ख्याल में काफी सराहनीय काम है । हो सकता है कि इतना काम किसी भी प्रदेश में न हुआ हो । (चौधरी रिजक राम जी की ओर से विघ्न) चौधरी साहब आप तो जमना में पानी की बात करते हैं, मैं तो छोटी सी नहर की बात करना चाहता हूं । जो भी एक बार आई ० पी ० एम ० रह जाता है उसके दिमाग से नहरें नहीं निकलती हें । मेरे दिमाग में तो एक छोटी सी नदी की योजना है । स्पीकर साहब राक्षसी, चतंग दो बरसाती नदियां हैं । अगर इन नदियों को रैपूलर कर दिया जाये तो फिर फ्लड के टाईम पर उन नदियों का पानी हमारे इलाके को दे दिया जाये । फ्लड के टाईम पर उन नदियों को हमारे इलाके को बड़ा लाभ होता है । हमारे इलाके को बड़ा शैराब करती है । जब वे ओवर फलो होती हैं तो पैडी को बड़ा फायदा पहुंचाती हैं । हमारे यहां इस नदी का पाना आने से इस साल भी बडी अच्छी पैडी हुई है । जब यह नदी ओवर फलों होती है तो इसके पानी को जमना में

डालते हैं– । अगर यह रैगूलर ढंग से चलें तो पानी ओवर फलों हो कर खेतों में जाये तो उससे पैडी अच्छी हो सकती है ।

तीसरी चीज इन्डस्ट्री के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज लग रही हैं । बहुत सी जगहों पर लग रही है । फरीदाबाद और पानीपत में लग रही हैं । आप जानते हे कि जहां पर भी इन्डस्ट्रीज लग गई वहां पर लेबर क्लास और मिडल क्लास की हालत सुधर जाती है । मैं सरकार से आपकी मार्फत दरखास्त करना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र और पिपली को भी इस के लिये कन्सिडर किया जाये । कुरूक्षेत्र और पीपली ऐसी जगह हैं, जब पिपली के अन्दर ट्ररिस्ट उतरते हैं तो वे कुरुक्षेत्र को देखने के लिए जाते हैं । जहां वे धार्मिक स्थान को देखने के लिए जाते हैं तो उनको वहां अच्छी इन्डस्ट्री भी देखने को मिले तो और भी अच्छा रहेगा । वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा ।

मैं थोड़ा सा डिमान्ड नम्बर 18 के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि कितने ही मिल्क–प्लांट लग गये हैं मगर मेरे इलाके में कोई मिल्क प्लांट नहीं है । मेरा सरकार से इस बारे में गिला है कि जब और इलाकों में डेरीज का इस तरह से विस्तार किया जा रहा है तो पिपली या लाडवा में मिल्क प्लांट लगाया जाना चाहिए । ऐसा करने से लोगों को रोजगार मिल सकता है । गरीब लोगों को रोजगार के लिये यह सब से बड़ा साधन हो सकता है।

एक मैम्बर : मिल्क प्लांट लगने के बाद तो छाछ भी नहीं मिलती है।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : मैं तो स्पीकर साहब अर्ज कर रहा था कि जिस तरीके से विस्तार हो रहा है और योजनाये बनायी जा रही हैं तो लाडवा में जरूर मिल्क प्लांट बनना चाहिए । लाडवा का जो दूध है वह यमुना नगर होते हुए. यू ० पी ० में जाता है । अगर यहां पर मिल्क प्लांट लगा दिया जाये तो इस सारे इलाके के लोगों को सहूलियत हो जायेगी । हमारे हरियाणा का दूध हरियाणा में ही रह जायेगा ।

मैं स्पीकर साहब ज्यादा समय न लेते हुए आपका धन्यवाद करता हूं और आपकी मार्फत फिर रिक्वैस्ट करता हूं कि जो मेरी डिमान्डज हैं वे सभी मुनासिब और उचित हैं । सरकार को इन पर गौर करना चाहिए और इनको पूरा करना चाहिए । यही मेरी अर्ज है । आपका धन्यवाद, आपने बोलने के लिए समय दिया ।

चौधरी प्रभु सिंह (छछरौली एस० सी०): स्पीकर साहब आपके जरिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूं कि वे हरेक बात को पूरी तसल्ली से कहते हैं और जो भी बात कहते हैं उसको पूरा करते हैं । इसलिए थोड़ी सी मेरे हलके की डिमान्डज हैं उनकी तरफ उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मेरे हलके में गन्ना बहुत ज्यादा होता है । जैसे कि और जगहों पर शूगर मिल

लगाये जा रहे हैं तो इसी प्रकार मेरे हलके में भी एक शूगर मिल लगाया जाये । शूगर मिल लग जाने से मेरे इलाके को बहुत फायदा पहुंचेगा और गन्ने का रेट भी अच्छा मिलेगा ।

सरकार ने वाटर सप्लाई सिस्टम चालू किया हए । वाटर सप्लाई स्कीम मेरे हलके में चालू नहीं हुई है । मेरा हलका एक बैकवर्ड हल्का है । मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि कई गांवों के लोग ऐसे हैं जो नहरों का पानी पीते हैं । जैसे हमारे यहां रेनवाड हैं वहां पर पानी की बड़ी दिक्कत है । मैं सरकार से दरखास्त करूंगा वहां पर वाटर सप्लाई स्कीम चालू की जाये ताकि उन लोगों को मीठा पानी मिल सके ।

स्पीकर साहब मैं आपके जरिए अपने एजूकेशन मिनिस्टर साहब का ध्यान भी अपने इलाके की तरफ दिलाना चाहता हूं । मेरे इलाके में खीजराबाद गर्ल्ज स्कूल है । उसकी बिल्डिंग बहुत पुरानी है । अब तो बिल्कुल छप्पर से ही काम चला रखा है । एक कच्चा सा कोठड़ा बना हुआ है । इसलिए मेरी दरखास्त है कि उसको पक्का बनाया जाये या हमारे यहां हास्पिटल की अब नयी बिल्डिंग बन गई है और वह दूसरी बिल्डिंग में चला गया है । वह बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है । उस खाली बिल्डिंग में उस गर्ल्ज स्कूल को शिफ्ट कर दिया जाये तो बच्चों की तकलीफ बच जायेगी । स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये सरकार का ध्यान गांव की एक समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं । मैंने अपनी आंखों से देखा है, पहले गांवों के अन्दर बहुत जोर से मलेरिया होता था

लेकिन सरकार ने मलेरिया की रोकथाम के लिये बहुत अच्छा इन्तजाम किया और अब मेरे ख्याल में मलेरिया बिल्कुल भी नहीं है । अगर वहां पर गन्दगी का ध्यान न रखा गया तो यह मलेरिया दोबारा भी हो सकता है । एक तो सरकार ने जो गांव के लिये एप्रोच रोड्ज दी हैं उन पर बडी गन्दगी होती एं और दूसरे वैसे भी गांव में गन्दगी रहती है, इससे मलेरिया का दोबारा होने का खतरा रहता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि गांव–गांव के अन्दर टट्टियां बनायी जायें ताकि गांव के लोगों को फायदा हो और सरकार को भी मलेरिया की रोकथाम फिर नहीं करनी पड़ेगी और सहूलियत होगी । स्पीकर साहब. मैं आपके जरिये सरकार से एक और दरखास्त करूंगा । जैसे सरकार गांव–गांव में डिपो दे रही हैं, इससे बहुत लाभ होगा । लेकिन मेरी अर्ज यह है कि जो गांव के लिये डिपो बनाये जाते हैं, इस बात में खास तौर पर हरिजनों का भी ध्यान रखा जाये । गांव–गांव में कपड़े वगैरा के, चीनी वगैरा के और खाद वगैरा के, डिपो जल्दी से जल्दी खोले जायें ताकि गरीब आदमियों को इससे राहत पहुंचे । स्पीकर साहब मैं आखिर में एक बात और कह दूं । जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया था, मेरा अपना गांव है वहां से 6 फर्लांग पर बस–अड्डा है । वहां तक जाने के लिये कोई सड़क नहीं मैं सरकार से यह कहूंगा कि गांव से वहां तक सड़क बना दी जाये ताकि लोगों कौ आने–जाने में दिक्कत न हो । आपने मुझे बोरनने के लिये टाईम दिया.. इसके लिये आपका धन्यवाद ।

वित्त मंत्री (श्री राम सरन चन्द मित्तल) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब सप्लीमेंट्री बजट पर माननीय शिव राम वर्मा जी की तरफ से बहस शुरू होने लगी तो आपने सदस्यों का इस ओर ध्यान दिलाया था कि इस सप्लीमेंट्री बजट के अन्दर या सप्लीमैंट्री ग्रान्ट्स में जो प्रोपोजल्ज हैं, उन्हीं पर बहस हो रही है न कि जनरल बजट पर बहस हो रही है । तो इससे मेरा काम यूं आसान हो गया कि दरअसल जो प्रोपोजल्ज इन सप्लीमैंट्री एस्टीमेटस में हैं, उनके ऊपर तो किसी ने खास नुक्ताचीनी की नहीं, जैसे गवर्नर्ज एडैरस पर या जनरल बजट पर डिमान्ड्ज रखीं, उसी तरह से इसमें भी अपने हलके की डिमान्ड्ज रखीं । उसके मुताल्लिक मैं पहले ही अर्ज कर चुका द्रूं कि सम्बन्धित विभाग इन तमाम डिमान्डज और जरूरियात पर पूरा–पूरा तौर करेंगे ।

इसके अलावा दो बातें मैं अर्ज कर देना चाहता हूं । एक बात तो मैं एग्रीकल्चर के बारे में कह देना चाहता हूं कि दरअसल फसल का इतना ध्यान दिया जाता है कि सरसों या कुछ और चीजों पर जब बीमारी पैदा हो गयी थी तो हमने मेवात में उस के ऊपर एरियल स्प्रे करवाया और उस पर 8 लाख रुपया खर्च किया गया । इस तरह से एग्रीकल्चर पर सरकार पूरा–पूरा ध्यान दे रही है ।

लाला गौरी शंकर ने यह कहा था कि बाजरे का बीज ठीक नहीं है । उनकी यह बात बिल्कुल ठीक है कि बाजरे का बीज जो दक्षिण से आया है, वह बिल्कुल ठीक नहीं था । वह

हमने बन्द कर दिया है और आइन्दा अच्छा बीज, चाहे यूनिवर्सिटी से लें या कहीं और से लें, लिया जायेगा । मैं समझता हूं कि मुझे इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही सब अर्ज कर दिया है । इसलिये अब इन डिमान्डज को पास किया जाये ।

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,45,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 1—Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10,43,022 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 2—General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,59,29,670 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 3—Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 45,43,880 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 4—Revenue.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,97,10,910 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 6—Finance.

The motion was carried .

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 89,87,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 8—Buildings and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,22,29,147 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No.9— Education.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 14,27,900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No .11-Urban Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,81,450 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No 12—Labour and

Employment.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 52,89,450 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 13—Social Welfare and Rehabilitation.

The motion was carried.

Mr Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10,66,88.430 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 15—Irrigation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 16—Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,59,77,760 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 17— Agriculture .

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 18—Animal Husbandry.

The motion was carried.

Mr Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7,28,430 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 20—Forest

That a supplementary sum not exceeding Rs. 26,10,380 be granted to the Governor to defray the chargse that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 21—Community Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 6,47,830 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No.22— Cooperation.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 8,80,760 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 24—Tourism.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 9,53,85,410 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1976 in respect of Demand No. 25—Loans and Advances by State Government.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 2.00 p.m. on Tuesday, the 27th January, 1976.

12.57 बजे

(The Sabha then* adjourned till 2.00 p.m. on Tuesday, the 27th January. 1976.)